चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 15 नवंबर–21 नवंबर 2010

मूल्य 5 रुपये

इतिहास विकास से बनता है, पत्थर लगाने से नहीं : अखिलेश

पेज-3

अमन की राह पर एक सार्थक पहल

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

टू द प्वाइंट : क्रिकेट के असली खेल की खुली किताब

पेज-15

बिहार में

राहुल फेल हो गए

मनीष कुमार

एक कहानी है. एक गांव में दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा चल रहा था. दोनों एक-दूसरे को तबाह करने में दिन-रात लगे रहते थे. उनमें से एक को अचानक एक आइडिया आया. उसने अपनी एक आंख फोड़वा ली. हर दिन वह सुबह-सुबह अपने विरोधी के सामने खड़ा हो जाया करता था. जिसने अपनी आंख फोड़वा ली, उसे यह आइडिया आया कि क्यों दिन भर पड़ोसी के पीछे लगे रहें, इससे अच्छा तो यह है कि एक आंख फोड़ लो और सुबह-सुबह उसके सामने चले जाओ. काने को देखने से दिन वैसे ही ख़राब हो जाएगा. कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव में यही काम किया है. लालू यादव को सबक सिखाने की जिद ने कांग्रेस पार्टी को अंधा बना दिया. पार्टी ने बिहार में ऐसी रणनीति बनाई, जिससे पूरा विपक्ष ही खंड-खंड हो गया.

सवाल यह है कि राहुल ने बिहार में ऐसी रणनीति क्यों अपनाई. दरअसल राहुल गांधी के लिए बिहार चुनाव एक प्रयोगशाला है, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है, युवाओं का सर्वमान्य नेता बनना है. इसी मायने में बिहार चुनाव राहुल गांधी का इम्तहान है. बिहार के चुनाव में यह भी फ़ैसला होना है कि राहुल गांधी का करिश्मा चुनाव पर असर डालता है या नहीं? राहुल गांधी में संगठन का पुनर्निर्माण करने की काबिलियत है या नहीं? बीस साल पहले कांग्रेस बिहार की सबसे मजबूत और ताक़तवर पार्टी हुआ करती थी. राहुल क्या कांग्रेस पार्टी के पुराने दिन लौटा पाएंगे? राहुल गांधी और उनके सलाहकारों के लिए यही चुनौती है. राहुल गांधी ने मुसलमानों और युवाओं के ज़रिए इस काम को अंजाम देने की कोशिश की है. ऐसा ही कुछ राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में करना है. अगर बिहार का प्रयोग सफल रहता है तो राहुल गांधी के लिए पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ़ हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गए. राहुल गांधी नौजवानों को राजनीति में सामने लाने की बात करते हैं. भारत के युवाओं का सर्वमान्य नेता बनना उनका सपना है. बिहार चुनाव उनके लिए एक मौक़ा था, जब वह ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उम्मीदवार बना सकते थे. अगर राहुल गांधी बिहार में 25-40 वर्ष की आयु के 60 फीसदी उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने में कामयाब होते तो यह माना जा सकता था कि राहुल गांधी जो कहते हैं, वही करते हैं, लेकिन बिहार चुनाव में वह एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से दस से ज़्यादा उम्मीदवारों को टिकट नहीं दे सके.

इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं से समर्थन तो चाहती है, लेकिन उनके हाथ नेतृत्व देना नहीं चाहती.

कांग्रेस की योजना बिहार में असफल होती दिखाई दे रही है. चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अनिल शर्मा थे. उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में बड़ा योगदान किया. जो काम लालू यादव और रामविलास पासवान नहीं कर सके, वह काम अनिल शर्मा ने किया. उन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाया. पूरे राज्य का दौरा कर पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, लेकिन पार्टी ने उन्हें बेइज़्ज़त करके अध्यक्ष पद से हटा दिया. दरअसल, राहुल गांधी के सलाहकार पिछले छह महीने से बिहार में हर तरह के प्रयोग को अंजाम देने में लगे थे. राहुल गांधी कहां जाएंगे, कहां प्रेस कांफ्रेंस करेंगे, कैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा, किन्हें संगठन की ज़िम्मेदारी दी जाएगी आदि सब कुछ उनके सलाहकार राहुल गांधी के नेतृत्व के नाम पर कर रहे थे. राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी.

बिहार चुनाव अपने आख़िरी चरण में है. इस चुनाव की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि हर पार्टी ने अपने-अपने हिसाब से जनता को मूर्ख बनाने के हर दांव खेले. कांग्रेस पार्टी इस खेल में सबसे आगे रही. अब चुनाव के नतीजे ही यह बताएंगे कि जनता इनके झांसे में आई या नहीं. अफ़सोस की बात यह है कि बिहार चुनाव के दौरान जनता की समस्याएं और उनसे जुड़े सवाल चुनाव का मुद्दा नहीं बन सके. विपक्ष ने और भी निराश किया. सरकार की कमियों को मुद्दा बनाने के बजाय सबने नीतीश कुमार को ही निशाने पर ले लिया. विपक्षी दलों की कृपा से नीतीश कुमार चुनाव के केंद्र में आ गए. यही नीतीश कुमार की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है.

इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की. कांग्रेस ने इस चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया. बिहार कांग्रेस के एक सचिव सागर रायका और पार्टी की यूथ विंग के अध्यक्ष ललन कुमार को पुलिस ने साढ़े छह लाख रुपये के साथ गिरफ़्तार किया. इन पर सोनिया गांधी की रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे बांटने का आरोप है. सोनिया गांधी की रैली में शामिल होने के लिए पैसे बांटने के आरोप में कांग्रेस के छह अन्य कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए. पार्टी ने ख़ुद को एनडीए को चुनौती देने वाली मुख्य पार्टी बनाने में साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगा दिया. राहुल गांधी ने अपनी सारी ताक़त झोंक दी. उनकी रैलियों में लोग तो आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को चुनौती देने में नाकाम रही.

शुरुआत से ही बिहार चुनाव में कांग्रेस की वजह से काफी कन्फ्यूजन फैला. राहुल गांधी के सलाहकारों ने उन्हें यह समझा दिया कि नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छा काम किया है. उनकी तारीफ़ करने से राहुल गांधी को लोग सच बोलने वाला नेता समझेंगे. इसके बाद वह जो भी बोलेंगे, लोग उनकी बातों पर विश्वास करेंगे. राहुल बिहार गए और उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार बिहार का विकास कर रहे हैं. जिसका अर्थ यह निकला कि नीतीश कुमार से पहले लालू यादव की जो सरकार

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सवाल यह है कि राहुल ने बिहार में ऐसी रणनीति क्यों अपनाई. दरअसल राहुल गांधी के लिए बिहार चुनाव एक प्रयोगशाला है, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है, युवाओं का सर्वमान्य नेता बनना है. इसी मायने में बिहार चुनाव राहुल गांधी का इम्तहान है. बिहार के चुनाव में यह भी फ़ैसला होना है कि राहुल गांधी का करिश्मा चुनाव पर असर डालता है या नहीं? राहुल गांधी में संगठन का पुनर्निर्माण करने की क़ाबिलियत है या नहीं? बीस साल पहले कांग्रेस बिहार की सबसे मज़बूत और ताक़तवर पार्टी हुआ करती थी.

सेवानिवृत्त अधिकारियों को इस तरह नियुक्त करने की यह परंपरा नई नहीं है, लेकिन हर कोई इससे ख़ुश नहीं है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

ऐसे कैसे होगी जांच

कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर भले आश्वस्त हों कि राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार की एक साथ कई एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच से मामला और उलझ कर नहीं रह जाएगा, लेकिन इसके संकेत अभी से देखने को मिल रहे हैं. ख़बरों के मुताबिक़, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई आयकर अधिकारियों से इसलिए ख़फ़ा हैं कि उन्होंने अन्य जांच एजेंसियों को विश्वास में लिए बगैर आरोपी अधिकारियों के घरों और कार्यालयों में देश भर में छापे मारे. इन दोनों एजेंसियों ने अपनी नाख़ुशी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दी है. फ़िलहाल यही लग रहा है कि सभी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपने-अपने जांच कार्यों का संचालन कर रही हैं. हालांकि चंद्रशेखर संतुष्ट हैं और उनका यही मानना है कि सीबीआई और प्रवर्तननिदेशालय जैसी एजेंसियां एक-दूसरे के कार्यक्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं करेंगी, लेकिन ताजा संकेतों को देखकर यही लगता है कि मामला इतना सीधा नहीं है, जितना बताया जा रहा है.

कभी नहीं से देर भली

मई महीने में मंगलोर में हुए विमान हादसे और विमान यात्रियों की तेजी से बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार की देर से ही सही, लेकिन आंखें खुलती नज़र आ रही हैं. उसने एक स्वायत्त नागरिक विमानन प्राधिकरण (सीएए) के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने का फ़ैसला किया है. सीएए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की जगह लेगा, जो बढ़े कार्यभार को वहन करने में बार-बार अक्षम साबित होता रहा है. डीजीसीए नागरिक विमानन मंत्रालय के अधीन काम करता है और सीमित स्वायत्तता के चलते इसकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, लेकिन इसके मौजूदा अध्यक्ष नसीम जैदी का मानना है कि नए प्राधिकरण के गठन से निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी. उधर अंदर की जानकारी यह है कि नए संस्थान के गठन के लिए अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का दबाव है, जिसने इंग्लैंड और अमेरिका की तर्ज पर एक प्राधिकरण के गठन की अनुशंसा की है. रोचक तथ्य यह है कि सीएए की बागडोर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बजाय किसी ऐसे शख्स के हाथों में हो सकती है, जो नागरिक विमानन मामलों का विशेषज्ञ हो. अब यदि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दबी ज़ुबान से इसका विरोध कर रहे हों तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए.

नौकरशाहों के लिए रिटायरमेंट स्कीम

यूपीए सरकार सेवानिवृत्त होने वाले नौकरशाहों को खाली नहीं बैठने देना चाहती, खासकर उन अधिकारियों को, जिनकी सियासी गलियारों में अच्छी पहुंच है. हाल के दिनों में कई ऐसे अधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है. ऐसे नौकरशाहों में शीला भिड़े और ए के रथ शामिल हैं, जिन्हें कोल इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. इसी तरह वित्तीय सेवाओं के पूर्व सचिव अरुण रामनाथन को शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया में भेजे जाने का फ़ैसला लेने की सूचना है. हालांकि सेवानिवृत्त अधिकारियों को इस तरह नियुक्त करने की यह परंपरा नई नहीं है, लेकिन हर कोई इससे ख़ुश नहीं है. योजना आयोग भी कई बार इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है. आयोग का मानना है कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार किसी स्वायत्तशासी संस्था के हाथों में होना चाहिए, लेकिन उसकी इस सलाह पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

dilipcherian@gmail.com

बिहार में राहुल फेल हो गए

पृष्ठ 1 का शेष

थी, उसने विकास का काम नहीं किया. राहुल गांधी ने एक ही झटके में विपक्ष को कमज़ोर कर दिया. राहुल गांधी के ऐसे बयानों से लालू यादव और रामविलास पासवान का नाराज़ होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस बयान से वे दोनों बैकफुट पर आ गए. इसके बाद ख़बर यह भी आई कि कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार की तरफ़ दोस्ती का हाथ बढ़ाया. यह संदेश दिया गया कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी नीतीश की सरकार को समर्थन दे सकती है. नीतीश कुमार ने राहुल के बयान के बदले उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई भी तालमेल करने से सार्वजनिक तौर पर मना कर दिया. फिर कांग्रेस ने लालू यादव और रामविलास पासवान के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की. कांग्रेस की तरफ़ से यह बात फैलाई गई कि चुनाव परिणामों के बाद यदि बिहार में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति सामने आती है तो कांग्रेस लालू यादव की जगह रामविलास पासवान को समर्थन देगी. पहले राहुल गांधी ने नीतीश की तारीफ़ की, फिर चुनाव प्रचार के दौरान उन पर केंद्र की योजनाओं को सही ढंग से लागू न करने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने बीच-बीच में गठबंधन और रणनीति को लेकर अफवाह फैलाई. राहुल गांधी के सलाहकार शायद बिहार से वाक़िफ़ नहीं हैं और शायद इसलिए ऐसी ग़लती हो गई. बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर काफी परिपक्व है, वह नेताओं के बहकावे में नहीं फंसती. बयानबाज़ी का असर बिहार की जनता पर नहीं होता. यही वजह है कि कांग्रेस का चुनावी अभियान बिहार में मज़ाक बन गया.

कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगने के लिए एक मुस्लिम नेता को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया. क्या कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि सिर्फ़ अध्यक्ष बना देने से मुसलमान उनके पास वापस आ जाएंगे, उनका वोट मिल जाएगा? मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने जो कलाबाज़ी की है, उसका इतिहास तो अनंत है. क्या कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई किए बिना मुसलमानों को धोख़ा दिया जा सकता है? कांग्रेस पार्टी जो कहती है और जो करती है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ होता है. लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने ही बयान को भूल गए हैं. मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद यह कहकर राजनीतिक गलियारों में शाबाशी बटोरी थी कि सरकारी संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का ज़्यादा हक़ है. यूपीए की सरकार बने अब सात साल होने वाले हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के विकास से जुड़ा एक भी क़ानून नहीं लाया गया है. चुनाव से ठीक पहले बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला आ गया. इस फ़ैसले पर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की चुप्पी ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर कर दिया. कांग्रेस ने बिहार में 48 मुसलमानों को मैदान में उतार दिया. कांग्रेस की इस बात के लिए तारीफ़ होनी चाहिए कि इसने इतने ज़्यादा मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिए, लेकिन समझने की बात यह है कि क्या इन उम्मीदवारों को इसलिए टिकट दिया गया कि ये जीतने वाले उम्मीदवार हैं. या फिर लालू यादव का नुक़सान करने के लिहाज़ से यह रणनीति बनाई गई है. चुनाव परिणाम से यह साबित हो जाएगा कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को टिकट देने के फ़ैसले से किसे नुक़सान हुआ और इसका फ़ायदा किसे हुआ.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

कांग्रेस पार्टी ने बिहार में जो काम किया, वही काम वह पश्चिम बंगाल में भी दोहराने की तैयारी में है. उससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ़ ममता बनर्जी ही हैं, जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार को हराने की ताक़त रखती हैं. लोकसभा, पंचायतों और नगरपालिकाओं में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत हुई है. राहुल गांधी ने जब यह कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं शर्तों पर तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी, जो सम्मानजनक हों. इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी को अगर उसके मन मुताबिक़ सीटें नहीं मिलीं तो वह बिहार की तरह अकेले चुनाव लड़ेगी. चुनाव त्रिकोणीय हो जाएगा और इसका फ़ायदा लेफ्ट फ्रंट को मिलेगा. अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पर यह आरोप लगना निश्चित है कि पार्टी पश्चिम बंगाल में बदलाव नहीं चाहती है.

बिहार चुनाव के संदर्भ में राहुल गांधी की राजनीति पर ग़ौर करना ज़रूरी है. मामला किसानों का हो या फिर उड़ीसा के नियमगिरि के आदिवासियों का, राहुल गांधी के नज़रिए और केंद्र सरकार की नीतियों में मतभेद है. राहुल गांधी ग़रीबों, किसानों और आदिवासियों के साथ नज़र आते हैं, लेकिन सरकार उनकी विचारधारा के विपरीत चल रही है. राहुल गांधी भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार इंडिया के साथ नज़र आती है. राहुल गांधी की कथनी और केंद्र सरकार की करनी में ज़मीन-आसमान का अंतर है. सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी बिहार की जनता को यह विश्वास दिला पाएंगे कि बुनियादी सवालों पर वह जो कह रहे हैं, सही है? वह जिस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, वह सही है? वैसे राहुल गांधी की इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए कि जब वह आदिवासियों, मज़दूरों और ग़रीबों के मुद्दे पर बोलते हैं तो एक भावी प्रधानमंत्री नज़र आते हैं. उनके बयानों को सुनकर अच्छा भी लगता है, लेकिन डर भी लगता है. राहुल गांधी कुछ मुद्दों पर ऐसी राय रखते हैं, जिसका विरोध देश ही नहीं, बल्कि विदेशों की बड़ी-बड़ी शक्तियां करती हैं. देखना है कि राहुल गांधी के विचार, उनकी राजनीति सरकारी योजनाओं में कब तब्दील होती है.

बिहार चुनाव में जातीय समीकरण, अपराधियों और परिवारवाद का बोलबाला रहा. नेताओं ने जनता की समस्याओं के बजाय अपने निजी स्वार्थों पर ज़्यादा ध्यान दिया. नीतीश कुमार ने भी जनता को मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वह नरेंद्र मोदी का विरोध करने का भ्रम भी फैलाते रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी सलामत रहा. उन्होंने विकास के आंकड़ों की कलाबाज़ी दिखाई. सड़क बनाने को सुशासन का नाम देकर जनता को बेकारी, अशिक्षा और ग़रीबी जैसे मुद्दों से दूर रखने में वह कामयाब रहे. भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की बी टीम बनकर अपने धार्मिक और विवादित मुद्दों पर पर्दा डालकर लोगों को गुमराह किया. वामपंथी पार्टियों की दुविधा यह रही कि पार्टी दिल्ली के दफ्तर से बाहर ही नहीं निकली. बिहार में ग़रीबी, अशिक्षा एवं बेरोज़गारी जैसी समस्याएं हैं, लेकिन वामपंथी दलों ने भी निराश ही किया. जनता के लिए उन्होंने सड़क पर उतरने की ज़हमत नहीं उठाई. लालू यादव के खिलाफ़ सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि वह विकास विरोधी हैं. उनकी इसी छवि का नुकसान रामविलास पासवान को हो रहा है. मायावती ने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को खड़ा कर चुनाव को बहुकोणीय बना दिया. लालू यादव और रामविलास पासवान ने अगर ग़रीबों, दलितों, मज़दूरों, किसानों और मुसलमानों के विकास को मुद्दा बनाया होता तो चुनाव में बहस का मुद्दा ही अलग होता. कांग्रेस ने लालू यादव और रामविलास पासवान से हाथ न मिलाकर विपक्ष के वोटों का बंटवारा कर दिया.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 36
दिल्ली, 15 नवंबर-21 नवंबर 2010
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

इतिहास विकास से बनता है, पत्थर लगाने से नहीं : अखिलेश

समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के पुत्र एवं सांसद अखिलेश यादव से बात करें तो उनमें एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के उभरते व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मिलती है. युवा नेतृत्व के संकट से लेकर उत्तर प्रदेश से जुड़े कई अन्य राजनीतिक मसलों पर उनसे चौथी दुनिया के एडिटर इंवेस्टीगेशन *प्रभात रंजन दीन* ने एक लंबी बातचीत की. प्रस्तुत हैं मुख्य अंशः

उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा नेतृत्व का अकाल है, दो चेहरों को छोड़कर. इनमें एक चेहरा राहुल गांधी का है तो दूसरा अखिलेश यादव का. अन्य युवा चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की औपचारिकता भर हैं. राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सांसद ज़रूर हैं, लेकिन उनके बारे में पूरा देश जानता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश कितनी प्राथमिकता पर है. यह जो संकट है राज्य में युवा नेतृत्व का, इस खाई को कैसे पाटेगी आपकी पार्टी?

आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है. देखिए, जहां तक देश और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा नेतृत्व का मसला है तो कांग्रेस समेत सभी पार्टियां इस सवाल से रूबरू हैं. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस सवाल से उबरने की पूरी कोशिश कर रही है. सपा के तमाम युवा संगठनों ने यह प्रयास किया है कि नौजवान पार्टी के साथ खड़े हों. बहुत हद तक हम उसमें सफल भी रहे हैं. उसी का परिणाम है कि आज सबसे शानदार युवा संगठन सपा का है...संघर्ष में सपा ही आगे रही है युवाओं और नौजवानों को लेकर. जबसे मैं राजनीति में हूं, आज मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, लेकिन हमेशा युवाओं के साथ ही संघर्ष में रहा. नौजवानों के साथ ही लगातार काम किया. छात्रसंघ के सवाल पर या छात्रसंघ के विजयी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के सवाल पर हम लोग ही कैंपस से लेकर सड़क तक लड़े, सपा ही आगे बढ़कर संघर्ष करती रही. एक समय ऐसा था, जब छात्रसंघ बहाल था, छात्रसंघ का चुनाव हुआ करता था. समाजवादी पार्टी के पास ही पूरा का पूरा छात्र नेतृत्व रहा करता था. सपा से जुड़े छात्र ही छात्रसंघों में पहुंचते थे और बहुत बड़ी संख्या में छात्रसंघ से निकले हुए नौजवान आज हमारे संगठन में हैं. जहां तक कांग्रेस के युवा नेता का सवाल है, बहुत घूम-घूमकर प्रचार हो रहा है. उसमें अख़बार भी साथ दे रहे हैं, मीडिया भी साथ दे रहा है. ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे युवा नेतृत्व अकेले कांग्रेस के पास है, युवा चेहरे केवल कांग्रेस के पास हैं. यह सही है कि कांग्रेस ने युवा चेहरों को मौक़ा दिया है, मंत्री भी बना दिया, बहुत अच्छे पदों पर बैठा दिया संगठन में. यह सही है कि इन्हें मौक़ा मिला है काम करने का. देश के तमाम युवा इनकी तरफ़ देख रहे हैं कि ये कुछ काम करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उनकी निराशा दूर होगी, लेकिन केंद्र की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस के ये युवा नेता नाकाम साबित हो रहे हैं. इनकी असफलता का सवाल अब व्यापक शक्ल लेने लगा है. अब तो हम जहां भी जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच संघर्ष और समाधान की बात करेंगे तो हम पर भी सवाल उठेंगे. वे कहेंगे कि इतने बड़े-बड़े नेता जब कुछ नहीं कर पाए तो यह नेतृत्व क्या कर पाएगा. इसलिए अगर ये कुछ काम नहीं कर पा रहे, समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे, बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, युवाओं की निराशा कैसे ख़त्म हो, सरकार में होने के बावजूद अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो ये लोग सवाल अपने पर नहीं, बल्कि तमाम अन्य युवा नेतृत्वों के मत्थे भी तो छोड़े जा रहे हैं.

वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है. जिन सवालों का आपने ज़िक्र किया, उसके परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस नेतृत्व जिन सवालों के घेरे में है और भीषण भ्रष्टाचार के कारण बसपा नेतृत्व जिन सवालों के घेरे में है, इन घेरों से निकलने और राज्य में सपा की ताज़गी भरी युवा छवि को विकल्प के रूप में पेश करने की क्या कोई योजना है?

देखिए हम कर रहे हैं संघर्ष, वे कर रहे हैं सत्ता की राजनीति. हमारा उद्देश्य है संघर्ष में रहकर अपने साथ युवाओं को जोड़ना और वे सत्ता में रहते हुए भी युवाओं को नहीं जोड़ पा रहे हैं. जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 2012 के चुनाव का सवाल है, यह सही है कि उन्होंने (कांग्रेस ने) मिशन 2012 बनाया है, लेकिन इधर जनता को दिखाई ही नहीं दे रहा है कि वे मिशन 2012 के लिए कर क्या रहे हैं. मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो बर्बादी है, उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं को रोकने का जो काम किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का जो पैसा भ्रष्टाचार के ज़रिए बर्बाद हो रहा है, लूट हो रही है, इतना संगठित भ्रष्टाचार लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, जैसा बसपा की सरकार कर रही है. कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में भ्रष्टाचार दिखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खुलेआम लूट है, खुलेआम मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और पूरी सत्ता संगठित होकर भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस को यह दिखाई नहीं दे रहा है. अगर उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी इसके लिए ज़िम्मेदार है और प्रदेश की जनता यह देख रही है. इसलिए हम समाजवादियों को लगता है कि यदि हम तैयारी से अपनी नीतियों को लेकर जनता के पास जाएंगे, अपने कार्यक्रमों को लेकर जाएंगे तो उसका सार्थक परिणाम सामने आएगा. आज जनता को भी यह महसूस हो रहा है कि बेरोजगारी भत्ता कितना बड़ा फ़ैसला था समाजवादी पार्टी का...विद्या धन कितना बड़ा फ़ैसला था...जो हम लोगों ने विश्वविद्यालय बनाए, कॉलेज बनाए, सड़के बनाईं, पुल बनाए, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, चीनी मिलें लगवाईं...आज जनता याद कर रही है कि सपा की सरकार होती तो चीनी मिलें बिकती नहीं और लगतीं...लेकिन यह सरकार चीनी मिलें बेच रही है. हम लोगों ने फ़ैसला ले लिया था नौजवानों के लिए नौकरी का भी और बेरोज़गारी भत्ते का भी, लेकिन तमाम योजनाओं का पैसा यह सरकार लगवा रही है पत्थरों में, मूर्तियों में, स्मारकों में. इतने पत्थर आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं लगवाए होंगे, जितने उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार ने लगवा दिए. केवल इसलिए कि उनका नाम इतिहास में आ जाए. काम से इतिहास बनता है या पत्थर लगाने से? यह उन्हें कौन समझाए? इतिहास उत्तर प्रदेश का बने न बने, पर ख़ुद का इतिहास बनाना चाहते हैं. अपने ही महापुरुषों को छोटा दिखाना चाहती है सरकार. यह सरकार इस प्रयास में है कि भीमराव अंबेडकर का नाम भी उसके सामने छोटा पड़ जाए, कांशीराम भी पीछे छूट जाएं. मुख्यमंत्री अपनी मूर्तियां, पत्थर के हाथी, पत्थरों के पार्क और पत्थरों के स्मारक बनवाने में लगी हुई हैं. इतने पैसों से उत्तर प्रदेश का कितना भला हो सकता था, यह बात क्या जनता नहीं समझती है? और हम भी इन मसलों को जब जनता के पास ले जाएंगे तो हमें भरोसा है कि जनता समाजवादियों को मौक़ा देगी. प्रदेश में आम लोगों की ज़िंदगी बेहाल होकर रह गई है, लेकिन सरकार को कोई परवाह ही नहीं.

आपने कहा कि इन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जाएंगे...क्या इसकी कोई रूपरेखा बनी है?

पंचायत चुनाव के पहले ही हम लोगों ने प्रदेश भर में सर्वेक्षण कराया और लोगों से आवेदन मंगवाए. पार्टी का उद्देश्य यह है कि 2012 के चुनाव में प्रदेश के लोगों को बसपा की अराजकता से निजात मिले, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उन्हें मौक़ा दे, टिकट दे चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मंगवा लिया. आवेदन मंगवाने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर उन लोगों से बातचीत की. उन्हीं से पूछा कि कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे हम उन्हें विधायक बनवा सकते हैं. इस काम में समय ज़रूर लगा, लेकिन इससे प्रदेश भर की ताज़ा तस्वीर सामने उभर कर आई. पार्टी को यह विचार करने का आधार भी मिला कि विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी कैसा हो, ज़मीनी स्तर पर तैयारी कैसी हो और लोगों की मौजूदा सरकार के प्रति राय क्या है. ज़मीनी मुद्दे सामने आए. उम्मीदवारों के बारे में फ़ैसला करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. यह कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रदेश के तक़रीबन सारे ज़िलों में सर्वेक्षण और संभावित प्रत्याशियों से विचार-विमर्श का काम पूरा हो चुका है. बहुत जल्दी पार्टी यह फ़ैसला ले लेगी कि हमारा कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहेगा. 2012 में केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं बदलेगी, बल्कि 2014 में पूरे देश की राजनीति को भी बदलने का काम उत्तर प्रदेश ही करेगा. बिहार का विधानसभा चुनाव भी बहुत हद तक उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति का संकेत देगा. मिशन बनाकर जो दल घूम रहे हैं (इशारा कांग्रेस व बसपा की तरफ था), उनका मिशन जब बिहार में फेल हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में उसके असर के बारे में आसानी से समझा जा सकता है.

आप कन्नौज के सांसद होने के साथ-साथ सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. पार्टी का युवा अध्यक्ष क्या विधानसभा चुनावों में युवा प्रत्याशियों को प्राथमिकता देगा?

आप यकीन मानिए कि प्रदेश भर में हम लोगों ने संभावित प्रत्याशियों से जो बातचीत की है या जो भी हमने सर्वे किया है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में युवकों ने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा है. हम उन्हें मौक़ा भी देंगे, लेकिन हमने एक शर्त ज़रूर रखी है कि उन्हें जनता के बीच रहकर काम करना होगा. अगर जनता के बीच काम करेंगे और इसका हम आकलन कर लेंगे और जनता से पता कर लेंगे कि वाकई उसके बीच रहकर किसी ने काम किया है तो पार्टी ऐसे प्रतिबद्ध युवकों को ज़रूर मौक़ा देगी.

जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारनीत भ्रष्टाचार के प्रति कांग्रेस आंखें मूंदे हुए है. क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और बसपा के बीच कोई अंदरूनी समझदारी है?

मैं लोकसभा का सदस्य हूं. लोकसभा में कई बार कई ऐसे मुद्दे आते हैं, जब बसपा के सांसद पूरी तरह भ्रमित दिखते हैं कि उन्हें निर्णय क्या लेना है. वे तुरंत-तुरंत बदलते रहते हैं. कई ऐसे सवाल आए, जिनमें बसपा के सांसद बोलना चाहते थे, लेकिन अचानक पीछे हट गए. सपा की नीति और रास्ता साफ़ है कि हम भाजपा के साथ नहीं जा सकते. हम दूरी बनाकर रखेंगे भाजपा और कांग्रेस से. जितने भी महत्वपूर्ण सवाल सामने आए लोकसभा में, बसपा ने कांग्रेस को ही अपना समर्थन दिया. कुछ मसलों पर हमने भी कांग्रेस को समर्थन दिया है, लेकिन हमारी स्पष्ट राजनीतिक बाध्यता है कि हम भाजपा को सत्ता के क़रीब कतई नहीं आने देना चाहते. अब देखिए न, नोएडा पार्क का मसला. लोगों ने आंदोलन किया. बसपा सरकार ने पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने ही नो ऑब्जेक्शन दे दिया. ईको पार्क कहकर पत्थरों का पार्क बना दिया और पुराने जेल परिसर में लगे सैकड़ों घने-पुराने पेड़ काट डाले. इस पर केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले वन विभाग ने चुप्पी क्यों साधे रखी? कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जला डाला. घर जलाने वाले को बसपा ने विधान परिषद का सदस्य बना दिया. कांग्रेस चुप्पी क्यों साधे रह गई? कहीं न कहीं लगता है कि कांग्रेस की कोई समझ है या मदद मिल रही है, जिससे शह पाकर बसपा सरकार प्रदेश में मनमानी करने पर उतारू है. अगर केंद्र सरकार अंकुश लगा दे या सख्त रवैया अख्तियार कर ले तो यह पत्थर लगना, यह लूट-भ्रष्टाचार सब एक दिन में रुक जाए.

सामाजिक-राजनीतिक माहौल के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक पर्यावरण भी नष्ट कर डाला है. सैकड़ों घने पेड़ काट डाले गए, पत्थरों से शहर को पाट डाला गया और गोमती नदी के किनारों को भी अतिक्रमित कर वहां भी पत्थर मढ़ दिए गए. सपा के पास आख़िर क्या इलाज है इसका?

बसपा सरकार ने केवल लखनऊ में चार हज़ार एकड़ ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ा किया है. उसे पत्थरों से पाट दिया और हज़ारों करोड़ रुपये फूंक डाले. पर्यावरण की तो धज्जियां उड़ाकर रख दीं. इस सरकार ने पर्यावरण के सारे नियम ध्वस्त कर डाले. गोमती नदी और नालों तक पर क़ब्ज़ा हो गया. केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश भर में. इस सरकार ने इतना नुक़सान कर दिया है कि उसका इलाज किसी चमत्कार से तो हो नहीं सकता, लेकिन जब कभी भी जनता हमें मौक़ा देगी और हमारी सरकार आएगी तो जिस पर्यावरण को इस सरकार ने ख़त्म कर डाला है, उसे बहाल करने की कोशिश ज़रूर करेगी. सोनभद्र, मिर्जापुर, हमीरपुर एवं बुंदेलखंड आदि में बिना मापदंडों के जो पत्थर खोदे गए और पहाड़ों का विध्वंस किया गया, उसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई नौकरशाह. ऐसे नौकरशाहों की शिनाख्त है और उन्हें जेल जाना होगा.

जिन अधिकारियों ने बसपा के कैडर की तरह आचरण किया, नौकरशाही की आचार संहिता का उल्लंघन किया और सत्ता के शीर्ष गलियारे पर भी वही क़ाबिज हैं. ऐसे नौकरशाहों से कैसे निबटेगी आपकी पार्टी, अगर सत्ता में आई तो?

ऐसे तमाम अधिकारी हैं, जिनकी ज़िम्मेदारियां कुछ दूसरी थीं और वे अपनी आचार संहिता भूल गए. वे अपनी सीमाएं तोड़कर आगे बढ़ गए और सरकारी काम छोड़कर उन्होंने मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी के नौकर की तरह काम किया. जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, भ्रष्टाचार किया है, प्रदेश को लूटा है, बर्बाद किया है, समाजवादी पार्टी ने साढ़े तीन साल में ऐसे ही अधिकारियों की सूची तैयार की है, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए.

2007 से लेकर अभी तक जिस तरह बसपा ने अराजक राजनीति और प्रशासन का सृजन किया, उसके ख़िलाफ़ सपा ने पुरज़ोर विरोध दर्ज क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी कहीं अपने आप को कमज़ोर तो नहीं पाती रही मायावती सरकार के सामने?

सबसे पहली लाठी छात्रसभा के नौजवानों पर बरसी थी. जैसे ही बसपा की सरकार बनी थी, समाजवादियों ने मौका दिया था छह महीने का. कुछ महीने गुज़र जाने के बाद सपा के युवा नेताओं ने छात्रसंघ के मसले पर सरकार को घेरा था. समाजवादी लोग केवल सरकार से पूछना चाहते थे कि छात्रसंघ की बहाली का जो आश्वासन सदन में दिया गया था, वह कब पूरा होगा. इस लोकतांत्रिक मांग पर छात्रसभा के नौजवानों को बुरी तरह पीटा गया. जख्मी छात्रों का इलाज कराने के बजाय उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसके ख़िलाफ़ प्रदेश नेतृत्व एसएसपी आवास के सामने जाकर बैठ गया. उनमें मैं भी शामिल था. उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रही. यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता शिवपाल सिंह यादव के साथ भी पुलिस ने हाथापाई की. पार्टी के सदस्यों और नेताओं पर जितने झूठे मुकदमे इस सरकार ने लादे और जेल भेजा, ऐसा कभी नहीं हुआ. यह लोकतांत्रिक राजनीति का काला पन्ना है. क्या इसे समाजवादी पार्टी भूल जाएगी?

आख़िर में प्रदेश के दलितों और खास तौर पर मुसलमानों के बारे में बताएं कि यह समुदाय कितना बसपा के साथ है और कितना सपा के साथ?

यह केवल कहने-सुनने की बात है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की सरकार है. प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों की हालत ख़राब है, जिनका तथाकथित रूप से नेतृत्व कर रही है बसपा सरकार. संकट में पड़ने पर मुख्यमंत्री ज़रूर यह कहती हैं कि वह दलित हैं, इसलिए संकट में हैं और संकट दूर होते ही अपना व्यक्तिगत और अपने चाकरों का हित साधने लगती हैं. उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? सबसे ग़रीब वे, सबसे भूखे वे, सबसे प्रताड़ित वे...फिर किस बात की दलित सरकार? दलितों को यह साफ समझ में आ गया है कि मायावती केवल दलितों की एक जाति के लिए हैं, वह जाटव जाति भी भ्रम में ही है. दलितों के इस एक वर्ग के लिए भी मायावती ने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर? अब दलितों को यह लगने लगा है कि उनका हित समाजवादी पार्टी ही देख सकती है. रही बात मुसलमानों की, तो आप यह मानें कि मुसलमान सपा के ही साथ हैं. मुसलमानों के साथ सपा का पारंपरिक रिश्ता है. कल्याण सिंह का मसला तो मीडिया का मसला है. मुसलमान भी जानते हैं कि कल्याण का साथ केवल इसलिए लिया गया था कि हमें भाजपा को उसकी औकात दिखानी थी.

prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. अरविंद कुमार जैन बताते हैं कि जब वह मंत्री थे तो उन्होंने एक बार स्वास्थ्य भवन में छापा मारने की ग़लती कर दी, जहां से वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आ पाए.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 15 नवंबर–21 नवंबर 2010

कश्मीर

एक बयान देशद्रोह दूसरा क्या है?

बुकर पुरस्कार विजेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय ने पिछले दिनों कश्मीर पर एक बयान दिया. उनका कहना था कि कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं रहा. उन्होंने ये बातें श्रीनगर में आयोजित एक सेमिनार में कहीं. इस बयान पर सरकार की भौंहें तनी और दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिया गया कि वह अरुंधति के बयान की अच्छी तरह जांच करे और वे आधार ढूंढे, जिनसे उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सके. गौरतलब है कि इसी दौरान दिलीप पडगांवकर ने भी एक बयान दिया. वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर पर बने मध्यस्थ दल की अध्यक्षता कर रहे दिलीप पडगांवकर ने श्रीनगर में कहा कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए जारी बातचीत में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाना चाहिए. अब सवाल यह है कि यदि अरुंधति राय का बयान देशद्रोह है तो पडगांवकर का बयान क्या है? उनकी जिम्मेदारी कश्मीर में शांति बहाली के लिए रास्ता खुलवाना था या फिर इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण करना. क्या वह संयुक्त राष्ट्र में नेहरू जी के उस भाषण को भूल गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? बावजूद इसके पडगांवकर का कहना था कि अगर लोग यह मानते हैं कि बिना पाकिस्तान के साथ बातचीत किए हालात सुधारे जा सकते हैं तो यह गलत होगा. पाकिस्तान कश्मीर मामले में 1947 से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए शांति बहाली के लिए उससे बातचीत आवश्यक है.

पडगांवकर के इस बयान पर राजनीतिक बहस तो छिड़ी ही, साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई. चौथी दुनिया से बातचीत में प्रख्यात इस्लामिक विद्वान कल्बे रुशैद रिजवी ने कहा कि कश्मीर के आम लोग यह कभी नहीं चाहते कि कश्मीर मसले पर किसी भी रूप में पाकिस्तान को शामिल किया जाए. वहां की जनता पाकिस्तान को एक बीमार देश के रूप में देखती है, जो किसी की भी मदद नहीं कर सकता. बहरहाल, पडगांवकर यह बयान भी देते हैं कि कश्मीर में मध्यस्थ दल वहां के लोगों से मीडिया के सामने बातचीत नहीं करेगा. गौरतलब है कि गृहमंत्री पी चिदंबरम ने भी मध्यस्थ दल को निर्देश दिया है कि मीडिया से बातचीत कम ही की जाए. दिलचस्प तथ्य यह है कि पडगांवकर खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं. ऐसे में एक पत्रकार का मीडिया के बारे में नकारात्मक बयान देना कहां तक सही माना जा सकता है? वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर इस पर कहते हैं कि पहले तो सरकार कश्मीर मसले पर मीडिया को प्रोत्साहित करती है, फिर इस मामले को मीडिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रही है. सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.

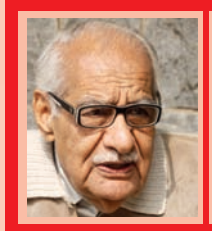

जाहिर है, शुरू से ही कश्मीर एक संवेदनशील मसला रहा है. अरुंधति राय के बयान को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि अरुंधति ने अपने बयान के बारे में यही कहा था कि वह वही कह रही हैं, जो लाखों लोग रोज कहते हैं. लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कुछ ऐसा ही बयान सरकार द्वारा बनाए गए मध्यस्थ दल के मुखिया भी देते हैं, तब क्यों सरकार चुप्पी मार जाती है? यह क्यों साफ नहीं किया जाता कि मध्यस्थ दल किसके इशारे पर ऐसा बयान दे रहा है. क्या इस बयान के लिए सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और कांग्रेस ने अपनी सहमति दी थी? अगर नहीं तो फिर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की धमकी किसी एक को ही क्यों दी जाती है?

शशि शेखर/सिद्धार्थ राय
feedback@chauthiduniya.com

यह सरकार गैगिंग गवर्नमेंट बन चुकी है. विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों का मुंह बंद कराने की कोशिश इस सरकार की पॉलिसी बन गई है.
–ए बी वर्धन, महासचिव, सीपीआई.

पहले तो सरकार कश्मीर मसले पर मीडिया को प्रोत्साहित करती है, फिर इस मामले को मीडिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रही है. सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.
–कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार.

कश्मीर के आम लोग कभी नहीं चाहते कि कश्मीर मसले पर किसी भी रूप में पाकिस्तान को शामिल किया जाए. वहां की जनता पाकिस्तान को एक बीमार देश के रूप में देखती है, जो किसी की भी मदद नहीं कर सकता.
–कल्बे रुशैद रिजवी, इस्लामिक विद्वान.

चौथी दुनिया से बातचीत में प्रख्यात इस्लामिक विद्वान कल्बे रुशैद रिजवी ने कहा कि कश्मीर के आम लोग यह कभी नहीं चाहते कि कश्मीर मसले पर किसी भी रूप में पाकिस्तान को शामिल किया जाए.

उत्तर प्रदेश

माफ़िया के हवाले स्वास्थ्य सेवाएं

सुरेंद्र अग्निहोत्री

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर माफियाओं का एकछत्र राज कायम है. स्वास्थ्य सेवाओं से संबद्ध सरकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों का गठजोड़ इतना सघन हो गया है कि राजधानी लखनऊ में डेंगू से ताबड़तोड़ हुईं कई मौतों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को अदालत में तलब करना पड़ा. चाहे नकली दवाओं का मामला हो या खाद्य पदार्थों में मिलावट का या फिर मलेरिया उन्मूलन हेतु आने वाले करोड़ों के बजट को चट करने का, उत्तर प्रदेश की अव्वलता को कोई चुनौती नहीं दे सकता. जिसने भी चुनौती देने की कोशिश की, उसे रास्ते से हटना पड़ा. कोई पद से गया, कोई कद से गया तो कोई दुनिया से ही चला गया.

प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. अरविंद कुमार जैन बताते हैं कि जब वह मंत्री थे तो उन्होंने एक बार स्वास्थ्य भवन में छापा मारने की ग़लती कर दी, जहां से वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आ पाए. यही हाल पूर्व मंत्री डॉ. जौहरी का रहा, उन्हें बीच में ही मंत्री पद से रुखसत होना पड़ा. परिवार कल्याण मंत्री देवेंद्र सिंह भोले भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे. माफ़ियाओं के गठजोड़ के तार इतने मज़बूत हैं कि उनके आगे मंत्री तक खुद को बौना महसूस करते रहे हैं. प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं की झलक देखने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किए गए एक ऑपरेशन की बानगी ही काफी है. मिशन के तहत कानपुर देहात में एक पुरुष की बच्चेदानी निकालने के नाम पर भुगतान ले लिया गया. अधिकारियों ने इस भुगतान को ख़ुशी–ख़ुशी पास भी कर दिया. ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन कार्यवाही करे भी तो कौन? जब आका ही पूरे खेल में शामिल हों तो फिर शिक़ायत किससे की जाए? हाल में सीबीआई ने दवा के नाम पर ज़हर देने वाले लोगों का भंडाफोड़ करके राज्य सरकार से दवा आपूर्ति करने वाली संबंधित फर्म के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराने की अनुमति मांगी है. सीबीआई सूत्रों के अनुसार, इस फर्म के राजनीतिक रिश्तों के भी पुख्ता सबूत मिल चुके हैं. यह फर्म काफी समय से सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करती रही है. इनमें जीवनरक्षक दवाएं भी शामिल हैं. सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए एक पत्र में इस मामले में मुक़दमा दर्ज कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है. गृह एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिवों को भी इस पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है, ताकि वे जान सकें कि राज्य में किस तरह खुलेआम जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव को भेजे गए इस पत्र में सीबीआई ने राज्य में हो रहे दवा घोटाले का पूरा ज़िक्र किया है. केंद्र सरकार को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाएं दिए जाने की शिक़ायतें मिली थीं. इस आधार पर मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, रामपुर, बरेली एवं शाहजहांपुर आदि ज़िलों के सरकारी अस्पतालों में छापे मारे गए. वहां दी जा रही दवाओं के नमूने लिए गए, जिनकी जांच कोलकाता स्थित सरकारी लैब में कराई गई. जांच में पाया गया कि एक फर्म विशेष द्वारा सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की गई दवाएं मानक के अनुरूप नहीं हैं.

जांच रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई ने मेरठ स्थित उस फर्म विशेष पर अपनी नज़रें गड़ाईं. पता चला कि वह राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाली प्रमुख फर्मों में शामिल है. इस फर्म के साथ विभिन्न राजनीतिक हस्तियों, विभागीय अधिकारियों एवं डॉक्टरों के गठजोड़ के भी तमाम सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं. सूत्रों के अनुसार, शासन में उक्त फर्म के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है. यहां यह जान लेना ज़रूरी है कि प्रदेश में 45 सौ करोड़ रुपये के विभागीय सालाना बजट में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के बजाय अहम पदों पर बैठे लोगों द्वारा कमीशन हड़पने का खेल खुलेआम चलता है. इस खेल में अगर कोई आदमी दीवार बनता है तो उसे निपटा दिया जाता है, कभी तबादले से तो कभी दूसरे तरीक़ों से. एक वक़्त ऐसा था, जब डीजी हेल्थ के आगे प्रमुख सचिव तक घुटने टेकने को मजबूर हो जाते थे. पल्स पोलियो, शिशु मातृ सुरक्षा, कुष्ठ निवारण, टीकाकरण, जननी सुरक्षा, क्षय रोग उपचार एवं अंधता निवारण जैसी योजनाएं सरकारी बजट की बंदरबांट का ज़रिया बनी हुई हैं. वर्ष 2000 में परिवार कल्याण विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉ. बच्ची लाल की हत्या का कारण उनका इस पद पर पहुंचना ही था. वह भविष्य में डीजी हेल्थ बनने वाले थे. इस हत्या में एक वर्तमान माफ़िया सांसद का नाम पुलिस विवेचना में आया था. अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं में सिर्फ़ उद्योगपति और ठेकेदार ही भूमिका अदा करते थे, लेकिन माफ़ियाओं के ख़ूनी खेल ने स्वास्थ्य विभाग के रंग और ढंग ही बदल दिए. निर्माण कार्यों की निविदाएं तय करने और ठेका पाने की जोड़तोड़ राजधानी लखनऊ में होने लगी. निर्माण कार्यों हेतु मिलने वाले अरबों के बजट के लालच में माफ़ियाओं ने इस विभाग में अपना डेरा डाल दिया. परिणामस्वरूप अनेक चिकित्सालयों का निर्माण मानक के विपरीत हुआ. कई जगह आईसीयू सहित अनेक मशीनें बेवजह ख़रीद ली गईं अथवा आईसीयू बना दिया गया, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचमए) के तहत मिले तीन हज़ार करोड़ रुपये पर सबकी निगाहें हैं. परिवार कल्याण के नाम पर ज़िलेवार क़रीब 15 से 30 करोड़ रुपये ख़र्च होने हैं. इसके लिए शासन की नई व्यवस्था से माफ़ियावाद को बढ़ावा मिलेगा. सीएमओ–परिवार कल्याण को सीधे चेक से भुगतान, आपूर्ति एवं निर्माण के ठेके देने और संविदा चिकित्सकों, नर्सों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति आदि का अधिकार देना विभागीय चिकित्सकों भी हज़म नहीं हो रहा है. सीएमओ के समानांतर सृजित सीएमओ– परिवार कल्याण पद के ख़िलाफ़ प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ अदालत चला गया है. संघ के अध्यक्ष डॉ. यू एन राय का कहना है कि वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए भुगतान चेक पर दो अधिकारियों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए. उधर सीएमओ–परिवार कल्याण डॉ. विनोद कुमार आर्या के हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने विभाग के कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं. उन कर्मचारियों का भी लेखा–जोखा हासिल किया जा रहा है, जो सीएमओ के क़रीब रहते थे. पता चला है कि अंधता निवारण योजना के तहत 53 लाख के टेंडर के अलावा किसी भी ठेके का मामला मौजूदा समय में नहीं था. यही टेंडर पाने के लिए ठेकेदारों में जोर आजमाइश चल रही थी. डॉ. आर्या की नियुक्ति चार महीने पहले ही बतौर ज़िला परियोजना अधिकारी, परिवार कल्याण (डीपीओ) हुई थी. एक माह पहले ही डीपीओ का पद सीएमओ–परिवार कल्याण में तब्दील हुआ था. तबसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य उनके पास थे. मूल रूप से शाहजहांपुर निवासी डॉ. आर्या के करियर पीएमएस से 1987 में शुरू हुआ था. सूत्रों के मुताबिक़, उनके कामों से जुड़ा लगभग तीस करोड़ रुपये का बजट हाल में जारी हुआ था.

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी ठेके और हत्याएं

बीते दस वर्षों के दौरान सरकारी ठेके हथियाने को लेकर एक दर्जन से ज़्यादा हत्याएं हुईं. राजधानी लखनऊ में डॉ. आर्या की हत्या के तुरंत बाद बहराइच में ठेकेदारी को लेकर एक अवर अभियंता पर जानलेवा हमला हो गया. सरकारी ठेकों के चक्कर में अब तक कई अधिकारी अपनी जान गवां चुके हैं.एस के मिश्रा जल निगम सीतापुर में मुख्य अभियंता थे. 2001 में लखनऊ में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई. 6 जुलाई 2003 को मुरादाबाद में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अनवर मेंहदी रिजवी की हत्या हो गई. सोनभद्र में इसी विभाग के एक और सहायक अभियंता एस आर चौधरी 28 दिसंबर 2004 को अपनी जान गवां बैठे. इसी प्रकार 23–24 दिसंबर 2008 की रात अधिशासी अभियंता औरैया मनोज कुमार गुप्ता की हत्या कर दी गई. 2 अगस्त 2009 को गोरखपुर में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता मनोज कुमार सिंह की हत्या हो गई. 2009 में ही सरयू नहर खंड–3 बलरामपुर के सहायक अभियंता रूप चंद्र भास्कर की हत्या हुई. इसी तरह अधिशासी अभियंता जी एस यादव भी मौत के घाट उतार दिए गए.

देश के विकसित एवं समृद्ध क्षेत्रों में गिने जाने वाले चंडीगढ़ के इन आंकड़ों से भारत के ग्रामीण इलाक़ों की हालत के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है.

स्वास्थ्य सेवाओं में लिंगभेद

नज़रिये में बदलाव की ज़रूरत

केयर इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और सीतापुर में कराए गए एक अन्य सर्वे के मुताबिक़, 15–44 साल की अधिकांश महिलाओं को नर और मादा जननांगों के बारे में कम ही जानकारी है.

	पुरुष	महिला
नए ओपीडी मरीज	4470 (54.60)	3713 (45.40)
पुराने ओपीडी मरीज	29332 (57.00)	22163 (43.00)
आवश्यक टीकाकरण	18615 (51.80)	17333 (48.20)
भर्ती मरीजों का प्रतिशत	55.80	44.20

आदित्य पूजन

देश में बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी सायना नेहवाल जब पैदा हुई थीं तो उनकी दादी एक महीने तक उन्हें देखने नहीं गईं, क्योंकि उन्हें पोती नहीं, पोते की हसरत थी. भारत के पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों के प्रति यही नज़रिया उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा है, साथ ही उन्हें ऐसी सुविधाओं के उपभोग से भी दूर करता है, जो देश में आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं. यह बात देश में स्वास्थ्य सेवाओं एवं महिलाओं की स्थिति को देखकर और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे–3 के मुताबिक़, भारत में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु दर और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, इन तीनों ही वर्गों में महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों से कहीं ज़्यादा है. आंकड़ों में यह अंतर हमारी सामाजिक अवधारणाओं की पुष्टि करता है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संकुचित रवैया अपनाया जाता है, सुविधाएं सुलभ होने पर भी उन्हें उनसे दूर रखा जाता है.

इंडियन जर्नल ऑफ पीडियॉट्रिक्स ने हाल के दिनों में चंडीगढ़ में एक सर्वे किया, जिसमें यह पाया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं के उपभोग के मामले में महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं. सर्वे के मुताबिक़, स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी सेवा का लाभ उठाने वाले रोगियों की संख्या में पुरुषों का प्रतिशत 54.60 रहा, जबकि महिलाओं का 45.40. एक बार डॉक्टरी सहायता लेने के बाद दोबारा ओपीडी सेवा का लाभ उठाने वाले मरीजों में भी महिलाओं का अनुपात पुरुषों से काफी कम है. सर्वे के अनुसार, 57 प्रतिशत पुरुषों के मुक़ाबले केवल 43 प्रतिशत महिलाएं ही इस सेवा का लाभ उठा पाती हैं. इन दो आंकड़ों से समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य को दी जाने वाली अहमियत के बारे में पता चलता है. अस्पतालों में भर्ती किए जाने वाले रोगियों की संख्या के लिहाज़ से देखें तो इसमें भी पुरुषों का अनुपात 55.80 प्रतिशत रहा, जबकि महिलाओं का केवल 44.20 प्रतिशत. स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक टीकाकरण कार्यक्रम में भी महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं. पुरुषों के मामले में यह अनुपात जहां 51.80 प्रतिशत रहा, तो महिलाओं के मामले में केवल 48.20 प्रतिशत.

देश के विकसित एवं समृद्ध क्षेत्रों में गिने जाने वाले चंडीगढ़ के इन आंकड़ों से भारत के ग्रामीण इलाक़ों की हालत के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है. हमारे सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश में महिलाओं के स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना पुरुषों के. भारत अपनी जीडीपी का लगभग 5.1 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर ख़र्च कर रहा है. पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के बाद पिछले क़रीब 60 सालों में पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है. ग्रामीण इलाक़ों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य मेलों आदि के माध्यम से आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन दुखद सत्य यह है कि महिलाएं फिर भी इनका उपभोग नहीं कर पाती हैं. देश में महिलाओं के स्वास्थ्य पर एक नज़र दौड़ाएं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का मुख्य ध्यान गर्भाधान, शिशु के सुरक्षित जन्म और गर्भ निरोध पर केंद्रित है. उक्त सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन पर जोर देने से महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अन्य पहलू पृष्ठभूमि में चले जाते हैं. इनमें कुपोषण, जननांग संबंधी और सेक्स जनित संक्रमित बीमारियां महत्वपूर्ण हैं. हैरत की बात तो यह है कि देश के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इन पहलुओं से पूरी तरह अनजान हैं.

केयर इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और सीतापुर में कराए गए एक अन्य सर्वे के मुताबिक़, 15–44 साल की अधिकांश महिलाओं को नर और मादा जननांगों के बारे में कम ही जानकारी है. इतना ही नहीं, अविवाहित लड़कियों का 56 प्रतिशत और विवाहित महिलाओं का 57 प्रतिशत मासिक संबंधी समस्याओं के बारे में जानते हुए भी इलाज नहीं कराता. सर्वे के नतीजों से यह बात भी खुलकर सामने आ जाती है कि सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन ग्रामीण इलाक़ों में अभी भी अधिकतर महिलाएं प्रसव के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं जातीं. घरों में शिशु के जन्म के दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की ग़ैर मौजूदगी से जच्चा और बच्चा की जान को ख़तरा रहता है. सर्वे के मुताबिक़ जननांग संबंधी और सेक्स संक्रमण से होने वाली बीमारियों के बारे में अधिकांश महिलाएं कुछ भी नहीं जानतीं. जानकारी न होने से वे इनसे बचने के तरीक़े भी नहीं अपनातीं. कोई आश्चर्य नहीं कि 15–44 साल की विवाहित महिलाओं का 37.3 प्रतिशत इन बीमारियों से ग्रस्त है, जबकि इस आयु वर्ग के पुरुषों में यह प्रतिशत केवल 10 है.

इन आंकड़ों से यह बात तो स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं के उपभोग के मामले में महिलाएं पुरुषों के मुक़ाबले पीछे हैं. इसके लिए सरकार की वे खोखली नीतियां ज़िम्मेदार हैं, जिनमें महिलाओं की सामाजिक हैसियत के लिए कोई जगह नहीं होती. सरकार नीतियां बनाकर और पैसों का आवंटन कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेती है, जबकि सच्चाई यह है कि उक्त धनराशि सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और ग्रामीण इलाक़ों की महिलाएं बेमौत मरने को अभिशप्त हैं. इन नीतियों और योजनाओं से होने वाले फ़ायदों के बारे में महिलाओं को कैसे बताया जाए, उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक कैसे बनाया जाए, इसके लिए कोई पहल नहीं की जाती. हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं के उपभोग के मामले में महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए सारा दोष सरकार को ही नहीं दिया जा सकता. इसके लिए हमारी वह संकुचित सोच और सामाजिक अवधारणाएं भी ज़िम्मेदार हैं, जिनमें महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है. उन्हें न बोलने की आज़ादी है और न ख़ुद के बारे में फ़ैसले लेने की. सारे फ़ैसले परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, जिनमें उनकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता.

हमारे सामाजिक परिवेश में महिलाओं को इस तरह रहने की सीख दी जाती है कि वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में खुलकर बोल भी नहीं पातीं. बचपन से ही उन्हें यह सिखाया जाता है कि बर्दाश्त करना, दर्द को सहना नारियों का गुण है. सारी सुविधाएं पुरुषों के लिए बनी हैं और उन पर उनका एकाधिकार है. इस सामाजिक दायरे से बाहर जाने वाली महिलाओं को उत्शृंखल समझा जाता है. फिर महिलाओं की अशिक्षा और शर्मीला व्यवहार भी इसमें एक बड़ी बाधा है. अशिक्षा का नतीजा यह है कि महिलाएं अपनी स्वास्थ्य समस्याओं की ओर से अनजान बनी रहती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदगी के बावजूद वहां तक नहीं पहुंच पातीं. पहुंचती भी हैं तो पुरुष चिकित्सकों के सामने अपनी समस्याएं बता नहीं पातीं. आज भारत हर क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है और इसमें पुरुषों के साथ नारियां भी समान रूप से क़दमताल कर रही हैं. जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें महिलाओं की उपलब्धियों को पुरुषों से कमतर आंका जा सके. इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं में लिंगभेद की यह समस्या हैरान करती है. साथ ही इस समस्या से पार पाना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है. इसके लिए ज़रूरी है कि महिला साक्षरता में वृद्धि के साथ–साथ उनके बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए हरसंभव प्रयत्न किए जाएं. ग्रामीण इलाक़ों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सामाजिक नज़रिए में बदलाव. जब तक समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहेगा, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता रहेगा, तब तक हालत में किसी व्यापक बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती.

aditya@chauthiduniya.com

अयोध्या मसले के समाधान में सभी समुदाय के लोगों का सहयोग जरूरी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीमकोर्ट के बाद क्या होगा.

सूफी सैय्यद जिलानी कत्ताल का अयोध्या दौरा

अमन की राह पर एक सार्थक पहल

राजेश एस कुमार

जहां एक तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड और विभिन्न हिंदू संगठनों ने अयोध्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है, वहीं दूसरी ओर इस मामले को अदालत से बाहर सुलझा लेने की कोशिशें भी जारी हैं. अच्छी बात यह है कि यह प्रयास हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के धर्मगुरुओं, विद्वानों एवं हाशिम अंसारी जैसे आम नागरिक की तरफ से किए जा रहे हैं. ये नेक नीयत वाले लोग हैं, जो इस मसले को आपसी सद्भाव, सौहार्द्र और बातचीत से सुलझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं. ऐसी ही एक कोशिश अक्टूबर की 26 तारीख को देखने को मिली, जिसके तहत श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण और वर्ल्ड सूफी काउंसिल के चेयरमैन सूफी सैय्यद जिलानी कत्ताल ने मिलकर बैठक के जरिए अयोध्या मसले को निपटाने की बात कही. सैय्यद मोहम्मद जिलानी के अयोध्या आगमन के बाद हुई इस पहल में रामनगरी के कई धर्माचार्य शामिल हुए. गौरतलब है कि रसिक पीठाधीस्वर महंत जन्मेजय शरण सूफी सैय्यद जिलानी कत्ताल के साथ मिलकर दस वर्षों से भारत के कोने-कोने में सद्भाव यात्रा के माध्यम से शांति, अमन और सौहार्द्र का पैगाम दे रहे हैं. भक्ति आश्रम के महंत राम प्रिया शरण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बड़ा भक्तमाल के महंत कौशल किशोर दास, आचार्य राम टहल शरण वेदांती, सुतीक्ष्ण आश्रम के महंत जगदेव शरण, स्वामी पराकुंशाचार्य के अलावा आल इंडिया प्रियंका-राहुल गांधी फोरम के प्रदेश सचिव नारायण मिश्र, जिलाध्यक्ष मधुबन दास एवं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बालकृष्ण गोस्वामी भी मौजूद थे.

महंत जन्मेजय शरण ने जानकी घाट स्थित बड़े स्थान मंदिर परिसर में आयोजित शांति सौहार्द्र वार्ता में उपस्थित संत समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अखंडता बनी रहेगी तो इस मामले का हल अपने आप हो जाएगा.

महंत जन्मेजय शरण ने जानकी घाट स्थित बड़े स्थान मंदिर परिसर में आयोजित शांति सौहार्द्र वार्ता में उपस्थित संत समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अखंडता बनी रहेगी तो इस मामले का हल अपने आप हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हम लोग देश के अलग-अलग इलाकों में सद्भावना स्थापित करने के साथ बातचीत के जरिए मसले के समाधान में जुटे हैं. देशवासियों की ओर से भी इस दिशा में सकारात्मक समर्थन मिला है. सूफी सैय्यद जिलानी जब अयोध्या पहुंचे तो वहां उन्होंने जन्मेजय शरण और अन्य संत-महंतों के साथ रामलला के दर्शन किए. उसके बाद वह गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड गए, जहां उन्होंने माथा टेका. वर्ल्ड सूफी काउंसिल के चेयरमैन सूफी सैय्यद जिलानी ने कहा कि चाहे कश्मीर हो या अयोध्या, सभी मसलों का हल आपसी बातचीत से ही संभव है. फिर हम आपस में क्यों लड़ें? जरूरत तो इस बात की है कि इस दिशा में सार्थक पहल की जाए और लोग इसमें अपनी भरपूर भागीदारी करें. इससे देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी. कोई भी मजहब खूनखराबे की इजाजत नहीं देता. फिर मंदिर-मस्जिद के नाम पर खून क्यों बहाया जा रहा है? अगर हम ही नहीं रहेंगे तो मंदिर-मस्जिद में इबादत आखिर करेगा कौन? इस्लाम गले लगाने का हिमायती है और मजहब से बड़ी इंसानियत है. अयोध्या मसले के समाधान में सभी समुदाय के लोगों का सहयोग जरूरी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीमकोर्ट के बाद क्या होगा, आखिर वहां से वापस आकर भी बातचीत का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा.

जिलानी ने बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाकर गैर मजहबी लोगों को गले लगाने और पीड़ितों की मदद करने का संदेश दिया है. उन्होंने बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि समय मिला तो वह उनसे मिलने भी जाएंगे. सबसे पहले खुद को भारतीय बताते हुए सैय्यद जिलानी ने देश की तरक्की को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया. महंत जन्मेजय शरण ने कहा कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मस्थली है, लेकिन यहां अन्य धर्मों को भी बराबर सम्मान मिलता रहा है. हम हिंदू-मुस्लिम बाद में हैं, पहले इंसान हैं. हनुमानगढ़ी के नागा रामलखन दास ने अयोध्या मसले को राजनीतिक रंग देने वालों को इससे दूर रहने की सलाह दी. जाहिर है, इन विद्वानों के नेक प्रयास इस बात के उदाहरण हैं कि हिंदुस्तान की गंगा-जमुनी तहजीब आज भी जिंदा है, जो किसी भी सांप्रदायिक संगठन या राजनीतिक दल के खतरनाक मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी.

rajesh@chauthiduniya.com

पत्थरों के इस गांव में लहलहाती हरियाली और झूमते पेड़ सरकार द्वारा चलाई जा रही पर्यावरण बचाने की मुहिम के लिए एक प्रेरक मिसाल हो सकते हैं.

पिपलांत्री

जगमगाती गलियां और वातानुकूलित पंचायत भवन

शशि शेखर

उदयपुर से तक़रीबन 70 किलोमीटर दूर राजसमंद ज़िले में एक ग्राम पंचायत है पिपलांत्री. 16 सौ की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत विकास के नित नए सोपान रच रही है. अरावली की संगमरमर की पहाड़ियों पर बसे पिपलांत्री को देखकर गर्व होता है कि भारत गांवों का देश है और अब गांव भारत के लोकतंत्र को सही मायनों में परिभाषित कर रहे हैं. यह यहां के लोगों द्वारा मिलजुल कर लिए गए फ़ैसलों का ही नतीजा है कि पिछले कई सालों से सूखे की मार झेल रहे पिपलांत्री की पहाड़ियों से मीठे पानी के स्रोत फूट रहे हैं और पत्थरों पर फूल खिल रहे हैं. आप गांव में घूमेंगे तो वैसा कतई नहीं लगेगा, जैसा राजस्थान के किसी दूरदराज के गांव का खयाल आने पर एक तस्वीर उभरती है. पूरे गांव में पक्की सड़कें, हर घर में पानी का कनेक्शन, दूधिया स्ट्रीट लाइटों से जगमगाती गलियां, प्राइमरी से लेकर इंटर तक अच्छे स्कूल-कॉलेज, महापुरुषों की प्रतिमाओं से सजे चौराहे और स्थानीय लोगों को सुकून देता यहां का वातानुकूलित पंचायत भवन. यानी वह हर सुख-सुविधा, जो किसी अच्छे शहर में भी मयस्सर नहीं होती.

पिपलांत्री में विकास की जो इबारत लिखी जा रही है, उसकी कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है. तक़रीबन 6-7 साल पहले तक गांव वाले नहीं जानते थे कि पंचायत का मतलब क्या होता है अथवा पंचायत द्वारा गांव के विकास के लिए कोई काम कराए जा भी रहे हैं या नहीं. चूंकि यह गांव संगमरमर की पहाड़ियों पर बसा है और इसके चारों ओर बड़े पैमाने पर संगमरमर के खनन का काम होता है. खनन के दौरान निकलने वाले मलबे को गांव में ही डाला जाता था, जिससे यहां न केवल पत्थरों के मलबे के पहाड़ बन रहे थे, बल्कि गांव की ज़मीन और आबोहवा भी ख़राब हो रही थी. गांव वालों ने तो इसे जैसे अपनी नियति ही मान लिया था. पंचायत की बागडोर पिछले 3 दशकों से एक ही परिवार के हाथों में थी. वर्ष 2005 में जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो पंचायत की बागडोर गांव के ही नौजवान श्याम सुंदर पालीवाल के हाथ में आ गई.

कैसे बदला पिपलांत्री

श्याम सुंदर पालीवाल ने सरपंच बनते ही सबसे पहले पंचायत घर को दुरुस्त कराया. पालीवाल बताते हैं, चूंकि पंचायत घर में गांव के हर वर्ग के लोग आते हैं. यहां बैठकर लोगों को सुकून मिले, इसलिए हमने इसकी इमारत को दुरुस्त कराया, एयर कंडीशनर लगवाया, आरामदायक कुर्सियों-सुंदर फर्नीचर एवं बिजली-पानी की व्यवस्था की. यानी हमने पंचायत को सभी सुविधाओं से लैस कराया. पिपलांत्री में राजस्थान का पहला वातानुकूलित पंचायत घर है.

ग्रामसभा बनी विकास का आधार

पालीवाल बताते हैं, गांव में समस्याओं का अंबार लगा था. काम बहुत करने थे, लेकिन काम कहां से और कैसे शुरू करें, इसके लिए मैंने ग्रामसभा का सहारा लिया. शुरुआत हुई शिक्षा में सुधार से. पंचायत घर से शुरू हुई गांव के विकास की यात्रा स्कूल-कॉलेज, सड़क, पानी एवं स्ट्रीट लाइट से होती हुई आज तक बदस्तूर जारी है.

जनता की भागीदारी

पिपलांत्री में ख़ास बात यह है कि यहां के हर काम में गांव के लोग जुड़े हुए हैं. मसलन यहां स्ट्रीट लाइटें सड़क पर किसी खंभे पर न लगकर घरों के बाहर लगी हैं. उनका कनेक्शन घर के मीटर से है. स्ट्रीट लाइट के बिजली ख़र्च से लेकर रखरखाव तक पूरी ज़िम्मेदारी संबंधित घर पर है. जो परिवार स्ट्रीट लाइट का रखरखाव नहीं करता, उसके घर से वह लाइट उतरवा ली जाती है.

सबका ख्याल

पिपलांत्री में मानवीयता की भी कई मिसालें हैं. गांव में कई स्थानों पर सोलर पंप लगे हैं. गांव वालों की सलाह पर वहां पशुओं के लिए पानी की हौदियां बनवाई गईं. एक आदमी ने सलाह दी कि इन हौदियों में जब गिलहरी और चूहा जैसे छोटे जीव पानी पीने के लिए आते हैं तो वे अक्सर पानी में गिर जाते हैं और निकलने का रास्ता न होने के कारण मर जाते हैं. अब इसके लिए हर हौदी में छोटी-छोटी सीढ़ियां बनवा दी गई हैं.

पेड़ मेरा भाई

पत्थरों के इस गांव में लहलहाती हरियाली और झूमते पेड़ सरकार द्वारा चलाई जा रही पर्यावरण बचाने की मुहिम के लिए एक प्रेरक मिसाल हो सकते हैं. यहां पेड़ लगाना पर्यावरण के लिए महज़ खानापूर्ति नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है, स्नेह है. गांव वाले अब तक एक लाख से भी ज़्यादा पेड़-पौधे लगा चुके हैं. इसमें गांव की महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है. गांव में हर किसी के नाम से एक पेड़ लगा हुआ है. उसकी सिंचाई, काट-छांट और देखभाल की ज़िम्मेदारी उसी पर है. गांव में जब किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार के लोग उसकी याद में 11 पेड़ लगाते हैं और हमेशा के लिए उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी संभालते हैं. जब किसी घर में लड़की का जन्म होता है तो ग्राम पंचायत द्वारा उस लड़की के नाम 18 साल के लिए 10 हज़ार रुपये की धनराशि जमा की जाती है, मगर लड़की के मां-बाप द्वारा तब तक हर साल 10 पौधे रोपे जाते हैं. इस तरह लड़की के ब्याह लायक़ कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और गांव को 180 पेड़ मिल जाते हैं. पेड़ों को बचाने के लिए गांव में एक अनोखी मुहिम चलाई गई है. रक्षाबंधन के दिन गांव की महिलाएं पेड़ों को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधती हैं और उनकी सुरक्षा का वचन देती हैं. श्याम सुंदर पालीवाल बताते हैं कि पेड़ लगाने वक़्त कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है. ज़्यादातर फलदार पौधे लगाए जाते हैं, ताकि जब ये पेड़ बनकर फल दें तो गांव की ग़रीब महिलाएं उन फलों को बेचकर कुछ पैसे कमा सकें. गांव में बड़े पैमाने पर एलोवेरा यानी ग्वारपाठा लगाया जा रहा है. गांव की हर पहाड़ी और हर रास्ते में एलोवेरा लगा है. पंचायत की योजना है कि यहां एलोवेरा जूस का प्लांट लगाकर ख़ुद ही उसकी बिक्री की जाए. इस पंचायत के सचिव जोगेंद्र प्रसाद शर्मा की नियुक्ति यहां कुछ महीने पहले ही हुई है. वह बताते हैं कि जबसे हम इस गांव में आए हैं, पौधे ही लगवा रहे हैं.

एनीकट यानी जीवनधारा

बरसात के समय पहाड़ियों से होकर नीचे बेकार बहने वाले पानी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए गांव में कई जगह एनीकट बने हैं. आज इन्हीं एनीकटों की बदौलत गांव के हर घर में पेयजल का कनेक्शन है.

पारदर्शिता

वैसे तो पंचायत के हर काम में गांव के हर आदमी की भागीदारी है, मगर फिर भी सभी जानकारियों को गांव की वेबसाइट पिपलांत्री डॉट कॉम पर समय-समय पर डाला जाता है. श्याम सुंदर पालीवाल अब पूर्व सरपंच बन चुके हैं, मगर वह आज भी हर काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. साफ-सफाई की बदौलत पिपलांत्री को निर्मल ग्राम पंचायत का खिताब मिल चुका है. पिपलांत्री ग्राम पंचायत से 7 और गांव जुड़े हैं. पिपलांत्री की तरह उन सभी गांवों में भी पक्की सड़कें, सामुदायिक शौचालय और पेयजल कनेक्शन हैं.

खेल-खेल में ऊर्जा उत्पादन

गांव के लोग पर्यावरण को लेकर कितने जागरूक हैं, इस बात का अंदाज़ा यहां मौजूद सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटरपंप और झूला पंपों को देखकर लगाया जा सकता है. यहां स्कूलों में ज़मीन से पानी निकालने और उसे टंकी में इकट्ठा करने के लिए झूलों की मदद ली जाती है. एक स्कूल में चकरी वाला झूला लगा है. बच्चे उसे घूमाते हैं और उस पर झूलते हैं. झूलों से खींचे गए पानी को स्कूल में पीने और साफ-सफाई आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

आसान नहीं थी डगर

गांव में संगमरमर के पहाड़ हैं. यहां कई बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा खनन का काम हो रहा है. वे सारा मलबा गांव की ज़मीन पर डालती आ रही थीं. श्याम सुंदर पालीवाल ने गांव वालों को साथ लेकर कंपनियों का विरोध किया. चूंकि कंपनियों के पास ग्राम पंचायत और प्रशासन की एनओसी थी, इसलिए पालीवाल को पूर्व सरपंच और स्थानीय प्रशासन से भी टकराना पड़ा. आख़िरकार जीत गांव वालों की हुई. आज इन खदानों से ग्राम पंचायत को आमदनी भी होने लगी है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

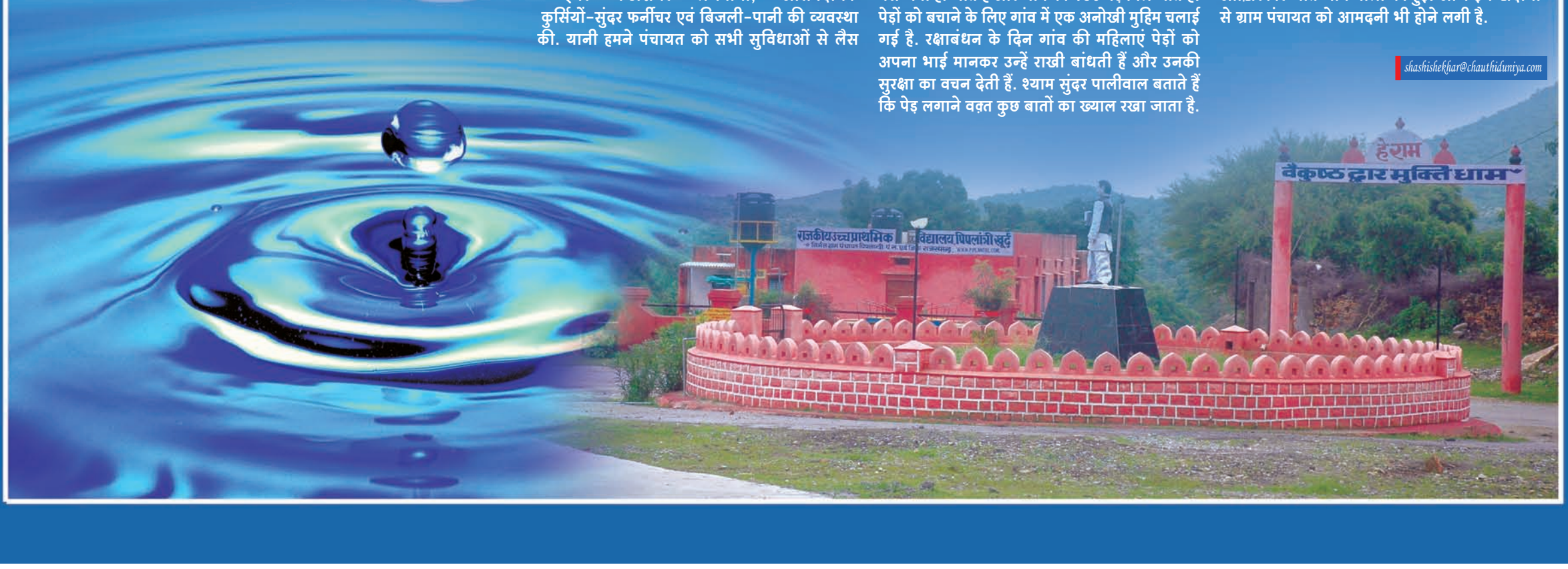

ओबामा अमेरिका में भारत के सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं. चुनाव ख़त्म होने के बाद अमेरिकी संरक्षणवादिता और आर्थिक मामलों में अन्य देशों पर दबाव डालने की नीति और ज़्यादा जोर पकड़ेगी.

मेघनाद देसाई

ओबामा भविष्य की जरूरत हैं

एक साल में कितना कुछ बदल जाता है. पिछले साल जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाशिंगटन पहुंचे थे और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी अगवानी की थी तो हर भारतीय का दिल उत्साहित हो उठा था . कुछ बहुत बड़ा हासिल होने की भावना से नई उम्मीदें अंगड़ाइयां ले रही थीं. पहले जॉर्ज बुश और उसके बाद ओबामा ने हमारे प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उनकी इस पहल में सच्चाई झलक रही थी. यह इस बात का परिचायक था कि क़रीब पचास पहले जब शीत युद्ध अपने चरम पर था और आइजन हावर भारत आए थे, उसके बाद से लेकर अब तक भारत वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक अलग मुक़ाम हासिल कर चुका था, लेकिन पिछले सप्ताह भारत आए ओबामा और एक साल पहले के ओबामा में आकाश–पाताल का फ़र्क़ है. अब वह अपनी परछाई मात्र बनकर रह गए हैं. जुलाई महीने में भारत आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की तरह ओबामा भी रक्षात्मक होने का आभास देते रहे. यदि उनकी क़िस्मत अच्छी होगी तो मध्यावधि चुनावों के परिणाम उनके लिए उतने नुक़सानदायक नहीं होंगे, जितनी उम्मीद की जा रही है. यदि ऐसा हुआ तो सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत बना रहेगा, लेकिन प्रतिनिधि सभा में पार्टी अपना बहुमत खो देगी. लेकिन यह ओबामा के लिहाज़ से सबसे अच्छा परिणाम होगा. अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनके मुताबिक़ अमेरिकी मतदाता ओबामा के ख़िलाफ़ अपने गुस्से का जमकर इज़हार करेंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों सदनों में अपना बहुमत खो देगी.

ओबामा की हालत एक बड़े विरोधाभास के रूप में हमारे सामने है. जॉन केनेडी अथवा यहां तक कि बिल क्लिंटन के मुक़ाबले उनकी उपलब्धियां काफी अच्छी हैं. संसद में उनके कार्यकाल में पारित हुए नए क़ानूनों की संख्या बड़ी है और उनका दायरा भी विस्तृत है. स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बिल को संसद की अनुमति दिलाने में कई पूर्व राष्ट्रपतियों को सफलता नहीं मिली और यह ओबामा की सबसे बड़ी उपलब्धि है. वॉल स्ट्रीट की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए भी उन्होंने कुछ कड़े क़ानून बनाए हैं. इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार नीचे की ओर जा रही है. हालत यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार चुनाव के दौरान उनके साथ दिखना नहीं चाहते. उनके ख़िलाफ़ एक घृणा जैसा माहौल है. एक ऐसी भावना, जो अमेरिकी जनता आमतौर पर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ प्रदर्शित करती है, जिन्हें वह अमेरिका विरोधी मानती है. एक चौथाई अमेरिकी मतदाता समझते हैं कि वह मुसलमान हैं, हालांकि यह गलत सोच है. विश्व के सबसे ताक़तवर देश के नागरिक आज सदमे में हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि अमेरिका की वैश्विक महाशक्ति होने की हैसियत ख़तरे में है. उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा निस्संदेह चीन है, लेकिन भारत को भी अब कमज़ोर नहीं आंका जा सकता. ख़ुद ओबामा भी यह कह चुके हैं कि अमेरिका बंगलुरू के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहा है और आउटसोर्सिंग से अमेरिका में नौकरियों को ख़तरा है. ऐसे बयान एक कमज़ोर नेतृत्व की छवि पेश करते हैं.

इस सबके बावजूद ओबामा अमेरिका में भारत के सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं. चुनाव ख़त्म होने के बाद अमेरिकी संरक्षणवादिता और आर्थिक मामलों में अन्य देशों पर दबाव डालने की नीति और ज़्यादा जोर पकड़ेगी. देश की अर्थव्यवस्था अभी भी कमज़ोर है और इसकी संभावना कम है कि इसमें सुधार के लिए ओबामा कुछ खास कर पाने की हालत में होंगे. आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अमेरिका राजनीतिक रूप से पंगु होकर रह जाएगा और कांग्रेस राष्ट्रपति के हर काम में टांग अड़ाएगी. इंग्लैंड की तरह अमेरिकी जनता इतनी आसानी से अवसान को स्वीकार नहीं करेगी. वह एक ओर बाकी दुनिया से जमकर मुक़ाबला करेगी तो दूसरी ओर राष्ट्रपति ओबामा लगातार कम होती शक्ति के बावजूद कुछ करने की हालत में नहीं होंगे. अमेरिका का टी पार्टी मूवमेंट राजनीतिक दिवालिएपन और अतिवादिता की पराकाष्ठा है. इसके मुक़ाबले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कुछ नहीं. मुझे 1964 में राष्ट्रपति पद का

चुनाव याद आता है, जब रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह का शिकार हुए थे. हालांकि इस चुनाव में गोल्ड वाटर को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1980 में रोनाल्ड रीगन चुनाव जीतने में सफल रहे. इसके बाद अगले 28 सालों में 20 साल तक रिपब्लिकन पार्टी ही सत्ता में रही. यदि 2012 में ओबामा को सत्ता से बेदख़ल करने के लिए एक बार फिर टी पार्टी मूवमेंट की वापसी होती है तो इसके लिए ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है. एक ऐसा अमेरिका, जो अपनी घटती हैसियत को स्वीकार करने से इंकार करता हो और जहां दक्षिणपंथी ताक़तें जोर पर हों, अच्छी ख़बर नहीं है. अमेरिकी राजनीति से मध्यमार्गी तबका पहले ही लुप्त हो चुका है. एक ऐसा अमेरिका, जो स्वयं स्थिर नहीं है, जो दुनिया के बाक़ी हिस्सों में अपनी मर्जी से विरोधियों का चुनाव करता हो, लेकिन ख़ुद अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए गंभीर न हो, यह स्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती और आने वाले एक–दो दशक काफी कटुतापूर्ण हो सकते हैं.

जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नियोकंजर्वेटिव्स के पास एक विचारधारा थी, हालांकि उसकी दिशा ठीक नहीं थी. बुश के समर्थक दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था और उदारवादी अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे और इसके लिए किसी भी हद तक, यहां तक कि लड़ाई लड़ने को भी तैयार रहते थे. लेकिन टी पार्टी मूवमेंट के समर्थकों के पास न तो कोई विचारधारा है, न ही कोई वैश्विक नीति. सत्ता में आने पर उनकी कोशिश एक ईसाई धर्म समर्थक कट्टरवादी विदेश नीति थोपने की होगी, जिसमें एड्स रोधी अभियान के लिए कोई फंड नहीं होगा, फिलीस्तीन के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं होगी, चीन और हो सकता है कि भारत के ख़िलाफ़ भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार होगा. वे संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कोई अहमियत नहीं देते और बहुपक्षीय कूटनीति के भी ख़िलाफ़ हैं. इसका नतीजा यह होगा कि अमेरिका अपने आप में सिमट कर रह जाएगा और यह बाक़ी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा. संभव है, आज ओबामा को हमारी ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन 2012 के बाद ओबामा का अपने पद पर बने रहना हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है.

feedback@chauthiduniya.com

डेविड हेडली : भारत बनाम अमेरिका-पाकिस्तान

राजीव रंजन तिवारी

पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली के बारे में परत दर परत जो खुलासे हो रहे हैं, वह निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं. उक्त खुलासे खासकर भारत को सचेत करते हैं कि जिस तरह वह पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता, उसी तरह उसे अमेरिका को भी संदिग्ध निगाहों से देखना चाहिए. ब्रिटेन के एक अख़बार में छपी रिपोर्ट को यदि सही मानें तो पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली के बारे में अमेरिकी अधिकारियों को पता था कि उसके संबंध लश्कर–ए–तैयबा के साथ हैं. वह भारत में किसी आतंकवादी कार्रवाई का षड्यंत्र रच रहा है. यद्यपि अमेरिका ने भारत को यह जानकारी तो दी कि लश्कर–ए–तैयबा भारत के किसी बड़े शहर पर हमला कर सकता है, किंतु उसने यह नहीं बताया कि वह कौन आदमी है, जो इस आतंकी संगठन की मदद कर रहा है. यदि अमेरिका हेडली के बारे में बता देता तो शायद भारत उसे पहले ही दबोच लेता और मुंबई की भयावह आतंकी त्रासदी होने से बच जाती, क्योंकि हेडली उस वक़्त भारत में ही था और अपना जाल बिछाने में लगा था. अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में यह बात और भी अहम हो जाती है.

समझा जा रहा है कि भारत सरकार अमेरिका के ऐसे व्यवहार से चकित है, किंतु अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा को ध्यान में रखते हुए उसने चुप्पी साध ली. हो सकता है कि भविष्य में भारत यह सवाल अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष जरूर उठाए और उठाना भी चाहिए. हेडली ने अमेरिका में उसके साथ पूछताछ करने के लिए गए भारतीय अधिकारियों को बताया था कि वह हमले की तैयारियों के बारे में आईएसआई के अधिकारियों को लगातार सूचनाएं देता रहा.

हेडली के बारे में यह जानकारी उसकी दो पत्नियों ने ही अमेरिका को दी थी. हेडली की शायद तीन पत्नियां हैं, जिनमें एक अमेरिका एवं एक मोरक्को की रहने वाली है. मोरक्को वासी पत्नी ने पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को बताया था कि उसके पति के उन पाकिस्तानी आतंकियों से संबंध हैं, जो भारत में कोई बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे हैं. इसी तरह हेडली की अमेरिकी पत्नी ने अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के अधिकारियों से संपर्क करके उसके बारे में यह सूचना दी. इन महिलाओं के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने उनकी सूचनाओं को कोई महत्व नहीं दिया और उल्टे उन्हें वहां से भगा दिया. अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसी महत्वपूर्ण सूचना को भी गंभीरता से नहीं लिया, यह आश्चर्यजनक है. इससे तो उन्हीं ख़बरों की पुष्टि होती है कि हेडली एक तरह से डबल एजेंट था. वह पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के साथ अमेरिका के लिए भी काम कर रहा था और शायद अमेरिकी अधिकारियों को यह बात पहले से ही मालूम थी कि हेडली के पाकिस्तानी गुप्तचर संगठन आईएसआई से भी संबंध हैं. यदि ऐसा न होता तो वे ऐसी गंभीर सूचना देने वाली उसकी पत्नियों को भागने के लिए न कहते.

समझा जा रहा है कि भारत सरकार अमेरिका के ऐसे व्यवहार से चकित है, किंतु अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा को ध्यान में रखते हुए उसने चुप्पी साध ली. हो सकता है कि भविष्य में भारत यह सवाल अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष जरूर उठाए और उठाना भी चाहिए. हेडली ने अमेरिका में उसके साथ पूछताछ करने के लिए गए भारतीय अधिकारियों को बताया था कि वह हमले की तैयारियों के बारे में आईएसआई के अधिकारियों को लगातार सूचनाएं देता रहा. उसे इस तरह के दो अभियानों के लिए आईएसआई की तरफ़ से भुगतान भी हुआ था, इसलिए लगातार रिपोर्ट देना ज़रूरी था. ब्रितानी अख़बार की रिपोर्ट के बाद अब इसमें संदेह नहीं रह गया है कि मुंबई हमला आईएसआई की अपनी योजना का परिणाम था, जिसमें हेडली उसका मुख्य सहयोगी था. यद्यपि पाकिस्तान लगातार इस बात से इंकार करता आ रहा है, लेकिन अब उसकी सारी चालबाज़ी उजागर हो चुकी है. अमेरिका भी हेडली को लेकर जैसे दोहरे खेल खेल रहा है, उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है. अब भारत को हेडली के संदर्भ में अमेरिका से साफ कह देना चाहिए कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ यदि वह उसके साथ सहयोग करना चाहता है तो उसे इस तरह तथ्यों को छिपाने से बाज आना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा और सबसे नज़दीकी रणनीतिक साझीदार बताता है. अमेरिकी अधिकारी यह कहते कभी नहीं थकते कि भारत का अमेरिका के लिए विशेष महत्व है. यहां तक कि ओबामा की भारत यात्रा का कार्यक्रम भी पूरे तीन दिनों का रखा गया. राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक उन्होंने किसी देश की यात्रा में वहां इतना समय नहीं बिताया. कहा तो यह भी जा रहा है कि ओबामा ने व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का प्रथम राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत किया और उनके सम्मान में विशिष्ट भोज का आयोजन किया. एक तरफ़ भारत को इतना

सम्मान और दूसरी तरफ़ भारत के सबसे बड़े शत्रु पाकिस्तान के प्रति अति उदारतापूर्ण सैनिक सहायता! इन दोनों बातों के बीच तालमेल ढूंढना असंभव सा है. ओबामा की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए कई लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगी. बावजूद इसके तमाम भारतीयों को लगता है कि अमेरिका एक शातिर व्यापारी है, जो एक तरफ भारत को अरबों डॉलर के हथियार बेचता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सैनिक सहायता मुफ्त देता है. वह जानता है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता सीधे ज़िहादी संगठनों के पास पहुंचती है और उसे जो नए हथियार मिलते हैं, वे भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं. फिर भी अमेरिका का पाक के प्रति नरम रुख़ समझ से परे है. कहना गलत न होगा कि पाकिस्तान को अमेरिका से अधिक दूसरा और कौन जान सकता है. मुंबई हमले में आईएसआई की भूमिका एवं तालिबान को पाकिस्तानी सेना की मदद के बारे में दुनिया को भले देर से जानकारी मिली हो, लेकिन अमेरिका को यह सब पहले से पता है, फिर भी वह पाकिस्तान की सहायता बढ़ाता जा रहा है और उसे मोर्चे पर लगाए हुए है. कोई संदेह नहीं कि इसके पीछे उसकी कोई न कोई योजना जरूर होगी. ऐसी स्थिति में भारत को सचेत रहने की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

लापरवाही का नतीजा

01–07 नवंबर के अंक की आवरण कथा–पचास हज़ार बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार कौन ने काफी प्रभावित किया. लेखक ने एक बड़े मुद्दे पर बखूबी प्रकाश डाला है. यह सरासर सरकार की लापरवाही का नतीजा है. इस संदर्भ में शासन–प्रशासन की चुप्पी वाकई चिंताजनक है. जनस्वास्थ्य की रक्षा सरकार का कर्तव्य है.

–कृष्ण कुमार जैन, *ई-मेल से.*

नेक सलाह के लिए साधुवाद

25–31 अक्टूबर के अंक की कवर स्टोरी–किसी भी क़ीमत पर इन्हें वोट मत दीजिए पढ़कर मन में संतोष हुआ कि अभी भी कुछ लोग बाक़ी हैं, जिन्हें ख़रीदा नहीं जा सकता. बिहार की भोली–भाली जनता को राज्य की राजनीति को स्वच्छ बनाने की दिशा में चलने की नेक सलाह देने के लिए साधुवाद. यदि दागदार दामन वालों एवं सौदेबाज़ बहुरूपियों की नाव डूब जाए तो एक हद तक राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम लग सकती है. बिहार में सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों एवं सामान्य वर्ग की स्थिति भी काफी खराब है.

–डॉ. सुशील कुमार गुप्त, *खगड़िया, बिहार.*

सराहनीय प्रयास

आलेख–घूंघट विकास में बाधा नहीं पढ़ा, अच्छा लगा. यह जानना सुखद रहा कि अब हमारे गांवों में भी कंप्यूटर जैसी तकनीकी शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है और लड़कियां बिना किसी संकोच के इस शिक्षा का लाभ उठा रही हैं. शेखावाटी समेत समूचे राजस्थान में मोरारका फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं. वास्तव में ऐसी संस्थाएं ही हमारे गांवों का सच्चा विकास कर सकती हैं.

–खादीजा सिद्दीकी, *ई-मेल से.*

केऊ सुनवइय्या नाहीं...

केऊ सुनवइय्या नाहीं, रोओ चाहे गाओ
प्रमाणपत्र चाही तो दौरि–दौरि आओ.
तू समस्या से त्रस्त, वै बटोरै मा व्यस्त
सूर्य निकरे आओ, जाओ सूर्य अस्त.
बहुतेरे प्रमाणपत्र, कौन प्रमाण चाही
बीपीएल कार्ड केऊ पूछत नाहीं.
तोहरी समस्या से ई शासनतंत्र खड़ा है
हटे न गरीबी, खूंटा गहिरे गड़ा है.

–शिवराम शुक्ल, *इनायत नगर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश.*

औचित्यहीन बदलाव

प्रशासनिक परीक्षा में बदलाव: हकीकत की अनदेखी शीर्षक से प्रकाशित आलेख पढ़ा. केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूप में बदलाव एक बड़ा फ़ैसला है. यह कहना कतई ग़लत नहीं है कि सुधार के लिए अपेक्षित आधारों को ध्यान में नहीं रखा गया. सरकार को कोठारी कमेटी, सतीश चंद्रा कमेटी एवं वाई के अलग कमेटी की सिफारिशों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके बिना बदलाव का कोई औचित्य समझ में नहीं आता. इस फ़ैसले से लाभ एक सीमित तबके को होगा, जबकि इसका नकारात्मक असर एक बहुत बड़े तबके पर पड़ेगा.

–सौम्या सक्सेना, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

कल किसने देखा

निर्माता–निर्देशक: कल, आज और कल आलेख काफी सारगर्भित है. लेखक ने विषय पर वाकई मेहनत की है. वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है, इसलिए जो आज है, वह कल रहेगा भी, यह नहीं कहा जा सकता. शायद इसी सत्य को ध्यान में रखकर कहा गया है कि कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर.

–समीर सत्संगी, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

बेमिसाल सचिन

आलेख–सचिन तेंदुलकर: सिंपली द बेस्ट शीर्षक तले प्रकाशित आलेख ने प्रभावित किया. भारतीय क्रिकेट जगत को विश्व पटल पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सचिन का खासा योगदान है. वह सिर्फ़ उम्दा खिलाड़ी ही नहीं, उम्दा इंसान भी हैं. वह पिछले 21 वर्षों से क्रिकेट की दुनिया में सक्रिय हैं और नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. देश को उन पर नाज है.

–लक्ष्मी नारायण, *पालम कालोनी, नई दिल्ली.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

बिहार पूरे देश को सबक दे

हम क्यों बार-बार बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं. यह सवाल उन राजनैतिक व्यक्तियों ने हमसे पूछा है, जो ख़ुद अपने दलों के आलोचक हैं. हालांकि उनका कहना है कि हमारी अपील बिल्कुल सही है और इसका बिहार के लोगों पर असर भी हो रहा है, क्योंकि जनता बातचीत में अपराधियों, दागियों और बाहुबलियों के ख़िलाफ़ खुलकर बात करने लगी है तथा उनके खिलाफ अपना गुस्सा प्रगट करने लगी है, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को चुनाव में खड़ा किया है. मज़े की बात है कि राजनैतिक दलों द्वारा दागियों और बाहुबलियों को चुनाव में खुलकर खड़ा करने की भी ये समझदार राजनैतिक लोग आलोचना करने में सबसे आगे हैं.

बिहार के राजनैतिक दलों ने बाहुबलियों को टिकट देने में इस बार सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं. पिछले उप चुनावों में नीतीश कुमार ने बाहुबलियों और विधायकों तथा सांसदों के नज़दीकी रिश्तेदारों को टिकट देने में सख्त रुख़ अपनाया था, जिसकी एक वजह बनी कि वह उप चुनावों में हार गए. इस बार नीतीश कुमार ने ऐसा कोई रुख़ नहीं अपनाया, उन्होंने परिवारवाद और बाहुबली वाद को अपने गले से खुलकर चिपका लिया. भाजपा ने दागी उम्मीदवारों को जमकर टिकट दिए तथा अपनी वह छवि तोड़ दी, जिसकी वजह से वह अन्य राजनैतिक दलों से कुछ अलग जानी जाती थी. बेटों, पत्नियों और रिश्तेदारों को जमकर टिकट दिलवाए गए. पराकाष्ठा तो तब हो गई, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी पी ठाकुर ने अपने बेटे को टिकट न मिलने के विरोध में पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया. भाजपा ने गिड़गिड़ा कर उन्हें मनाया तथा वादा किया कि राज्यसभा में उनके बेटे को भेज दिया जाएगा. सी पी ठाकुर समझदार व्यक्ति माने जाते हैं, बड़े डॉक्टर हैं, जनता से उनका रिश्ता है. उन्होंने लोकनायक जय प्रकाश का भी काफी दिनों तक इलाज किया है.

कोई सीमा ही नहीं रही. रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने भाई को कांग्रेस से टिकट दिलवा दिया. किसी भी पार्टी का सांसद हो, अपनी पार्टी न सही, दूसरी सही, लेकिन टिकट दिलवाना उन्होंने अपनी इज़्ज़त का पैमाना बना लिया. सारे सिद्धांत बिहार चुनाव में हवा हो गए हैं. एक ही सिद्धांत बचा कि किसी तरह परिवार के लोगों को चुनाव में खड़ा करो और विधानसभा में पहुंचाओ. जिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने सालों साल पार्टी के लिए ख़ून-पसीना बहाया, उन्हें आख़िरी क्षण में आसमान दिखा दिया गया. कुछ प्रमुख नाम, जिनमें पहला रामविलास पासवान का नाम है, जिनके परिवार के छह लोग चुनाव लड़ रहे हैं. जेडीयू के मुन्ना शुक्ला की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं. पप्पू यादव की पत्नी पहले सांसद थीं, अब विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं. महेश्वर हज़ारी जेडीयू के सांसद हैं, उनके पिता और भाभी चुनाव लड़ रहे हैं. कौशल यादव और उनकी पत्नी को अलग-अलग क्षेत्रों से जेडीयू लड़ा रही है. जेडीयू के सांसद मोनाज़िर हसन की पत्नी आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं. धर्मपाल सिंह आरजेडी से तो उनके भाई बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं. जेडीयू के सुशील सिंह के भाई आरजेडी के उम्मीदवार हैं. बेगूसराय के उपेंद्र सिंह एलजेपी के उम्मीदवार हैं तो उनके पुत्र भाजपा के उम्मीदवार हैं. ऐसे लगभग चालीस से पचास लोग हैं, जो विधानसभा में किसी तरह घुसना और अपने परिवार को घुसाना चाहते हैं. न ये नेता समझ रहे हैं और न राजनैतिक दल समझ रहे हैं कि लोकतंत्र का इस तरह का दुरुपयोग आम जनता के मन में दु:ख, कुंठा और निराशा पैदा कर सकता है. इसका परिणाम बड़े पैमाने पर अशांति, अपराध और नक्सलवाद की बढ़ोत्तरी की जड़ बनेगा.

मोटे तौर पर अगर प्रतिशत में देखें तो भाजपा ने 68 प्रतिशत, लोजपा ने 60 प्रतिशत, जेडीयू ने 55 प्रतिशत, आरजेडी ने 60 प्रतिशत, बीएसपी ने 42 प्रतिशत और कांग्रेस ने 40 प्रतिशत अपराधी, दाग़दार या बाहुबली कहे जाने वाले उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. राजनीति साफ-सुथरी रहे, अब यह उद्देश्य है ही नहीं. विधानसभा में जीत ही पहला लक्ष्य है. शायद ही कोई बड़ा अपराधी या दागी या बाहुबली बचा हो, जो किसी न किसी पार्टी से चुनाव न लड़ रहा हो. साढ़े चार सौ से ज्यादा इसी नस्ल के उम्मीदवार हैं, अगर जनता ने गलती से वोट दे दिए तो बिहार विधानसभा की तस्वीर बड़ी भयावह बनेगी. हालांकि पांच साल पहले हुए चुनाव में देश को कई तोहफे बिहार ने दिए थे. जिस बिहार ने बूथ कैप्चरिंग की संस्कृति सारे देश में भेजी, उसी बिहार ने दो हजार चार और दो हजार पांच में सबसे साफ-सुथरे चुनाव भी कैसे होते हैं, सारे देश को दिखाया. इसमें के जे राव का बहुत बड़ा योगदान था. इन चुनावों में बिहार की जनता की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है. चुनावों में बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है, लेकिन अपराधी और परिवारवाद पर लगाम लगाना बिहार की जनता के हाथ में है, क्योंकि बिहार में किसी भी तरह विधानसभा में पहुंचो और सरकार पर क़ब्ज़ा करो की नीति पर इन दिनों काम हो रहा है और इसके लिए जाति और पैसे का बेशर्मी और फूहड़ता से इस्तेमाल हो रहा है.

बिहार के राजनैतिक दलों ने बाहुबलियों को टिकट देने में इस बार सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं. पिछले उप चुनावों में नीतीश कुमार ने बाहुबलियों और विधायकों तथा सांसदों के नज़दीकी रिश्तेदारों को टिकट देने में सख्त रुख़ अपनाया था, जिसकी एक वजह बनी कि वह उप चुनावों में हार गए. इस बार नीतीश कुमार ने ऐसा कोई रुख़ नहीं अपनाया, उन्होंने परिवारवाद और बाहुबली वाद को अपने गले से खुलकर चिपका लिया.

पाकिस्तान में दो सौ के आसपास परिवार हैं, जिनके कब्जे में वहां की राजनीति है. उन्हीं के हाथ में फौज है, इसीलिए आज पाकिस्तान में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. वहां के आतंकवाद का भी बड़ा कारण यही है. पाकिस्तान में आशा ही खत्म हो गई है. वहां के नौजवानों को लगता है कि राजनीति के जरिए कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति पर उन्हीं का कब्जा है, जो बदहाली के जिम्मेवार हैं. क्या यही बिहार में भी होगा या बिहार से सीख लेकर देश के दूसरे प्रदेशों में भी होगा? राजनीति से एक ही आशा होती है कि यदि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले, जो इसके पात्र हैं तथा जिनकी तकलीफ है, तो समस्याओं के हल की आशा बनी रहती है. बिहार की जनता पर इस बात की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें न जिताए, जो दागी या अपराधी हैं और न उन्हें जिताए, जो परिवारवाद में आते हैं. अगर परिवार के लोगों को चुनाव लड़ना है तो उन्हें पहले जनता के बीच या पार्टी में काम करना चाहिए. राजीव गांधी इसका एक उदाहरण हैं, जिन्होंने काफी साल पार्टी में काम किया. पर जिन्होंने एक भी दिन काम नहीं किया, केवल पिता या माता या सास-ससुर की वजह से विधानसभा में जाना चाहते हैं, उन्हें हर हाल में हराना चाहिए. एक ही सिद्धांत, जो अपराधी हैं, वे विधानसभा में न जाएं तथा जो परिवारवाद की उपज हैं, विधानसभा का मुंह न देख पाएं.

इसलिए हम बिहार में अपील कर रहे हैं कि बाहुबलियों, दागियों, अपराधियों और परिवारवाद फैलाने वाले लोगों को हारना चाहिए. चुनाव के महत्वपूर्ण चरण खत्म होने वाले हैं. हमारा बिहार की जनता से अनुरोध है कि वह ऐसे तत्वों को, जो लोकतंत्र का दुरुपयोग कर उसके हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें हरा कर सारे देश को नया रास्ता दिखाए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

हमारा गणतंत्र कहां जा रहा है?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद प्रकरण में सुनाया गया हालिया निर्णय भारत के न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर है. एक अर्थ में यह बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की घटना का समापन पर्व है, क्योंकि अदालत ने इस ग़ैर क़ानूनी कृत्य को विधिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस निर्णय का न तो भारतीय संविधान में निहित मूल्यों से कोई लेना-देना है और न ही संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों से. इस निर्णय की जड़ें भारत के क़ानून में ही नहीं हैं. यह सही है कि भारत के अधिकांश लोग इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचे. जो आलोचना हुई भी, वह अत्यंत दबी ज़ुबान में हुई. ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह एक संतुलित निर्णय है, जिससे सभी पक्ष प्रसन्न और संतुष्ट हैं. यह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर निर्णय नहीं दिया जा सकता था.

निर्णय के पहले देश के वातावरण में तनाव, अनिश्चितता एवं आशंकाएं व्याप्त थीं. हिंदुओं को डर था कि अगर हिंसा होती है और उसके शिकार वे या उनके प्रियजन होते हैं तो यह एक बड़ी मुसीबत होगी. मुस्लिम भी डरे हुए थे. उन्हें डर यह था कि उनकी संपत्ति को नुक़सान पहुंचाया जाएगा और उनकी जानें जाएंगी. सौभाग्यवश उन तत्वों ने, जो विभिन्न दंगा जांच आयोगों के अनुसार हिंसा के लिए ज़िम्मेदार रहे हैं, निर्णय का जश्न मनाने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, जैसा कि उन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद किया था. इस बार शायद संघ परिवार और समाज का सांप्रदायिक तबका 1992 की तुलना में कहीं अधिक ख़ुश था, परंतु उसने अपनी ख़ुशी को प्रगट करने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया. सतही तौर पर देखने से ऐसा लग सकता है कि मुसलमानों ने इस निर्णय के बाद चैन की सांस ली है, क्योंकि उन्हें 1992 जैसी हिंसा नहीं झेलनी पड़ी. लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अदालत के निर्णय ने उन्हें निराश किया है. उन्हें ऐसा लगा कि

कांग्रेस की प्रतिक्रिया अत्यंत शर्मनाक रही. हम सब जानते हैं कि कांग्रेस सांप्रदायिक हिंसा के तांडव की मूकदर्शक रही है. कई मौक़ों पर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों एवं शीर्ष नेताओं ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. कांग्रेस ने निर्दोषों का ख़ून बहते चुपचाप देखा है.

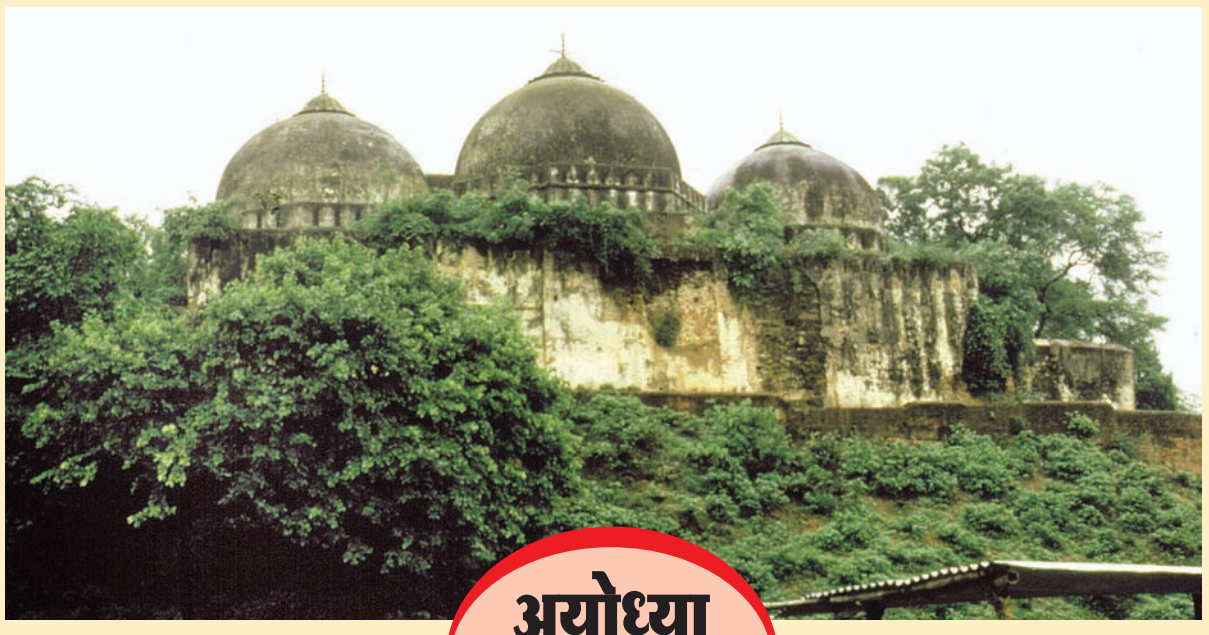

अयोध्या निर्णय

यह निर्णय हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में पहला क़दम है. मुसलमानों के एक बड़े तबके का मानना है कि क़ानून भी उनके न्यायपूर्ण अधिकार की रक्षा नहीं कर सका. गहरी कुंठा, गुस्सा और निराशा का भाव इस निर्णय पर उन मुसलमानों की प्रतिक्रिया का केंद्रीय तत्व है, जिन्होंने अपनी बात कहने की हिम्मत दिखाई. सांप्रदायिक दुष्प्रचार के ज़रिए हाशिए पर धकेल दिए गए मुसलमानों का एक बड़ा तबका अपना मन मसोस कर, आइए हम आगे बढ़ें के आह्वान को तवज्जो दे रहा है. दोनों पक्षों के बीच का विरोधाभास स्पष्ट है. जहां एक पक्ष को वह मिल गया है, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था. वहीं दूसरे पक्ष में यह भावना प्रबल है कि उसके साथ एक बार फिर धोखा हुआ है. संघ परिवार उत्साहित है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण का पथ प्रशस्त हुआ और उसकी मुसलमानों से यह अपेक्षा है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की पूर्ति में वे सहयोग करें. स्पष्टत: यह राष्ट्रीयता की भिन्न एवं परस्पर विरोधी परिभाषाओं का मामला है. जिस राष्ट्रीयता की बात संघ परिवार कर रहा है, वह धर्म निरपेक्ष प्रजातंत्र, स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों एवं हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों की विरोधी है. वैसे भी हम आरएसएस जैसे संगठन से और कोई अपेक्षा कर भी कैसे सकते हैं? संघ तो आधुनिक वेशभूषा में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का पैरोकार है. संघ की दृष्टि में अदालत के निर्णय ने 1949 में विवादित ढांचे में मूर्तियों की स्थापना और 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाने के घोर ग़ैर क़ानूनी कृत्यों को विधिक मान्यता प्रदान कर दी है. भारतीय समाज ने भी इन दोनों जघन्य अपराधों को अपनी स्वीकृति दे दी है. कांग्रेस की प्रतिक्रिया अत्यंत शर्मनाक रही. हम सब जानते हैं कि कांग्रेस सांप्रदायिक हिंसा के तांडव की मूकदर्शक रही है. कई मौक़ों पर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों एवं शीर्ष नेताओं ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. कांग्रेस ने निर्दोषों का ख़ून बहते चुपचाप देखा है.

हालिया निर्णय पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया दुलमुल रही है. कांग्रेस सिर्फ़ इसलिए ख़ुश है, क्योंकि देश में शांति बनी हुई है. उसके लिए इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है कि यह शांति सौहार्द्र से नहीं उपजी है, बल्कि आमजनों के एक बड़े तबके द्वारा अन्याय और अपमान के घूंट को चुपचाप पी जाने का नतीजा है. कांग्रेस ने तो संवैधानिक मूल्यों एवं क़ानून के राज के पक्ष में बोलना बहुत पहले ही छोड़ दिया था. उसके लिए तो चुनावी गणित अधिक महत्वपूर्ण है. सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता कांग्रेस की अवसरवादी सांप्रदायिक नीतियों से मेल नहीं खाती. इन सबके बावजूद इस देश में ऐसे लोग हैं, जो इस निर्णय से व्यथित हैं और इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं. वे यह मानते हैं कि यह निर्णय बहुवाद, प्रजातंत्र एवं भारतीयता के विरुद्ध है. नौकरशाही एवं राज्य तंत्र के अन्य हिस्से संतुष्ट हैं, क्योंकि सतही तौर पर ही सही, परंतु देश में शांति बनी हुई है. उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि न्याय हो रहा है या नहीं, देश की व्यवस्था क़ानून के अनुरूप चल रही है या नहीं. वैसे भी व्यवस्था के एक बड़े हिस्से पर संकीर्ण सांप्रदायिक विचारधारा का रंग चढ़ गया है और उसने हिंदुत्व की विचारधारा को आत्मसात कर लिया है. भारतीय राज्य के इस्पाती ढांचे को घुन लग गया है. उसका एक छोटा हिस्सा तो खुलकर हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहा है और एक बड़ा हिस्सा प्रजातांत्रिक मूल्यों के क्षरण को चुपचाप देख रहा है. प्रजातांत्रिक मूल्यों के क्षरण के पीछे कई कारक हैं, जिनमें अनवरत जारी सांप्रदायिक दुष्प्रचार, वैश्वीकरण के कुप्रभाव एवं इनके कारण हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तन आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं.

जाहिर है, हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ है और वह यह है कि इन परिस्थितियों में भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? राजनैतिक नेतृत्व केवल सतही शांति से संतुष्ट है और उसे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि देश के सभी नागरिकों के साथ न्याय हो रहा है या नहीं. इससे भारतीय संविधान के मूल्यों और न्याय के सिद्धांतों के लिए गंभीर ख़तरा उत्पन्न हो गया है. अयोध्या मामले में अदालत का निर्णय और उस पर प्रतिक्रिया उन सबके लिए अत्यंत गहन एवं गंभीर चिंता का विषय है, जो भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं और हिंदू राष्ट्र का झंडा नहीं थामे हुए हैं. आज समाज में सांप्रदायिक सोच का बोलबाला है. भारत की संवैधानिक और विधिक नींव की चूलें हिला देने वाला यह निर्णय भारतीय गणतंत्र पर इसके पूर्व हुए हमलों से कहीं अधिक गंभीर और चिंताजनक है. महात्मा गांधी की हत्या, सिख विरोधी दंगे, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, पॉस्टर ग्राहम स्टेंस की हत्या, गुजरात कत्लेआम और कंधमाल हिंसा से भी अधिक चिंताजनक हैं यह निर्णय, इसका निहितार्थ एवं इस पर हुई प्रतिक्रियाएं. सिख विरोधी हिंसा को छोड़कर धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक भारत की अवधारणा पर हुए अन्य सभी हमलों के मूल में हिंदू राष्ट्र की विचारधारा थी. संविधान पर संघ परिवार द्वारा प्रायोजित और अंजाम दिए गए इन हमलों के दौरान कांग्रेस ने घोर अवसरवादिता का प्रदर्शन किया. उसने इन सभी मामलों में केवल दर्शक की भूमिका निभाई. एक तरह से उसने भारतीय राष्ट्र के संस्थापकों के सिद्धांतों की इन खुली अवहेलनाओं में सहायक की भूमिका का निर्वहन किया. इस घटनाक्रम को हम क्रिकेट की दुनिया के एक उदाहरण से समझ सकते हैं. भारतीय संवैधानिक मूल्य बल्लेबाज़ हैं, आरएसएस-हिंदुत्ववादी ताकतें राजनीतिक गेंदबाज़ हैं, कांग्रेस फील्डर है और सामूहिक सांप्रदायिक सोच वह अंपायर है, जो गेंदबाज़ की हर अपील पर अपनी उंगली उठाकर बल्लेबाज़ को आउट क़रार दे देता है. राज्यतंत्र का एक बड़ा हिस्सा इस मैच के लिए ऐसी पिच तैयार करता है, जो गेंदबाज़ के लिए सबसे उपयुक्त एवं सुविधाजनक हो. यह घटनाक्रम हमें नाजी जर्मनी की याद भी दिलाता है, जहां यहूदियों, कम्युनिस्टों एवं ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का दानवीकरण करके देश का वातावरण ऐसा बना दिया गया था कि फासीवादी मूल्य राज्यतंत्र और आमजनों के दिलोदिमाग़ पर छा गए और अल्पसंख्यकों एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के दमन को सामाजिक स्वीकृति मिल गई. हिंसा की हर घटना सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देती है. अयोध्या मामले में जो निर्णय आया है, वह दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि निर्णय का सभी संबंधित पक्षों ने स्वागत किया है. प्रगतिशील ताक़तों एवं धर्म निरपेक्ष आंदोलन को गंभीर आत्मचिंतन की आवश्यकता है. एक ओर संघ परिवार हमारे देश के धर्म निरपेक्ष ढांचे को ध्वस्त करने के लिए एक के बाद एक हमले किए जा रहा है और दूसरी ओर सत्ताधारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धर्म निरपेक्षता की रक्षा के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रही है. ऐसे में भारतीय धर्म निरपेक्षता की रक्षा कौन करेगा? भारत के संविधान और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को कौन बचाएगा? समय आ गया है कि प्रगतिशील, उदारवादी और प्रजातांत्रिक ताक़तें खुलकर मैदान में आएं. यह उनके लिए करो या मरो का संघर्ष है. समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर हमले और अदालतों द्वारा भारतीय क़ानून की अवहेलना अत्यंत गंभीर चिंता के विषय हैं.

राम पुनियानी
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

इंडोनेशिया में मछुआरों के एक गांव मूसी बेन्यूआसिन निवासी रिजाल एक दिन में कम से कम 40 सिगरेट पीता है.

मिड डे मील का मांगें हिसाब

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

केंद्र की मिड डे मील योजना के अनाज का एक हिस्सा अनेक कारणों के चलते नष्ट हो जाता है और यह स्थिति कमोबेश सभी राज्यों की है, उस पर अनाज चोरी का मामला अलग से. यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती. स्कूली बच्चों को दिया जाने वाला भोजन निर्धारित मात्रा और कैलोरी से कम होता है. सवाल है कि यह बर्बाद हुआ अनाज कहां जाता है? इसके बारे में न तो सरकार कोई जवाब देती है और न ही अधिकारी. राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिए गए आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि वर्ष 2007–08 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अकेले दिल्ली की मिड डे मील योजना के लिए 11,080 टन अनाज उठाया गया. इसका 35 फ़ीसदी हिस्सा यानी 3,878 टन अनाज नष्ट हो गया. परिणामस्वरूप दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को मात्र 65 ग्राम पक्का भोजन दिया गया. इसके अलावा भोजन में कैलोरी की मात्रा निर्धारित से 50 कम पाई गई. यानी बच्चों को 300 की जगह 250 कैलोरी वाला भोजन दिया गया. यह तथ्य एक आरटीआई अर्जी के जवाब से सामने आए हैं. भारतीय खाद्य निगम के नियमों के मुताबिक़, अधिकतम 2 प्रतिशत अन्न परिवहन एवं भंडारण आदि के चलते नष्ट हो सकता है, जो दिल्ली में नष्ट हुए अन्न से 17 गुना कम है. इन आंकड़ों ने दिल्ली की मिड डे मील योजना के मॉनीटरिंग सिस्टम पर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं. संभव है कि अन्न का यह हिस्सा खुदरा बाज़ार में पहुंच रहा हो. बहरहाल, जब यह हाल देश की राजधानी का है तो ज़रा सोचें कि अन्य राज्यों में इस योजना की क्या दुर्दशा होती होगी. सवाल यह है कि क्या आप यह सब कुछ जानते–सुनते चुप बैठ जाएंगे? कतई नहीं. आप सूचना क़ानून का इस्तेमाल करेंगे और सरकार से मिड डे मील का हिसाब मांगेंगे. इस अंक में हम इसी मुद्दे से जुड़ा एक आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आप इस आवेदन का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक लोकतांत्रिक लड़ाई की शुरुआत ज़रूर करेंगे. आपकी इस लड़ाई में चौथी दुनिया आपके साथ है. आप अपनी समस्या के बारे में हमें पत्र लिखकर या ईमेल से सूचित कर सकते हैं. हम हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301

ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

मिड डे मील योजना का विवरण

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

.....के प्राथमिक विद्यालय की मध्यान्ह भोजन योजना के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना का विवरण निम्नलिखित ब्योरे के साथ दें:
   (क) दिनांक.....से.....के दौरान उपरोक्त स्कूल को उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री का विवरण (मासिक ब्योरे के साथ) उपलब्ध कराएं.
   (ख) विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त खाद्य सामग्री कितने विद्यार्थियों को वितरित की जानी थी?
   (ग) यह खाद्य सामग्री किस राशन दुकानदार/एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई?
   (घ) उपरोक्त दुकान/एजेंसी का चुनाव किस प्रकार किया गया? इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों/आद`शों/दिशानिर्देशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.
   (ड) इस दौरान विभाग द्वारा विद्यालय को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित सभी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध कराएं.
2. मध्यान्ह भोजन योजना को बेहतर ढंग से लागू कराने एवं गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित सरकार एवं विभाग द्वारा जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.
3. मध्यान्ह भोजन योजना में कालाबाजारी/भ्रष्टाचार आदि की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा की गई व्यवस्था से संबंधित सभी दिशानिर्देशों/नियमों/कानूनों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.
4. दिनांक.....से.....के दौरान क्या विभाग को उपरोक्त विद्यालय से मध्यान्ह भोजन योजना के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण एवं यदि इस संबंध में कोई जांच की गई है तो जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध कराएं.
5. मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत स्वीकृत खाद्य सामग्री यदि किसी कारणवश किसी विद्यालय द्वारा उपयोग नहीं की जाती है तो उसके निष्पादन के लिए विभाग ने क्या व्यवस्था की है? इससे संबंधित नीतियों/दिशानिर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.
6. मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित विभिन्न नियमों, निर्देशों, आदेशों एवं परिपत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....
संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

दम पे दम मारे जा...

आपने सिगरेट पीना कब शुरू किया था? ख़ैर जब भी किया हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि आर्दी से पहले नहीं किया होगा. आर्दी रिजाल की उम्र केवल दो वर्ष है, लेकिन उसे चेन स्मोकर की पदवी से नवाजा जा चुका है. इंडोनेशिया में मछुआरों के एक गांव मूसी बेन्यूआसिन निवासी रिजाल एक दिन में कम से कम 40 सिगरेट पीता है. वेबसाइट द सन डॉट को डॉट यूके के मुताबिक़, जब रिजाल केवल 18 महीने का था, तब उसके पिता ने उसे सिगरेट का एक कश लगवाया था. तभी से वह धूम्रपान का आदी हो गया है. उसका वजन 25 किलोग्राम से ज़्यादा है और उसके लिए अन्य बच्चों की तरह दौड़ना–खेलना असंभव सा है.

रिजाल की मां डायना के मुताबिक़, वह बुरी तरह से चेन स्मोकिंग का शिकार है. अगर उसे सिगरेट न मिले तो वह नाराज़ होकर चीखने लगता है और दीवारों से सिर टकराने लगता है. कहता है कि उसे चक्कर आते हैं. रिजाल एक खास ब्रांड की ही सिगरेट पीता है और उसके लिए परिवार को प्रतिदिन पांच डॉलर से अधिक राशि ख़र्च करनी पड़ती है. गांव के अधिकारियों ने परिवार के सामने प्रस्ताव रखा है कि यदि उनका बेटा सिगरेट पीने की आदत छोड़ दे तो वे उन्हें उपहार में एक कार देंगे. वहीं रिजाल के मछुआरे पिता मोहम्मद को अपने बेटे की इस आदत पर कोई एतराज़ नहीं है. वह कहते हैं कि उनका बेटा स्वस्थ है. मतलब उन्हें अपने बेटे द्वारा दम पे दम मारने से कोई शिक़ायत नहीं है.

अजगर का वार

छोटे–मोटे झगड़ों में प्रयोग होने वाले कई लोकल हथियारों के बारे में आपने सुना होगा. मसलन चेन, पंच बॉक्सर, हॉकी स्टिक आदि. लेकिन इन सारे हथियारों की जगह अगर कोई सांप ले ले तो ज़रा सोचिए कि वह झगड़ा कितना दहशत भरा हो सकता है. ऐसा ही कुछ अमेरिका के दक्षिण कैरेलिना के एक मोटल में हुआ. वहां ठहरे एक यात्री ने जब ऊंची आवाज़ में संगीत सुनने को लेकर विरोध किया तो उस पर अजगर से हमला किया गया. हालांकि वह इस हमले में ज़्यादा घायल नहीं हुए, लेकिन अजगर ने उन्हें कई जगह काट ज़रूर लिया. पीड़ित व्यक्ति का नाम कल्प है. कल्प ने बताया कि उन्होंने ऊंची आवाज़ में संगीत सुन रहे टोनी स्मिथ को आवाज़ कम करने के लिए कहा था. इसके क़रीब एक घंटे बाद टोनी ने कल्प का कंधा थपथपाया. जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि टोनी के हाथ में लगभग एक मीटर लंबा अजगर है.

कल्प के मुताबिक़, स्मिथ अजगर के मुंह को दबाए हुए था. उसने अजगर से मेरे चेहरे पर कई जगह हमला कराया और उसे मेरे मुंह में घुसाने की भी कोशिश की. इस दौरान अजगर ने मेरे होंठों पर भी काटा. इस घटना से पहले कल्प ने स्मिथ से कहा था कि उन्हें सांप से बहुत डर लगता है. स्मिथ अक्सर अजगर को गले में लटका कर घूमता था. कल्प का कहना है कि वह इस हमले के बाद इतना घबरा गया कि तीन घंटे तो शावर के नीचे ही खड़ा रहा. पुलिस में शिक़ायत के बाद स्मिथ को गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ़्तारी से पहले उसने अजगर को अपने परिवार को सौंप दिया. वैसे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में हमले में इस्तेमाल हथियार को अन्य की कैटेगरी में रखा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 15 नवंबर–21 नवंबर 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
व्यवसायिक दृष्टि से यह सप्ताह महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला साबित होगा. बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की संभावना है. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
आय के नवीन स्रोत बनेंगे. विरोधियों का पराभव होगा. क्रोध एवं भावुकता में लिए गए निर्णय कष्टकारी हो सकते हैं. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. कार्यक्षेत्र में वर्चस्व बनाने में सफल रहेंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
शासन–सत्ता का सहयोग मिलेगा. पद–प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में बाधाएं आएंगी. फिज़ूलख़र्ची से बचें. जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलने के योग हैं.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
भारी व्यय का सामना करना पड़ सकता है. मन प्रसन्न रहेगा. व्यर्थ के विवाद से बचना हितकर होगा. आर्थिक योजना को बल मिलेगा. प्रणय संबंध मधुर होंगे. विरोधियों का पराभव होगा. अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों की मदद लेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
स्वास्थ्य शिथिल रहेगा. किया गया परिश्रम सार्थक होगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आर्थिक दिशा में प्रगति होगी. परिवारीजनों से तनाव मिल सकता है. धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी. यात्रा–देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभदायक रहेगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
परिवारीजनों का सहयोग मिलेगा. साझीदारी में दरार पड़ सकती है. किसी का वाणी के स्तर पर उत्पीड़न न करें. मित्रों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास फलीभूत होंगे. कुछ ऐसा होगा, जिसका आपको लाभ मिलेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
रुके हुए काम पूरे होंगे. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. अपने सामान की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें. मन प्रसन्न रहेगा. प्रणय संबंधों में मधुरता आएगी. चारों ओर आपकी प्रशंसा होगी. वाणी की सौम्यता से व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
आप अपने संपर्कों को सहेजने की कोशिश करेंगे. परिवारीजनों का सहयोग मिलेगा. संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. नौकरीपेशा व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है. गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी. कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें. दुविधा की स्थिति बनी रहेगी. प्रणय संबंधों में दरार पड़ सकती है. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
रचनात्मक क्षेत्र में किया जा रहा कार्य सफल होगा. उपहार–सम्मान का लाभ मिलेगा. संबंधित अधिकारी के कृपापात्र होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुपये–पैसे के लेनदेन में सावधानी अपेक्षित है. व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
धन लाभ के योग हैं. व्यस्तता अधिक रहेगी. कुछ लोग आपकी पहचान का ग़लत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. वाणी पर संयम रखें, विवाद आपके लिए हितकर नहीं होगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
पिता या उच्चाधिकारी का भरपूर सहयोग मिलेगा. किसी व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. धन, पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. वाणी में मधुरता बनाए रखें.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

हाल के दिनों में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देशों के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास किया है.

अमेरिका : युवा चीनी सैन्य अधिकारियों को रिझाने का प्रयास

डी आर आहूजा

पेंटागन चीनी सैन्य अधिकारियों, विशेषकर युवा अधिकारियों के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. कुछ दिनों पहले पेंटागन और पीपुल्स आर्मी ऑफ चाइना के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठक के बाद अमेरिका ने घोषणा की कि चीन के साथ उसके सैन्य संबंध सामान्य होते जा रहे हैं. दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों के आपसी संबंध परंपरागत रूप से कटु रहे हैं, लेकिन पेंटागन अब नई पीढ़ी के चीनी अधिकारियों को रिझाने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिकी सेना को अपने दुश्मन के रूप में देखते रहे हैं. अमेरिकी सेना इन युवा अधिकारियों पर डोरे इसलिए डाल रही है, क्योंकि भविष्य में चीनी सेना का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में होगा. चीनी सेना के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व से अमेरिका भलीभांति परिचित है और वह चाहता है कि उसकी सेना भविष्य के चीनी सैन्य नेतृत्व से भी वाक़िफ़ रहे. हालांकि पेंटागन को अपने इन प्रयासों में बार–बार पीएलए के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है.

पीएलए के पुराने अधिकारियों को कटुतापूर्ण संबंधों के पुराने दिन याद हो सकते हैं, लेकिन थ्येनआनमन चौराहे पर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बाद जब चीनी सेना ने तत्कालीन सोवियत संघ के रवैये का विरोध किया तो दोनों देशों के आपसी संबंध पटरी पर आने लगे. लेकिन नई पीढ़ी के चीनी अधिकारियों ने सेना का अमेरिका विरोधी नज़रिया ही देखा है. अमेरिकी सेना के प्रति पीएलए का रवैया अलग तरह का है. वह एक ओर तो एक सैन्य ताक़त के रूप में अमेरिका की प्रशंसक है, वहीं दूसरी ओर चीन के प्रति उसके रवैये को हमेशा संदेह की निगाहों से देखती है. जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में चीन के सैनिक मामलों के विशेषज्ञ डेविड शैमबॉ का कहना है कि जैसे–जैसे चीन सेना संगठित हो रही है और उसकी ताक़त बढ़ रही है, अमेरिकी सेना की शंकाएं बढ़ रही हैं. चीन की सैन्य ताक़त में विस्तार का सबसे बड़ा आधार उसकी जल सेना है, जिसमें पिछले दशक में कई नए जहाज और जलपोत शामिल किए गए हैं और अब एयर चाइना नामक एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जो निकट भविष्य में उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा.

हाल के दिनों में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देशों के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास किया है. ख़बरों के मुताबिक़, चीन अपने दक्षिणी भाग में स्थित गुआंगडोंग प्रांत में जलपोत रोधी लड़ाकू प्रक्षेपास्त्र का निर्माण भी कर रहा है, जिनकी पहुंच फिलीपींस और वियतनाम तक होगी. इन कोशिशों से चीन दक्षिणी चीन सागर में अपनी जल सीमा को बढ़ाने का इच्छुक है, ताकि इस क्षेत्र की निगरानी कर रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को चुनौती दे सके. हालांकि यह एक सच्चाई है कि चीन अपनी सेना का कितना भी विकास क्यों न कर ले, वह अमेरिका को इतनी आसानी से चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन उसकी लगातार बढ़ती क्षमता और मारक क्षमता में विस्तार के मद्देनज़र अमेरिकी सेना कनिष्ठ स्तर के चीनी सैन्य अधिकारियों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहती है. चीन भी ऐसा ही चाहता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच किसी हल्की नोंकझोंक के भी गंभीर स्वरूप धारण कर लेने का ख़तरा हर समय बना रहता है. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में चीनी सैन्य मामलों के विद्वान हुआंग झिंग का मानना है कि पिछले कुछ सालों से चीनी सेना में कनिष्ठ स्तरीय अधिकारियों को प्रोन्नत कर उनकी ज़िम्मेदारियां बढ़ाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. झिंग कहते हैं कि हर सेना को गोलबंद करने के लिए एक दुश्मन, चाहे वह काल्पनिक ही क्यों न हो, की ज़रूरत होती है. अक्सर इस दुश्मन की ताकत को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया जाता है, ताकि सेना अपनी ताक़त में विस्तार के लिए दुश्मन की ताक़त का ध्यान रखे. चीनी सेना के हर जवान, सिपाही से लेकर आर्मी कमांडर तक को शुरुआत से ही यह सिखाया गया है कि अमेरिका उसका सबसे बड़ा शत्रु है. इस साल अमेरिका की हरकतों ने चीन के इस नज़रिए को और बल प्रदान किया है.

इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति बराक ओबामा की तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के साथ हुई बैठक और ताइवान को 6.7 मिलियन डॉलर के हथियार बेचने के बाद चीन ने आधिकारिक स्तर पर अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंधों को निलंबित कर दिया था. इसके बाद अमेरिका ने प्रशांत महासागर के द्वीपों और वहां स्थित खनिज संसाधनों पर मालिकाना हक के लिए चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा तो पीएलए की भौहें और भी तन गईं. और जब सितंबर महीने में अमेरिकी जल सेना ने दक्षिण कोरिया के साथ चीनी जल सीमा के करीब युद्धाभ्यास किया तो चीनी सैन्य अधिकारी आगबबूला हो गए. अमेरिका अपनी इन हरकतों से लगातार चीन को उकसाने की कोशिश कर रहा है और उसके हितों पर चोट कर रहा है. चीनी सेना के एडमिरल यांग यी ने पिछले महीने पीएलए डेली में दो लेख लिखे, जिनमें अमेरिका को इन कारगुजारियों के लिए गंभीर नतीजों की धमकी दी गई.

देखा जाए तो अमेरिका की ये हरकतें नई नहीं हैं. ओबामा के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दलाई लामा को 2007 में अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा था. ताईवान को हथियारों की बिक्री के प्रस्ताव को अमेरिकी संसद ने 1979 में ही मंजूरी दी थी और तबसे यह लगातार जारी है. चीन की जल सीमा से लगे क्षेत्रों में दक्षिण कोरिया के साथ सैन्याभ्यास भी नया नहीं है, लेकिन पीएलए के इस कड़े रुख़ के पीछे कई कारण हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है साल 2012 में होने वाला नेतृत्व परिवर्तन. इसके चलते कोई भी संभावित नेता कमज़ोर होने का संकेत नहीं देना चाहता. फिर सेना भी अपनी बढ़ी ताक़त के मद्देनज़र विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा वैश्विक परिदृश्य में चीन की बढ़ती अहमियत भी इसका एक बड़ा कारण है. बीजिंग स्थित नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिउ मिंगफू पूछते हैं कि अमेरिका ताईवान को हथियार क्यों बेचता है, चीन तो हवाई को हथियार नहीं देता? वह आगे कहते हैं कि पहले चीन अमेरिका की इन हरकतों को चुपचाप सहता रहता था, क्योंकि वह दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर फिक्रमंद था, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और चीन भी ताक़तवर हो चुका है. चीन की जनता अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर चिंतित है. देश की बढ़ी ताक़त के बाद वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके अनुरूप इज़्ज़त चाहती है. अमेरिका को इसका ख्याल रखना चाहिए.

पीएलए के इस तल्ख रवैये के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध सुधर रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण कूटनीति है. चीन के राष्ट्रपति का निकट भविष्य में, संभवत: अगले साल जनवरी में, वाशिंगटन की यात्रा का कार्यक्रम है और अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि हू जिंताओ की इस यात्रा से पहले चीन सैन्य संबंधों को दोबारा बहाल करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास करेगा, ताकि कोई कटुता न रहे. चीनी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस साल की शुरुआत में अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट एम गेट्स की बीजिंग यात्रा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन हाल के दिनों में मिले संकेतों से ऐसा लगता है कि उनकी यात्रा पुनर्निर्धारित की जा सकती है. चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक़, चीन के रक्षा मंत्री जल्द ही हनोई में होने वाले रक्षा सम्मेलन में गेट्स से मुलाक़ात कर सकते हैं, लेकिन इस सबके बावजूद पेंटागन को लेकर चीनी सेना के नज़रिए में किसी बदलाव की कोई संभावना नहीं दिखती. पेकिंग यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ जुई फेंग का कहना है कि अमेरिका के प्रति चीनी सेना का यह रुख़ नया नहीं है. यह पहले भी ऐसा ही रहा है, लेकिन अब इसमें खुलापन आ गया है. वह यह भी कहते हैं कि इसकी वजह केवल चीन की बढ़ी ताक़त ही नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में उसकी सेना की अपेक्षाकृत अनुभवहीनता भी इसका एक बड़ा कारण है.

(लेखक द ट्रिब्यून के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पीएलए के इस तल्ख रवैये के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध सुधर रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण कूटनीति है. चीन के राष्ट्रपति का निकट भविष्य में, संभवत: अगले साल जनवरी में, वाशिंगटन की यात्रा का कार्यक्रम है और अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि हू जिंताओ की इस यात्रा से पहले चीन सैन्य संबंधों को दोबारा बहाल करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास करेगा, ताकि कोई कटुता न रहे.

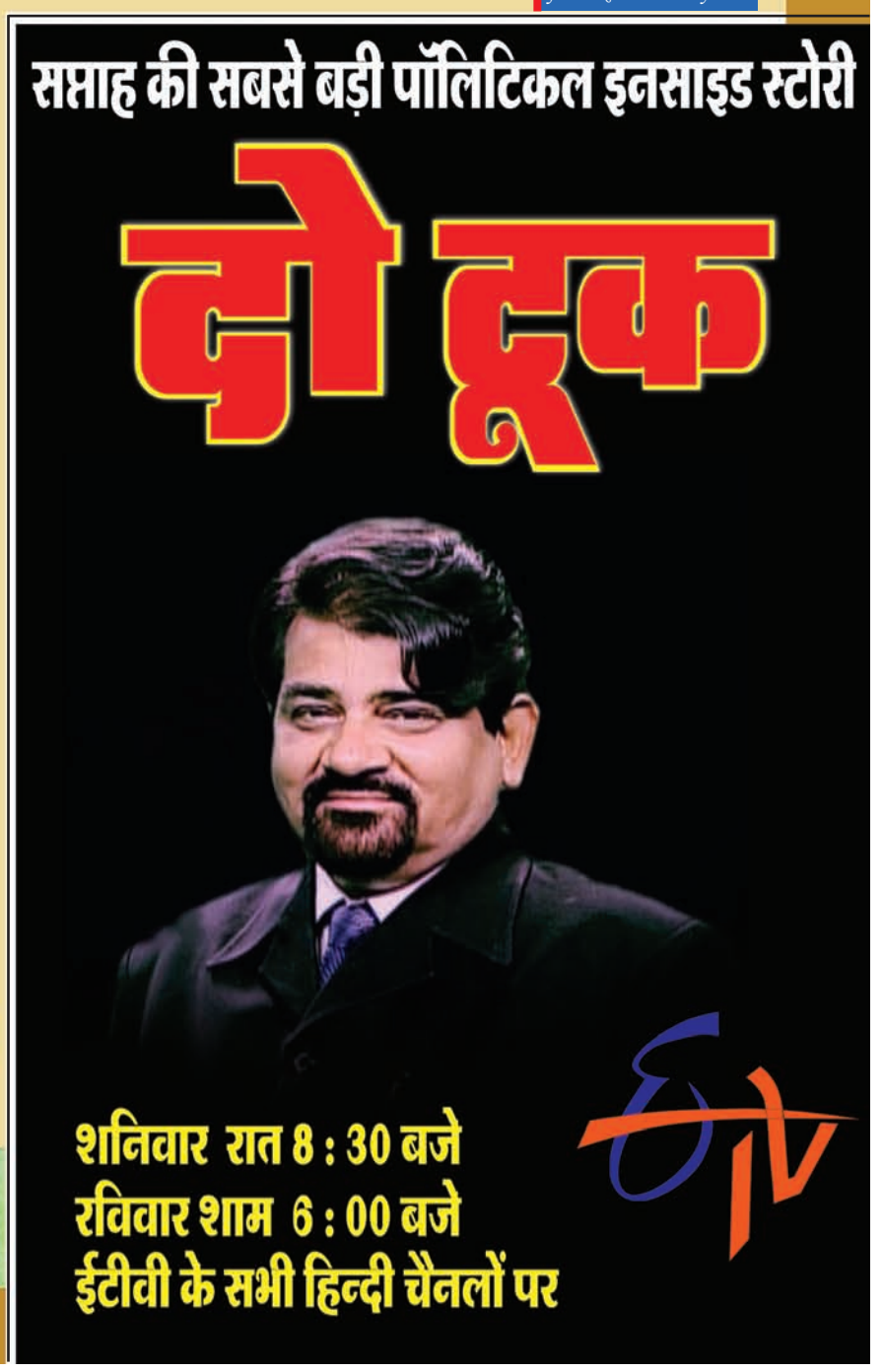

बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया. बच्चे ने आंखें फेर दी और बेसुध होकर गिर पड़ा.

बाबा का प्रसाद

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

मुंबई के हरिश्चंद्र पितले का पुत्र मिर्गी से पीड़ित था. उन्होंने उसका ख़ूब इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ न हुआ. अब केवल यही उपाय बचा था कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए. पितले जी ने बाबा का कीर्तन सुना. तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि बाबा के केवल कर स्पर्श और दृष्टिमात्र से ही असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं. उनके मन में भी साई बाबा के दर्शन की इच्छा पैदा हुई. वह यात्रा का प्रबंध कर भेंट हेतु फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों सहित शिरडी पहुंचे. मस्जिद पहुंच कर उन्होंने रोगी पुत्र को उनके श्रीचरणों में डाल दिया. बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया. बच्चे ने आंखें फेर दी और बेसुध होकर गिर पड़ा. उसके मुंह से झाग निकलने लगा और शरीर पसीने से भीग गया. ऐसी आशंका होने लगी कि अब उसके प्राण निकलने ही वाले हैं. यह देखकर उसके माता-पिता बुरी तरह से घबरा गए. माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी. तब बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा कि इस प्रकार प्रलाप न करो, धैर्य धारण करो. बच्चे को निवास स्थान पर ले जाओ. वह आधा घंटे बाद ही होश में आ जाएगा. उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया. बाबा के वचन सत्य निकले. जैसे ही वे बच्चे को वाड़े में लाए, वह स्वस्थ हो गया और पितले परिवार एवं अन्य सभी को हर्ष हुआ. पितले अपनी धर्मपत्नी सहित बाबा के दर्शन के लिए आए और अति विनम्र होकर आदरपूर्वक चरण वंदना करने लगे. मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे. बाबा ने मुस्कराकर पूछा, क्या तुम्हारी समस्त शंकाएं मिट गईं? जिन्हें विश्वास और धैर्य है, उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे.

पितले एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में मिठाइयां बांटी और उत्तम फल एवं पान बीड़े बाबा को भेंट किए. श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थीं. वह एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से निहारा करती थीं. उनका मृदु और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए. ईश्वर के समान ही संत भी भक्तों के अधीन होते हैं. जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं, उनकी रक्षा संत करते हैं. कुछ दिनों बाद पितले परिवार बाबा के पास मस्जिद में गया और चरण वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी. बाबा ने उन्हें उदी देकर आशीर्वाद दिया. पितले को पास बुलाकर वह कहने लगे, बापू पहले मैंने तुम्हें दो रुपये दिए थे और अब मैं तुम्हें तीन रुपये देता हूं. इन्हें अपने पूजा स्थान में रखकर नित्य इनका पूजन करो. इससे तुम्हारा कल्याण होगा. पितले ने उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः नमस्कार किया और आशीष के लिए प्रार्थना की. उन्हें एक विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूं कि बाबा ने दो रुपये मुझे पहले कब दिए थे. वह इस बात का स्पष्टीकरण चाहते थे, लेकिन बाबा मौन ही रहे. मुंबई पहुंचने पर उन्होंने अपनी माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन दो रुपयों की समस्या भी उनसे कही. उनकी माता को भी पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरानी घटना याद आई, जिसने यह समस्या हल कर दी. उनकी माता कहने लगीं कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर साई बाबा के दर्शनार्थ गए थे, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता कई साल पहले अक्कल कोटकर महाराज के दर्शनार्थ गए थे. महाराज पूर्ण सिद्धयोगी, त्रिकालज्ञ और बड़े उदार थे. तुम्हारे पिता परम भक्त थे. इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई. तब महाराज ने उन्हें पूजनार्थ दो रुपये दिए थे, जिनकी उन्होंने जीवनपर्यंत पूजा की. उनके पश्चात उनकी पूजा यथाविधि न हो सकी और वे रुपये खो गए. कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृति भी हो गई. तुम्हारा सौभाग्य है, जो श्री अक्कल कोटकर महाराज ने साई स्वरूप में तुम्हें अपने कर्तव्यों और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया. अब अपने कुलदेव और इन रुपयों की पूजा कर उनके यथार्थ स्वरूप को समझो तथा संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में गर्व मानो. पितले को अत्यंत हर्ष हुआ. उन्हें बाबा की सर्वकालज्ञता विदित हो गई और उनके श्री दर्शन का महत्व भी ज्ञात हो गया. इसके पश्चात वह अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रार्थना

हे साई, हमारे तो एकमात्र तुम्हीं हो, जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे. हे प्रभु, हमारी कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो.

जब तक हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं लगता, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है. हमारे पुत्र और मित्र, कोई भी अंत में काम न आएंगे.

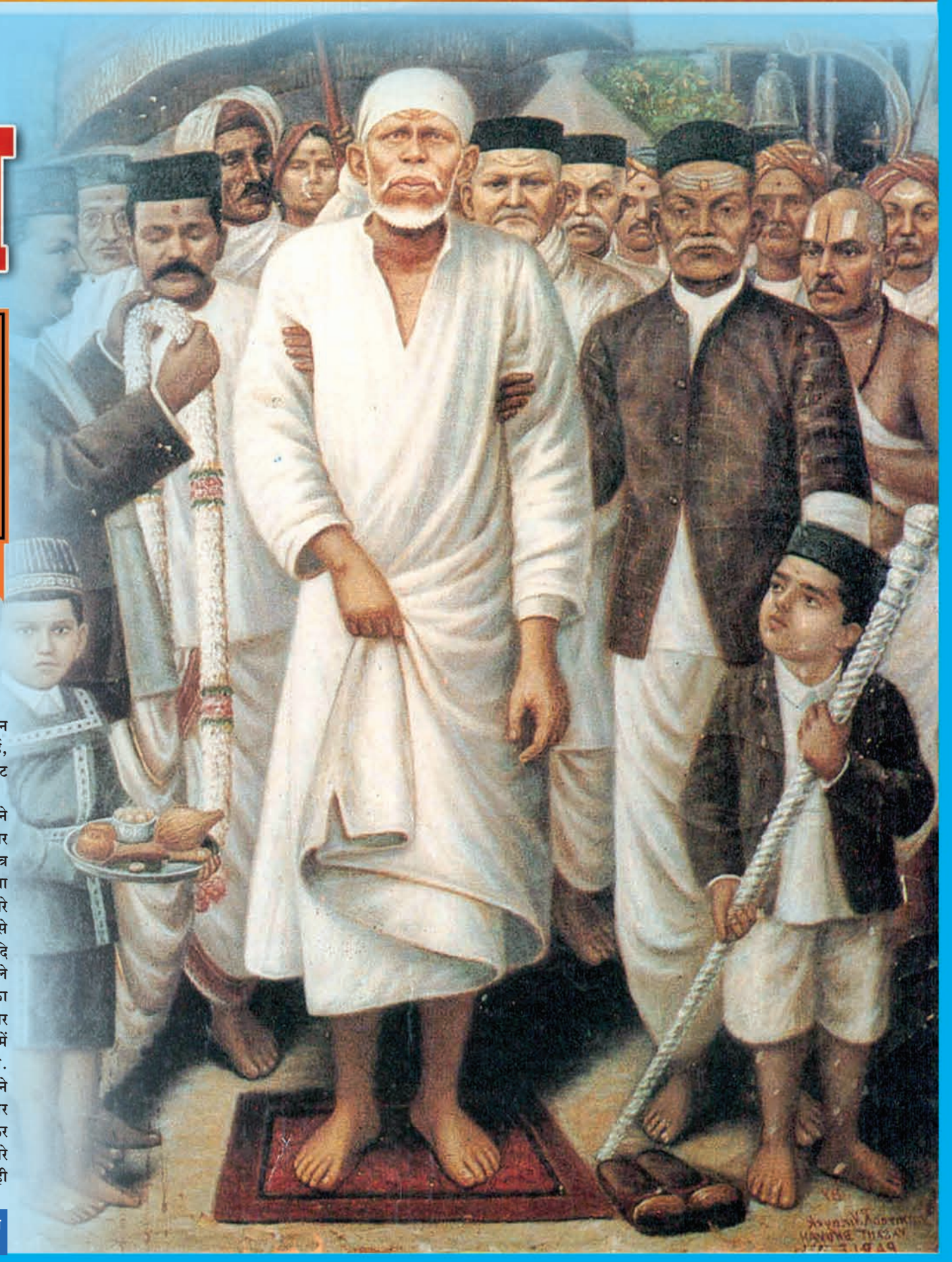

बाबा की एक खूबसूरत प्रार्थना है, जो प्राय: हेमाडपंत जी भी करते थे. वह इस प्रकार है:

हे साई सदगुरु, भक्तों के कल्पतरू. हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो. आपके श्रीचरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल न हों. हम इस जन्म-मृत्यु के चक्र से संसार में अधिक दुखी हैं. अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो. हमारी इंद्रियां, जो विषय-पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर, उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो. जब तक हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं लगता, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है. हमारे पुत्र और मित्र, कोई भी अंत में काम न आएंगे. हे साई, हमारे तो एकमात्र तुम्हीं हो, जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे. हे प्रभु, हमारी कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो. हमारी जुबान सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे. हे साई, हमारे अच्छे-बुरे सभी प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो.

प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और गृह में आसक्ति न रहे. हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए. हमारे मन की अशांति को दूर कर, उसे स्थिर और शांत करो. हे साई, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञानरूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे. यह जो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, यह तुम्हारी कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है.

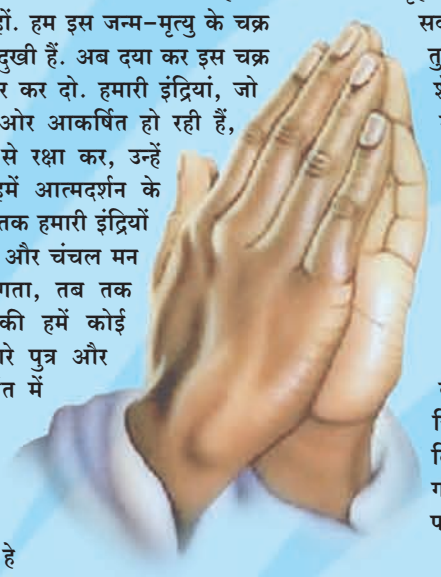

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्वेताश्वर उपनिषद में शिव को उनके विशिष्ट गुणों के कारण महादेव कहा गया है. हमारे वेदों में प्रकृति तत्वों को जीवन का मूल तत्व माना गया है और अग्नि, जल एवं वायु में देवत्व की प्रतिष्ठा की गई है.

समाचार बाज़ार की नैतिकता

अनंत विजय

जैसा कि किताब के नाम, समाचार बाज़ार की नैतिकता से ज़ाहिर है कि यह मीडिया से जुड़ी पुस्तक है और लेखक ने मीडिया को बाज़ार के बरक्श रखकर नैतिकता को कसौटी पर कसा होगा. दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रीडर कुमुद शर्मा ने बेहद श्रमपूर्वक देश–विदेश के लेखकों एवं मीडिया पुरोधाओं के उद्धरणों के आधार पर भारतीय मीडिया के बदलते स्वरूप को सामने लाने की कोशिश की है. इस किताब की संक्षिप्त भूमिका में कुमुद शर्मा ने लिखा है, आज समाचारों की दुनिया में समाचारपत्रों या समाचार चैनलों में समाचार का पहला सबक बाज़ार तय करता है. वहां समाचार चयन के समय एक ही बात दिमाग़ में उठती है कि क्या यह ख़बर बिकेगी? इसलिए बाज़ार मूल्य की ख़बरों को प्राथमिकता मिलती है. बहुत हद तक कुमुद शर्मा की राय सही हो सकती है, लेकिन पूरे परिदृश्य का सामान्यीकरण उचित नहीं है. ख़बरों के बिकने से ख़बरों की प्राथमिकता बहुधा तय होती होगी, लेकिन हमेशा ऐसा होता है, यह कहना सही नहीं होगा.

इस किताब में कुमुद शर्मा को भारतीय न्यूज़ चैनलों में मैक्सवेल ई मैकॉब और डोनाल्ड एलशा द्वारा जनसंचार के एजेंडा सेटिंग सिद्धांत की परिकल्पना पर किए गए अध्ययन के निष्कर्ष दिखाई देते हैं. इसके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय ख़बरिया चैनलों में जानबूझ कर कुछ मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है और कभी–कभी जानबूझ कर विशिष्ट मुद्दों को छोड़ दिया जाता है. उन सूचनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती, जो स्वस्थ और सामाजिक संतुलन का आधार बनें, वैचारिक प्रक्रिया को तीव्र करें और मानवीय सरोकारों को ज़िंदा रखें. पश्चिमी देशों के अंधानुकरण की वजह से भारतीय न्यूज़ चैनलों पर भी लेखिका का यही आरोप है, लेकिन कुमुद शर्मा सिद्धांतों के प्रतिपादन में और बाज़ारवाद को लेकर इतनी ऑबसेस्ड नज़र आती हैं कि देशी न्यूज़ चैनलों की सकारात्मक भूमिका भी उन्हें नज़र नहीं आती. कई ऐसी ख़बरें हैं, जिनमें चैनलों और अख़बारों ने देश का न केवल एजेंडा सेट किया, बल्कि सरकार को अपने फ़ैसले बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा. जेसिका लाल हत्याकांड में पूरे देश ने देखा कि मीडिया की क्या भूमिका और ताक़त हो सकती है. अभी हाल में भोपाल गैस कांड में छब्बीस साल बाद केंद्र सरकार को अगर पीड़ितों के लिए फिर से मुआवज़े का ऐलान करना पड़ा और सुप्रीमकोर्ट में सुधार याचिका दायर करने का फ़ैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा तो इसके पीछे ज़ाहिर तौर पर न्यूज़ चैनलों और पत्र–पत्रिकाओं का दबाव है. पत्रकारिता के लिए इस वक़्त को पतितकाल मानने वाले विश्लेषकों एवं विशेषज्ञों को यह बात मानने में परेशानी नहीं होनी चाहिए.

लेखिका की इस बात में दम है कि सही और संतुलित दृष्टि के अभाव में पत्रकार के लिए यह निर्णय लेना कठिन होगा कि किसी व्यक्ति, समाज, देश, संविधान या फिर मानवता के लिए क्या लिखना सही होगा या ग़लत. कई बार ख़बर के होने वाले असर और उसकी प्रमाणिकता का आकलन किए बग़ैर ऐसी ख़बरें छप या प्रसारित हो जाती हैं, जो देश और समाज के हित में नहीं होतीं तथा क़ानून व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देती हैं. तक़रीबन दो–ढाई साल पहले एक राष्ट्रीय चैनल ने भी दिल्ली के एक स्कूल की शिक्षिका पर स्टिंग के ज़रिए उसके सेक्स ट्रेड में शामिल होने की ख़बर प्रसारित कर राजधानी दिल्ली में हड़कंप मचा दिया था. उस ख़बर के बाद ज़बरदस्त हंगामा और आगजनी की घटना हुई थी. बाद में उक्त चैनल के प्रसारण पर सरकार ने लगभग तीन हफ्ते का प्रतिबंध भी लगाया था. यहीं पर पत्रकार के अलावा संपादक की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अख़बार में क्या छपे और चैनल पर क्या चले, क्योंकि फौरी नुक़सान के अलावा इस तरह की घटनाओं से पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है.

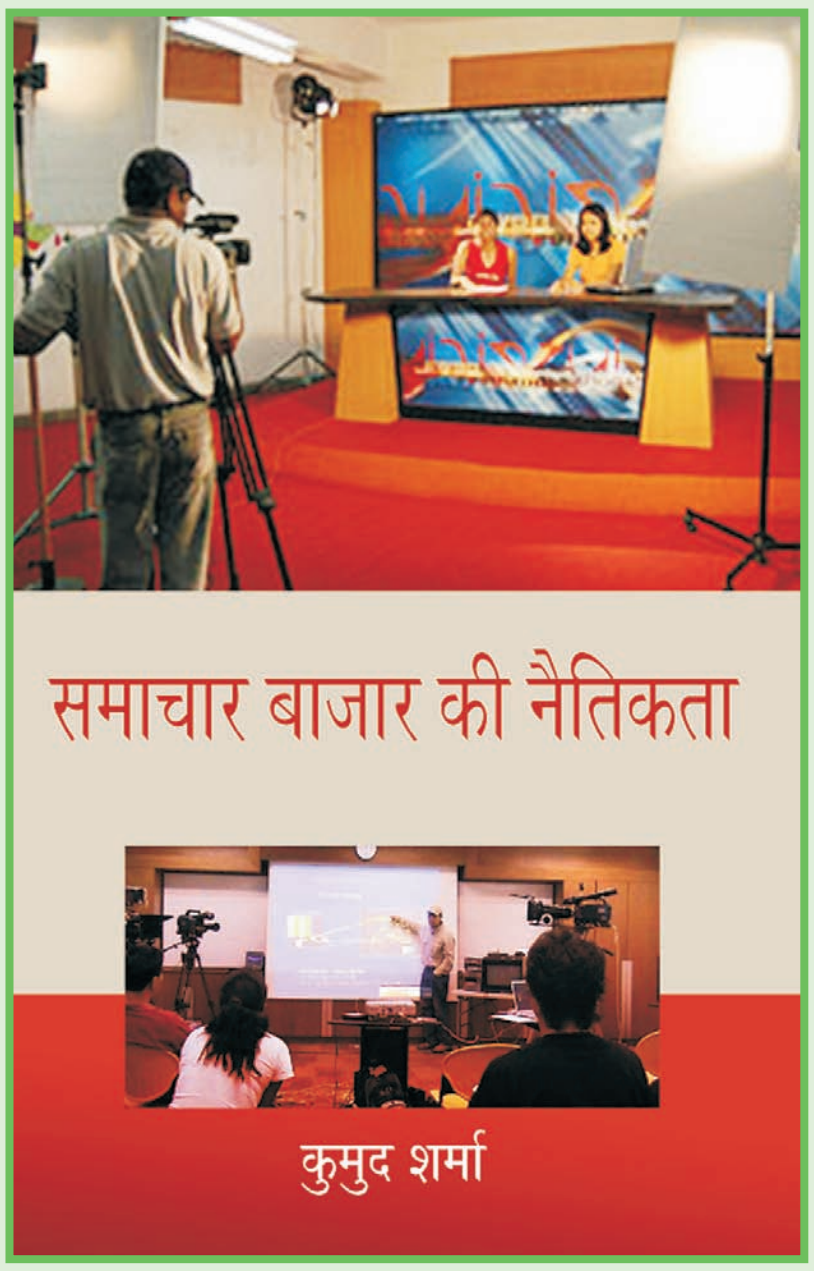

समाचार बाज़ार की नैतिकता शीर्षक तले लिखे लेख में कुमुद शर्मा एक बड़े सवाल से टकराती हैं. वह यह कि क्या समाचारों के प्रकाशन या प्रसारण के माध्यम से मुनाफ़ा कमाना अनैतिक है. पहले तो संसाधनों को लेकर विद्वान लेखिका के विचार यह कहते हैं कि अख़बार या चैनल चलाने के लिए संसाधन आवश्यक हैं, लेकिन अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि मुनाफ़े की अतिरिक्त लालसा जब समाचारों को प्रभावित करने लगे तो वह अनैतिक हो जाता है. इस बात से किसी को इंकार नहीं हो सकता है, लेकिन यह बेहद सब्जेक्टिव निष्कर्ष है, जिसे लेखिका मुनाफ़े की हवस क़रार दे रही हैं, दरअसल उसका पैमाना क्या हो. अगर उनका इशारा पेड न्यूज़ या फिर पैसे लेकर ख़बर दिखाने की ओर है तो यह पूरी तरह से अनैतिक ही नहीं, बल्कि निंदनीय भी है. अब यह बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है कि पत्रकारिता मिशन नहीं रही, लेकिन इसे पूरी तरह से सिर्फ़ लाभ कमाने का एक उद्यम मान लेना भी ग़लत होगा. तमाम आरोपों और निंदा के बावजूद अब भी मीडिया की क्रेडिबिलिटी देश की जनता के दिलोदिमाग़ पर क़ायम है. छपी और दिखाई गई ख़बरों का असर अब भी बरक़रार है. अख़बारों के बाद न्यूज़ चैनलों ने लोगों के मन में यह विश्वास तो जगा ही दिया है कि अगर उनके साथ अन्याय होगा तो चैनल उनके पक्ष में खड़े होंगे. कई बार ऐसा हुआ भी है. इस किताब में कई समाचारों का उदाहरण देकर लेखिका ने अपने तर्कों को मज़बूती प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन एक बड़ी चूक जो इस किताब में हो गई है, वह यह है कि तमाम उद्धरण और देशी–विदेशी लेखकों के विचार उस वक़्त के हैं, जब भारत में मीडिया का विस्तार नहीं हुआ था. लिहाज़ा उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर पिछले दशक में देश में मीडिया के चरित्र और स्वरूप में आए बदलाव को कसना उचित नहीं है. पुरानी अवधारणाओं के आधार पर कम से कम देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आकलन तो नहीं हो सकता है. इस देश के न्यूज़ चैनलों के विस्तार को एक–डेढ़ दशक ही हुए हैं. ऐसे में उनसे तमाम तरह की नैतिकताओं की अपेक्षा करना बिल्कुल उचित है, लेकिन पुरानी अवधारणाओं के आधार पर उन्हें खारिज कर देना या फिर बाज़ार का पिछलग्गू करार देना उचित नहीं होगा.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

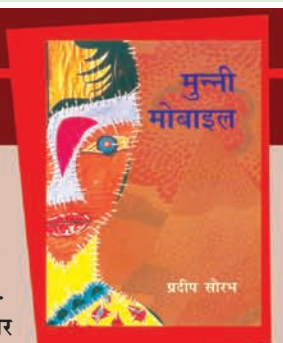

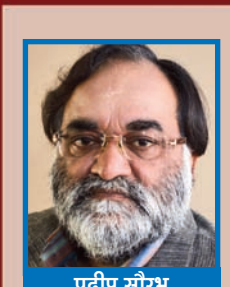

प्रदीप सौरभ

आनंद भारती दिल्ली की गे पार्टी की याद में उलझे हुए थे कि अचानक जोशी ने कहा, गुरु एक बात जानते हो? क्या? दुनिया को बदलने का सपना रखने वाले कार्ल मार्क्स भी लंबे समय तक इसी सोहो में किराए का मकान लेकर रहे थे.

आनंद भारती ने कार्ल मार्क्स के उस मकान को देखने की इच्छा जोशी से ज़ाहिर की. हालांकि वह पहले भी इस कोशिश में नाकाम रहा था. फिर भी दोनों ने कार्ल मार्क्स के मकान को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. जिससे भी पूछने की कोशिश करते, उसके पास लड़कियों की तस्वीरें और न्यूड डांस की बुकिंग की कॉपी होती.

चलते–चलते दोनों थक गए थे. जोशी ने कहा, चलो बियर पीते हैं. नाच–वाच भी तुम्हें दिखाते हैं.

लंदन की रात को देखने के लिए आनंद भारती बेचैन थे. थके होने के बावजूद वह और जोशी लेस्टर स्क्वायर की ओर चल दिए. जोशी ने बताया था कि और पब्स में एंट्री फीस लगती है, लेकिन लेस्टर स्क्वायर में येट्स पब हैं, जहां दस बजे से पहले अंदर हो जाने पर कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं. थोड़ी देर में दोनों येट्स पब के सामने थे. जोशी ने अंदर जाने की पहल की तो काले अफ्रीकी सुरक्षागार्डों ने उसे रोक लिया. उन्होंने आइडेंटी प्रूफ की मांग की. इस पर जोशी भड़क गए. दोनों के बीच काफी कहा–सुनी हुई. जोशी ने लंदन के क़ानून का हवाला दिया. फिर भी उन्होंने एक न सुनी. समय बर्बाद होता देख आनंद भारती ने जोशी से कहा, अमां यार, अपना आई कार्ड दिखा दो. क्या फ़र्क़ पड़ता है. हम यहां लड़ने तो आए नहीं हैं. जोशी ने अपने पर्स से अपना बीबीसी का आई कार्ड काले अफ्रीकी सुरक्षाकर्मी की ओर बढ़ा दिया. उसने उसे स्कैन किया और उन्हें अंदर जाने दिया.

अंदर का नज़ारा विचित्र था. डिस्क में कानफाड़ू म्यूज़िक बज रहा था. रंग–बिरंगी रोशनी इधर–उधर चमक रही थी. हज़ारों लाइटों के बीच अंधेरा पसरा था. बाहर की रोशनी से दोनों अंदर घुसे थे, इसलिए बहुत कुछ साफ–साफ नहीं दिख रहा था. थोड़ी देर में उन्हें सब दिखने लग गया था. एक किनारे में बार था. लड़कियां दारू परोस रही थीं. कुछ वेंडर लड़कियां भी नाचने वालों के बीच में घूमकर सिगरेट बेच रही थीं और बियर का आर्डर भी ले रही थीं. जोशी बार काउंटर की ओर गए और दो ग्लास बियर क्रेडिट कार्ड पर ले आए. बियर उनके अंदर जा रही थी. शोरगुल में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. हर आदमी नाचने में मस्त था. डांस करने वाले लड़के–लड़कियों के जिस्म पसीने से तरबतर थे. सब अपने में मस्त थे. किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी. नाचने का जुनून था. कान में मुंह लगाकर जोशी ने आनंद भारती से कहा, देखी दुनिया. उसने डिस्क के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो लोग कैसे मस्त हैं.

आनंद भारती ने उस कोने की ओर नज़र दौड़ाई. कुछ जोड़े बैठे थे. किसी के हाथ में व्हिस्की थी तो कोई चरस का सुट्टा लगा रहा था. इतनी बेतकल्लुफी कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता. एक जोड़े को आनंद भारती ने नज़र भरकर देखा. लड़का–लड़की नशे में चूर–चूर थे. लड़के ने लड़की की टी शर्ट के बटन खोल रखे थे. वह लड़की की छाती में बियर पीते–पीते हाथ घुमा देता था. लड़की ने भी लड़के की जींस के अंदर हाथ डाल रखा था. इसी तरह दूसरा जोड़ा भी अपनी दुनिया में डूबा था. लड़की ने जींस की चेन खोल रखी थी. वह मुंह झुकाए लड़के की गोद में बेसुध पड़ी थी. बीच–बीच में लड़की की जीभ कुछ हरकत करती थी. ऐसे ही उत्तेजक दृश्य चारों तरफ बिखरे थे. कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जीवित होते तो कामसूत्र भाग दो लिखने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. काम की नई भंगिमाएं और नए आसन उन्हें आसानी से मिल जाते.

अगले अंक में जारी...

जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर

यहां शिवभक्ति की गंगा हिलोरें लेती हैं

राजकुमार शर्मा

भगवान शिव विश्वंभर नाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग देवभूमि हिमालय के जागेश्वर में स्थित है. जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित बारह ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है. इसके पौराणिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं. यहां का प्राकृतिक वैभव हर पर्यटक–तीर्थयात्री का मन मोह लेती है. देवों के देव महादेव यहां आज भी वृक्ष वेश में युगल रूप से मां पार्वती सहित विराजते हैं. ऐसी मान्यता लेकर हज़ारों श्रद्धालु यहां हर वर्ष अपनी मनोकामना लेकर खिंचे चले आते हैं. यहां आने वाले हर श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है. भगवान शिव–पार्वती के युगल रूप का दर्शन यहां आने वाले श्रद्धालु नीचे से एक और ऊपर दो युगल शाखाओं में स्थित विशाल देवदारू के वृक्ष में करते हैं, जो 62.80 मीटर लंबा और 8.10 मीटर व्यास का है. उत्तराखंड के कुमाऊं एवं गढ़वाल जिले का यह इलाका सदा से देवों का निवास स्थान होने के कारण देवभूमि के नाम से जग में विख्यात है. भारत की सनातन संस्कृति में त्रय देवों में भगवान शिव को महादेव के नाम से पुकारा जाता है.

श्वेताश्वर उपनिषद में शिव को उनके विशिष्ट गुणों के कारण महादेव कहा गया है. हमारे वेदों में प्रकृति तत्वों को जीवन का मूल तत्व माना गया है और अग्नि, जल एवं वायु में देवत्व की प्रतिष्ठा की गई है. वहां भी शिव को रुद्र नाम से प्रतिष्ठापित किया गया है. वैदिक काल से पूर्व भी शिव का अस्तित्व रुद्र रूप से था. शिव कालातीत देवता हैं. वह सदैव लोकमंगल के लिए गतिशील देवता के रूप में जाने जाते हैं. वह किसी विशेष समय अथवा प्रयोजन के लिए अवतार नहीं धारण करते. शिव ही एकमात्र देवता हैं, जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई. मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया. इसी कारण उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है.

कुमाऊं क्षेत्र अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है. इस क्षेत्र के अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर 36 किलोमीटर की दूरी पर देवताओं का महानगर जागेश्वर स्थित है. इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई 1870 मीटर है. देवदारू के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थस्थल है. जागेश्वर में 124 मंदिरों का एक पूरा समूह है, जो अति प्राचीन है, जिसके चार–पांच मंदिरों में आज भी नित्य पूजा–अर्चना होती है. यहां स्थित शिवलिंग भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है. इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, यह तो नहीं मालूम, लेकिन इनका जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन द्वारा अपने शासनकाल में कराया गया था.

पौराणिक काल में भारत में कौशल, मिथिला, पांचाल, मस्त्य, मगध, अंग एवं बंग नामक अनेक राज्यों का उल्लेख मिलता है. कुमाऊं उसी कौशल राज्य का एक भाग था. माधवसेन नामक सेनवंशी राजा देवों के शासनकाल में जागेश्वर आया था. चंद्र राजाओं की जागेश्वर के प्रति अटल श्रद्धा थी. देवचंद्र से लेकर बाजबहादुर चंद्र तक ने जागेश्वर की हर तरह से सेवा की. बौद्ध काल में भगवान बद्री नारायण की मूर्ति गोरीकुंड और जागेश्वर की देव मूर्तियां ब्रह्मकुंड में काफी दिनों तक पड़ी रहीं. जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने इन मूर्तियों की पुनःस्थापना की.

feedback@chauthiduniya.com

कंपनी ने अपनी आईआर रेंज की क़ामयाबी से प्रेरित होकर बाज़ार की ज़रूरतों एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त नए मॉडल पेश किए हैं.

तनिष्क का ग्लैम गोल्ड कलेक्शन

गहनों के जाने-माने ब्रांड तनिष्क ने अपना नया कलेक्शन ग्लैम गोल्ड के नाम से बाज़ार में उतारा है. इस कलेक्शन के गहने भारी-भरकम के बजाय हल्के एवं ख़ूबसूरत हैं, जिन्हें आप किसी भी मौक़े पर पहन सकते हैं. उक्त गहने परंपरागत हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन के पैटर्न पर आधारित हैं. तनिष्क के डिजाइनर हेड संजीत दीवान के अनुसार, ग्लैम गोल्ड 2010 कलेक्शन गुजरात के क्षेत्रीय क्राफ्ट और राजस्थानी मीनाकारी से प्रभावित है. इस कलेक्शन के लांच के मौक़े पर इंटरटेनमेंट और फैशन इंडस्ट्री में तनिष्क ने एक पार्टी आयोजित की. फैशन शो की कोरियोग्राफर थीं अचला सचदेव. इस मौक़े पर नामी मॉडल दीपानीता शर्मा के अलावा कैंडिस पिंटो, एलिसिया राउत और बिनल त्रिवेदी ने रैंप पर कैटवॉक किया. इस सुंदर कलेक्शन को डिज़ाइन किया है ज्वेलरी डिज़ाइनर आसिफ़ एवं सजदा ने. इसे उन महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो भारतीय मूल्यों में विश्वास करती हैं.

ग्लैम गोल्ड के दो कलेक्शन हैं ग्लैम गोल्ड कलेक्शन पार्ट-1 और ग्लैम गोल्ड कलेक्शन पार्ट-2. ग्लैम गोल्ड कलेक्शन पार्ट-2 जयपुरी चटाई के डिज़ाइन पर आधारित है. इस कलेक्शन के गहने कई आकर्षक रंगों के संयोजन से बने हैं. इन गहनों में कानों के झुमके, चूड़ियां, पेंडेंट एवं नेकलेस सेट आदि हैं. तनिष्क के वाइस प्रेसिडेंट संदीप कुलहाली के अनुसार, हम अपने ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर गहने बनाते हैं. हमने देखा है कि आज की महिलाएं जहां मॉडर्न दिखना पसंद करती हैं, वहीं वे परंपरागत मूल्यों से भी जुड़ी हैं. हमने उन महिलाओं को ध्यान में रखा है, जो अपने लुक को लेकर काफ़ी सजग हैं और बौद्धिक एवं आकर्षक लुक वाले डिज़ाइन पसंद करती हैं.

कपड़े धोना हुआ आसान

ठंड की शुरुआत होते ही इलेक्ट्रानिक कंपनियां अपने विभिन्न उत्पादों के नए-नए मॉडल बाज़ार में उतारने लगती हैं. एलजी ने भी वाशिंग मशीन के कई नए मॉडल बाज़ार में उतारे हैं, जो कई आकर्षक रंगों में उपलब्ध हैं. एलजी फुल ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन के साथ-साथ सेमी आटोमेटिक मशीन के भी कई नए मॉडल बाज़ार में उतारी है. इन दोनों ही मॉडल के ग्राहक बाज़ार में मौजूद हैं. ऑटोमेटिक मशीन की बिक्री का प्रतिशत जहां 55 है तो वहीं सेमी ऑटोमेटिक मशीनों की बिक्री 45 प्रतिशत.

उक्त वाशिंग मशीने कपड़ों को ख़ास ध्यान में रखकर निर्मित की गई हैं. ये रंग को ख़राब नहीं होने देंगी और कपड़े की ख़ूबसूरती भी बरक़रार रखेंगी. एलजी इलेक्ट्रानिक्स इंडिया के होम अप्लायंस डिवीजन के प्रमुख राजीव जैन के अनुसार, कंपनी ने वाशिंग मशीन का डायरेक्ट ड्राइव फंड लोड मॉडल बाज़ार में उतारा है. इसके साथ ही कई और मॉडल लांच किए गए हैं. कंपनी को उम्मीद है कि 2010 के अंत तक 15 लाख वाशिंग मशीनों की बिक्री होगी, क्योंकि ज़्यादा बिक्री साल के अंत में ही होती है.

बच्चों के डिज़ाइनर कपड़े

भारतीय बच्चों को अंतराष्ट्रीय फैशन जगत से जोड़ने के उद्देश्य से टॉमी हिलफिगर ने अपना नया कलेक्शन भारत के बाज़ार में पेश किया है. कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर में अपने सात स्टोर खोले हैं.

अंतराष्ट्रीय फैशन जगत के लिए बच्चे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कि बड़े. विदेशों में जिस तरह बड़ों के लिए फैशन शो होते हैं, वैसे ही बच्चों के लिए भी ऐसे आयोजन अक्सर होते रहते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है. लेकिन बच्चों को अंतराष्ट्रीय फैशन जगत से जोड़ने के उद्देश्य से टॉमी हिलफिगर ने अपना नया कलेक्शन भारत के बाज़ार में पेश किया है. कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर में अपने सात स्टोर खोले हैं. इस मौक़े पर एम्बीएंस मॉल वसंतकुंज में बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री रवीना टंडन भी अपने बच्चों के साथ पहुंचीं. इसके अलावा तनीषा मोहन, अंकुर मोदी, लीना सिंह, पायल सेन और अंजली कपूर आदि लोग भी मौजूद थे. इस कलेक्शन में बच्चों के ज़रूरत की सभी चीज़ें हैं. रवीना टंडन ने कहा, मैं इस कलेक्शन को देखकर बेहद खुश हूं, क्योंकि अब मुझे अपने बच्चों के कपड़ों की ख़रीदारी के लिए लंदन, पेरिस और न्यूयार्क जैसी जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा. अब सारी चीजें यहीं मौजूद हैं, इसलिए कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है. यह कलेक्शन काफ़ी आकर्षक और आरामदेह है. यह तीन फैशन ग्रुपों का प्रतिनिधित्व करता है-एक्सप्लोर नेचर, एक्सप्लोर बीयॉन्ड और एक्सप्लोर न्यूयॉर्क सिटी.

फोटोकॉपी मशीनों की नई सीरीज़

कैनन इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ केनासाकु कोनिशी के अनुसार, ए-3 मल्टी फंक्शनल कॉपियर एक नए प्लेटफार्म इमेजनर एडवांस पर बनाई गई है.

जापान की जानी-मानी कंपनी डिजिटल इमेजिंग और कैमरा निर्माता कंपनी कैनन ने मिलकर फोटोकॉपी मशीनों की एक नई सीरीज़ बाज़ार में उतारी है. इस सीरीज़ की मशीनों में एक साथ कई सुविधाएं जैसे दस्तावेजों के प्रिंट, कॉपी, स्कैन एवं फाइलों के भंडारण और ट्रांसमीशन की विशेष सुविधा उपलब्ध रहेगी. कंपनी ने बाज़ार में एक साथ सात मॉडल उतारे हैं, जो पुरानी मशीनों के मुक़ाबले ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण हैं. कैनन इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ केनासाकु कोनिशी के अनुसार, ए-3 मल्टी फंक्शनल कॉपियर एक नए प्लेटफार्म इमेजनर एडवांस पर बनाई गई है.

कंपनी ने इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के साथ गठजोड़ की भी घोषणा की है, जिससे वह अपनी नई मशीनों में माइक्रोसॉफ्ट शेयर प्वाइंट को संबद्ध कर सकेगी. कंपनी ने अपनी आईआर रेंज की क़ामयाबी से प्रेरित होकर बाज़ार की ज़रूरतों एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त नए मॉडल पेश किए हैं. कैनन इंडिया के उपाध्यक्ष आलोक भारद्वाज के अनुसार, कंपनी के नए उत्पाद अगली पीढ़ी की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस हैं और इनकी क़ीमत 80,000 रुपये से शुरू है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Microsoft®

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

लगभग पंद्रह सालों के अंतरराष्ट्रीय करियर में गिब्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 90 टेस्ट और 248 वनडे मैच खेले, लेकिन टीम में कभी अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए.

टू द प्वाइंट : क्रिकेट के असली खेल की खुली किताब

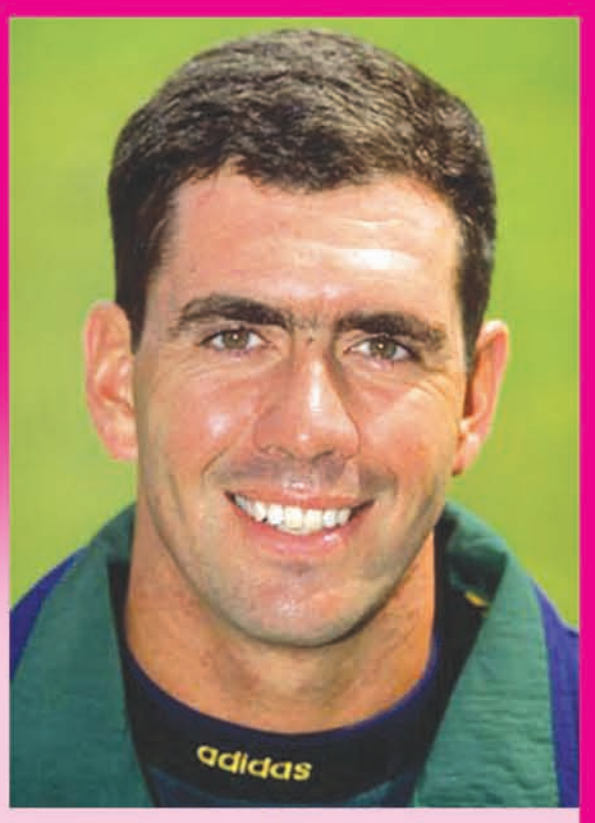

आख़िर इतना शोर क्यों मच रहा है हर्शेल गिब्स की किताब पर? टू द प्वाइंट नामक गिब्स की इस आत्मकथा में ऐसा नया क्या है? उन्होंने वही बातें लिखी हैं, जो हम सभी जानते हैं. फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि उन्होंने इन बातों को खुलकर लिखने की हिम्मत दिखाई है. क्रिकेट के खेल में सेक्स, ड्रग्स, मैच फिक्सिंग, अंडरवर्ल्ड, टीमों में गुटबाज़ी जैसी बातों की चर्चा गाहे-बगाहे होती रहती है, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ है, जब किसी मौजूदा खिलाड़ी ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करने का हौसला दिखाया है. हर्शेल गिब्स ने अपनी आत्मकथा में क्रिकेट के उन पहलुओं को बेबाकी से रखा है, जो हमेशा से इस खेल का अभिन्न हिस्सा रहे हैं. हालांकि क्रिकेट के प्रशासक इन बातों को मानने से इंकार करते हैं, लेकिन अब शायद इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि गिब्स अभी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय हैं और अगले विश्वकप में दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रतिनिधित्व करने की हसरत रखते हैं. बहरहाल, इन दिनों राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे गिब्स के इन खुलासों के बाद अब उनकी यह इच्छा शायद ही पूरी हो, लेकिन इतना तो तय है कि क्रिकेट के असली खेल से रूबरू कराने के लिए क्रिकेट के प्रशंसक उन्हें हमेशा याद रखेंगे.

लगभग पंद्रह सालों के अंतरराष्ट्रीय करियर में गिब्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 90 टेस्ट और 248 वनडे मैच खेले, लेकिन टीम में कभी अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए. इसके अलावा उनका करियर हमेशा विवादों में घिरा रहा. उनका नाम कभी मैच फिक्सिंग स्कैंडल में आया तो कभी प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल में, तो कभी उनकी रंगीन मिजाजी उन्हें सुर्ख़ियां दिलाती रही. साल 2000 में दक्षिण अफ्रीका टीम के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोन्ये का नाम सट्टेबाज़ों के साथ जुड़ा तो गिब्स भी इसके घेरे में आए और उन्हें छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया. गिब्स ने कबूल किया था कि क्रोन्ये ने उन्हें भारत के ख़िलाफ़ एक वनडे मुक़ाबले में 20 से कम रन बनाने के लिए 15 हज़ार डॉलर देने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था. हालांकि गिब्स ने इस मुक़ाबले में 74 रनों की पारी खेली थी. साल 2001 में दक्षिण अफ्रीका टीम के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान गिब्स को मेरीजुआना के सेवन का दोषी पाया गया था और उन्हें सज़ा हुई थी. इसके अलावा समय-समय पर देश-विदेश की कई अभिनेत्रियों एवं मॉडलों के साथ उनका नाम जुड़ता रहा. गिब्स ने अपनी आत्मकथा में इन सब बातों को स्पष्ट रूप से लिखा है. उन्होंने टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरों की खास चर्चा करते हुए बताया है कि 1996-97 के दौरान उनके साथी खिलाड़ी बार गर्ल्स को अपने कमरों में बुलाया करते थे. उन्होंने लिखा है कि होटल के एक कमरे में दो खिलाड़ियों के लिए जगह होती थी, लेकिन उनके साथ तीन-तीन लड़कियां भी होती थीं. गिब्स बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका टीम के अधिकतर खिलाड़ी सेक्स के पीछे भागते थे.

हालांकि उनकी आत्मकथा के जिस हिस्से को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वह दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के अंदरूनी मामलों से संबंधित है. गिब्स ने लिखा है कि टीम के कप्तान ग्रीम स्मिथ के हाथों में ज़रूरत से ज़्यादा ताक़त है और वह अपने सामने किसी और को अहमियत नहीं देते. टीम के पूर्व कोच मिकी आर्थर की चर्चा करते हुए वह बताते हैं कि आर्थर का खिलाड़ियों पर कोई प्रभाव नहीं था और स्मिथ उनकी बातों को अक्सर अनसुना कर देते थे. टीम के अंदरूनी मामलों में चार खिलाड़ियों का एक समूह, जिसमें स्मिथ के अलावा मार्क वाउचर, जैक कालिस और एबी डीविलयर्स शामिल हैं, ही सारे फ़ैसले लेता है. उन्होंने इस समूह को टीम में गुटबाज़ी और खिलाड़ियों के बीच दरार पैदा करने का दोषी ठहराया है. उम्मीद के मुताबिक़ ही दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाड़ियों और देश के क्रिकेट बोर्ड ने गिब्स के इन आरोपों से इंकार किया है. टीम के मौजूदा मैनेजर मोहम्मद मूसाजी ने टीम में गुटबाज़ी को नकारते हुए कहा कि गिब्स पिछले दो सालों से टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं, ऐसे में उन्हें टीम के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने और टीम स्पिरिट की कमी जैसे बयानों से बचना चाहिए. टीम के बल्लेबाज़ी सलाहकार एवं पूर्व कप्तान केप्लर वेसेल्स ने गिब्स की इन टिप्पणियों को एक पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए कहा कि उन्हें अब राष्ट्रीय टीम में वापसी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए.

गिब्स के साथी खिलाड़ी या क्रिकेट के प्रशासक चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उनकी किताब ने क्रिकेट की असलियत को उजागर किया है. इसने इस सच्चाई से पर्दा उठा दिया है कि खेल के बढ़ते बाज़ार के साथ इसका स्वरूप भी बाज़ारू होता जा रहा है. टीमों के चयन में खिलाड़ियों की प्रतिभा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि वह कप्तान और कोच का प्रियपात्र है या नहीं. मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच होने वाला संघर्ष तो बस एक दिखावा है, असली खेल तो ड्रेसिंग रूम के बाहर होता है, जहां खिलाड़ी पैसे और हवस की आग में अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार रहते हैं. कभी भद्रजनों का खेल कहे जाने वाले क्रिकेट के आधुनिक स्वरूप की यही सच्चाई है.

आदित्य पूजन
aditya@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
तीन महीने में रचा इतिहास
- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 15,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 50,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार-राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

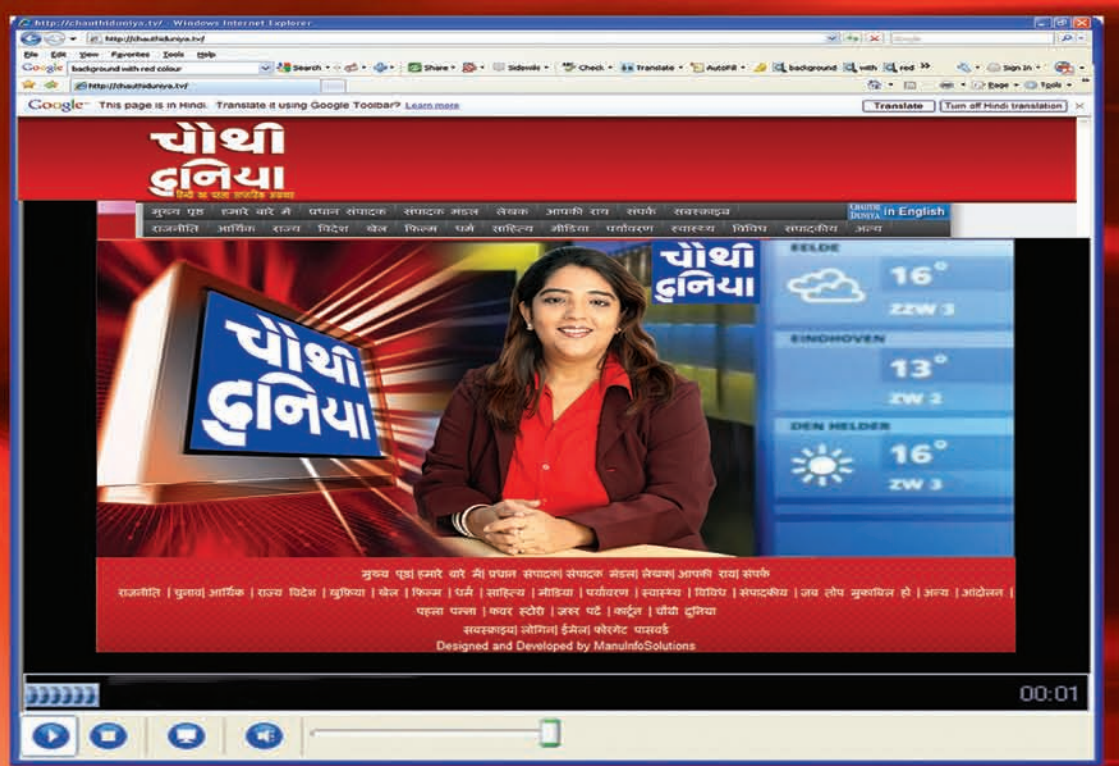

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

शाहरुख अपनी दोस्त रानी के मुंह से ऐसा सुनकर हैरान रह गए. रानी की पहली सुपर हिट फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख उनके हीरो थे.

निर्माता-निर्देशक-3

वक़्त के साथ बदलाव ज़रूरी

रीतिका सोनाली

निर्माता-निर्देशकों के एकछत्र राज से बॉलीवुड आज़ाद हो चुका है. उदारीकरण के दौर का साक्षी बनकर बॉलीवुड अब ख़ुद में एक ताक़त बनकर उभर चुका है. इस बदलाव के पीछे इंडस्ट्री की आर्थिक स्थिति का बड़ा योगदान है. इससे फिल्मों के रूप-स्वरूप में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है. वक़्त के साथ बदलाव ज़रूरी है. बदलाव की प्रक्रिया में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक यानी दोनों तरह की चीजें सामने आती हैं. जो सकारात्मक चीजें सामने आती हैं, उन्हें समाज अगले संभावित बदलाव तक स्वीकार कर लेता है, जबकि बदलाव के दौरान आई नकारात्मक चीजें थोड़े वक़्त के बाद ख़ुद समाज से बाहर हो जाती हैं. बॉलीवुड में बदलाव के दौरान दोनों ही पक्ष सामने आए. अंतरराष्ट्रीय फिल्म कंपनियों, देश-विदेश के औद्योगिक घरानों और कलाकारों के निजी प्रोडक्शन हाउसों के फिल्म निर्माण के क्षेत्र में क़दम रखने से हिंदी सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अच्छी पहचान मिली. फिल्म निर्माण और प्रदर्शन का स्तर भी पहले से बेहतर हो गया है. अनुभवी-विदेशी कंपनियों द्वारा बॉलीवुड में रुचि लेने से यहां एडिटिंग एवं शूटिंग आदि तकनीकी कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी एडवांस और ज़्यादा बेहतर हो गई है, जिसका असर पर्दे पर बेहतर प्रस्तुतिकरण में नज़र आता है. निजी कंपनियों द्वारा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करने से मुनाफा फोकस में आ गया है, जिसकी वजह से कंपनियां हर हाल में, बिना क्वालिटी पर समझौता किए बेहतरीन फिल्म बनाने की उम्मीद रखती हैं. फिल्म हिट हो, यह मंशा रखकर निर्माण से जुड़ी टीम कोशिश करती है कि एक बेहतरीन फिल्म बने. इस सोच से न सिर्फ़ फिल्मों की क्वालिटी अच्छी हुई है, बल्कि उनका स्तर भी वैश्विक हो गया है. आउटडोर लोकेशंस पर शूटिंग होने से विश्व के दूसरे देशों में बैठे भारतीय बॉलीवुड से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और इससे फिल्म का बेहतर प्रमोशन संभव हो पाता है और बॉलीवुड की लोकप्रियता बढ़ती है. युग के हिसाब से बदलाव होने पर कलाकारों की स्थितियों में भी सकारात्मक बदलाव आया है. पहले निर्माता-निर्देशक की हाथों की कठपुतली बने रहने वाले कलाकार अब ख़ुद के प्रोडक्शन हाउस होने की वजह से किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार कम होते हैं. इससे पहले कभी उन्हें मेहनताने के स्तर पर तो कभी प्रदर्शन के स्तर पर शारीरिक-मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता था, लेकिन अब कलाकारों की स्थिति अच्छी है. अपने प्रोडक्शन हाउस होने की वजह से वे निर्माताओं की मनमानी सहने के लिए मजबूर नहीं हैं और नवोदित कलाकारों की दिक्कतों को समझते हुए वे प्रतिभा और प्रदर्शन के बल पर अपनी फिल्मों के लिए उनका चयन कर सकेंगे. इससे बॉलीवुड में एक स्वस्थ वातावरण का संचार हो सकेगा. कहने का आशय यह है कि उक्त तमाम बदलाव बॉलीवुड और कलाकारों के लिए शुभ संकेत माने जा सकते हैं.

ritika@chauthiduniya.com

बिपाशा का डर

हॉट, डस्की और मज़बूत काया वाली बिपाशा बसु को देखकर कोई कह नहीं सकता कि वह डरपोक हो सकती हैं. फिल्म आक्रोश के प्रमोशन के दौरान फिल्म की टीम मुंबई से नागपुर और फिर नागपुर से जयपुर हवाई जहाज से जा रही थी. यह सिक्स सीटर प्लेन बिपाशा को जयपुर में ज्वाइन करना था, लेकिन बिपाशा ने इसमें बैठने से साफ़ इंकार कर दिया. वजह यह थी कि उन्हें मानसून के दौरान यात्रा करना बिल्कुल पसंद नहीं है. प्रोड्यूसर कुमार मंगत की लाख मिन्नतों के बावजूद बिप्स प्लेन में बैठने के लिए तैयार नहीं हुईं. बिपाशा का कहना था कि मानसून के दौरान यात्रा करने के उनके बहुत दुखद अनुभव रहे हैं. वह सामान्य हवाई सफ़र में ज़्यादा आराम महसूस करती हैं. टीम के सदस्यों ने भी उन्हें बहुत समझाया, पर बिपाशा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थीं. उनकी इस जिद के आगे झुकते हुए कुमार मंगत ने उसी प्लेन से मुंबई लौटने का ऐलान कर दिया. मुंबई वापसी की घोषणा से बिपाशा काफ़ी खुश थीं.

रानी की स्पष्टवादिता

बॉलीवुड के ख़ान बंधुओं की लड़ाई तो जगजाहिर है. खान बंधु एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौक़ा हाथ से जाने नहीं देते, पर इनकी दुश्मनी में कई बार अन्य लोग भी शामिल हो जाते हैं. हाल में कैटरीना की पार्टी में शाहरुख ने सलमान से संबंधित कोई टिप्पणी कर दी. इस पर रानी मुखर्जी ने सलमान का पक्ष लेते हुए शाहरुख को ग़लत ठहराया. शाहरुख अपनी दोस्त रानी के मुंह से ऐसा सुनकर हैरान रह गए. रानी की पहली सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख उनके हीरो थे. इसी फिल्म के दौरान रानी और शाहरुख में दोस्ती हुई थी, जो आज तक कायम है. इसके बाद भी दोनों कई फिल्मों में साथ नज़र आए. रानी की बड़ी बहन काजोल से भी शाहरुख की अच्छी दोस्ती है, पर रानी की इस स्पष्टवादिता से दोनों के बीच अब तनाव आ गया है. लोगों का कहना है कि रानी जल्द ही सलमान के टेलीविजन शो दस का दम में नज़र आने वाली हैं, इसीलिए जानबूझ कर ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है, ताकि शो हिट हो जाए. खैर, सच्चाई जो भी हो, पर शाहरुख ने अपने अगले प्रोजेक्ट में दीपिका पादुकोण को लेकर रानी की कमी पूरी कर ली है.

पति की प्रेरणा बनी मलाइका

वर्ष 1998 में आई फिल्म दिल से में चल छइयां छइयां... गाने पर आइटम डांस करके मलाइका बॉलीवुड में छा गई थीं. काफ़ी समय बाद वह पुन: उसी मुक़ाम पर हैं. फिल्म दबंग में आइटम डांस करके मलाइका आइटम डांसरों की सूची में नंबर वन पर पहुंच गई हैं. दबंग हिट रही और कारोबार में उसने आमिर ख़ान की फिल्म थ्री इडियट्स को भी पीछे छोड़ दिया. इसका श्रेय काफ़ी हद तक मलाइका को भी जाता है. पति अरबाज ख़ान की सुपर हिट फिल्म दबंग की वह सह निर्मात्री भी हैं. असफल अभिनेता अरबाज को स्थापित करने के लिए मलाइका ने कमर कस ली है. अरबाज मलाइका की सलाह पर ही कोई काम करते हैं. हाल में मलाइका ने अरबाज को सुझाव दिया कि वह टेलीविज़न की दुनिया में काम करें. छोटे पर्दे की लोकप्रियता को देखते हुए अरबाज ने झट इस सुझाव को मान लिया. अगर आने वाले समय में मलाइका अरबाज के किसी टीवी शो को होस्ट करती नज़र आएं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

ब्रेक के बाद

हम तुम, फना एवं थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जैसी फिल्में बना चुके प्रोड्यूसर कुणाल कोहली की अगली फिल्म ब्रेक के बाद जल्द ही रिलीज होने वाली है. कुणाल कोहली प्रोडक्शन और बिग पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दानिश असलम ने. मुख्य भूमिका में हैं, इमरान ख़ान और दीपिका पादुकोण. सहायक कलाकार हैं शर्मिला टैगोर, नवीन निश्चल, लीलेट दुबे, शाहाना गोस्वामी एवं युधिष्ठिर दास. इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई और मॉरीशस में हुई है. संगीत दिया है विशाल शेखर और प्रसून जोशी ने. पटकथा लेखन का जिम्मा संभाला रेणुका कुंजरू और दानिश असलम ने. फिल्म की कहानी अभय गुलाटी (इमरान ख़ान) और आलिया ख़ान (दीपिका पादुकोण) के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों एक-दूसरे को तब से जानते हैं, जब वे चार साल के थे. युवावस्था तक आते-आते उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है. आलिया बचपन से ही हीरोइन बनने का सपना देखती है. अपने सपने को लेकर वह इस कदर दीवानी है कि उसे इस बात का भी पता नहीं चलता कि कौन उसके रास्ते में आ रहा है और कौन जा रहा है. वह सिर्फ़ इसी कोशिश में लगी रहती है कि कैसे एक अच्छी हीरोइन बन जाए. अभय एवं आलिया का स्वभाव और आदतें एक-दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं, तब भी दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं. एक तरफ उनमें धीरे-धीरे प्यार पनपता है तो दूसरी तरफ उनके बीच की असमानता भी मूक रूप से विकसित होती रहती है.

यह बात तब और ज़्यादा उभर कर सामने आती है, जब आलिया हायर एजूकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है. एक तरफ दोनों पूरी मस्ती के साथ जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, वहीं अपने रिश्तों को लेकर लड़ते-झगड़ते रहते हैं. आलिया कहती है कि अभय को उससे प्यार नहीं है. ऐसे में दोनों अपने रिश्ते की सच्चाई को परखने और एक-दूसरे की कमी को महसूस करने के लिए एक ब्रेक चाहते हैं. इस फिल्म में दीपिका अपनी पिछली फिल्म लव आजकल वाले अंदाज में नज़र आई हैं. यह फिल्म आगामी 26 नवंबर को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 15 नवंबर–21 नवंबर 2010

www.chauthiduniya.com

सबका गणित उलझ गया

सरोज सिंह

बिहार का चुनाव अपने अंतिम दौर में है, लेकिन नतीजा अभी भी किसी सस्पेंस फिल्म की तरह अंधेरे में है. हालत यह है कि कोई भी बड़ा दिग्गज अपनी जीत या बढ़त का दावा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. कारण, नए परिसीमन के बाद से सभी धुरंधरों का जोड़-घटाना कुछ ऐसा गड़बड़ाया कि उनके माथे पर पसीना आ गया. नए परिसीमन के बाद हुए इस पहले चुनाव में बाज़ी किसके हाथ लगेगी, इसका जवाब राजनीतिक पंडितों के पास भी नहीं है. बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत और उसमें महिलाओं की भागीदारी के क्या मायने हैं, इसे लेकर चौक-चौराहे पर बहस जारी है. कुछ लोग इसे सत्ता विरोध तो कुछ इसे सत्ता के पक्ष का रुझान मान रहे हैं. मतदाताओं की चुप्पी ने तो जीत-हार के सवाल को और भी उलझा दिया है. अगर-मगर के गणित में नेताओं के दिन कट रहे हैं. पूरे दिन समर्थकों से बात करते-करते शाम को वे यह कहकर बैठक ख़त्म कर देते हैं कि 24 नवंबर को सब कुछ साफ़ हो जाएगा.

अगर नवंबर 2005 के चुनाव की बात करें तो उस समय पूरे बिहार की तो नहीं, लेकिन कम से कम बड़े नेताओं के चुनाव क्षेत्र के बारे में एक साफ़ राय ज़रूर बनाने में सहूलियत हुई थी कि किस वीआईपी सीट पर कौन सा वीआईपी उम्मीदवार आगे चल रहा है, लेकिन इस बार तो सारे राज़ जैसे ईवीएम में ही छिपकर रह गए हैं. सार्वजनिक तौर पर तो बड़े नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, पर दिल की बात पूछने पर कहते हैं कि बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे-तैसे निकल जाएंगे. दावे के साथ कोई दिग्गज नेता सही मायनों में अपनी जीत का दावा करने की स्थिति में नहीं है. जातीय ध्रुवीकरण के कारण जो अनुमान लगाया जा रहा है, वह अधूरा है, क्योंकि केवल एक जाति के आधार पर किसी सीट का परिणाम नहीं बताया जा सकता. दूसरी बात यह है कि मतदाताओं की चुप्पी से सारा मामला उलझ गया है. अति पिछड़े, महादलित एवं मुसलमान वोटों का रुख़ ऐसा रहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है. कोसी इलाक़े में लवली आनंद, रंजीता रंजन, महबूब अली कैसर, विजेंद्र यादव एवं रेणु कुशवाहा आदि की सीटों पर जिस तरह मतदान हुआ, उससे इन नेताओं की सांस फूल रही है. उक्त बड़े नेता यह बताने की हालत में नहीं हैं कि उनकी सीट निकल रही है या नहीं. छोटे नेताओं की सीटों का हाल इससे भी अधिक उलझा हुआ है.

आमतौर पर सारण प्रमंडल के तीनों ज़िले छपरा, सीवान और गोपालगंज चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात रहे हैं, लेकिन इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान ने रिकॉर्ड बनाया है. मतदान प्रतिशत में इज़ाफ़े से नतीजों की भविष्यवाणी करने वाले जानकारों का गणित भी गड़बड़ा गया है. मतदान के बाद कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि किस विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी. इसका एक कारण यह भी है कि प्रशासनिक तौर पर बूथों पर किसी भी तरह की गड़बड़ियों को नामुमकिन बना दिया गया है. अब लोग हार-जीत की अटकलें जातीय वोट बंटवारे के आधार पर लगा रहे हैं, लेकिन सभी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि राजद, जदयू और कांग्रेस के परंपरागत जातीय वोटों में दूसरे और तीसरे ने सेंधमारी की है. 2005 के विधानसभा चुनाव में राजद के गढ़ सारण से जनता ने उसका सूपड़ा साफ़ कर दिया था. पिछले चुनाव में राजद के मात्र दो विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच पाए थे. इस बार राजद ने ज़िले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक अमनौर को छोड़ शेष 9 स्थानों पर अपने दमदार प्रत्याशियों को लड़ाया, जिनमें छपरा सहित महाराजगंज संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों एकमा, मांझी, बनियापुर एवं तरैया में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के समर्थक प्रत्याशी मैदान में थे. शेष सीटों पर राजद के पुराने सिपहसालार प्रत्याशी बनकर जनता के बीच खड़े थे. महाराजगंज के वर्तमान राजद सांसद उमाशंकर सिंह का शुरुआती दौर से ही दल के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ बग़ावती तेवर हैरान करता नज़र आया. इसका लाभ अंतत: एनडीए प्रत्याशियों को मिलना तय माना जा रहा है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ़ से ज़िले की सभी सीटों पर राजद के माय समीकरण के अलावा राजपूत वर्ग के उम्मीदवार खड़े कर दिए जाने से राजद को अपनी चुनावी नैय्या पार लगाने में परेशानियों का सामना करने की नौबत आ गई है.

इस तरह के हालात सीवान और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्रों में अक्सर दिखते हैं. गोपालगंज में लालू प्रसाद के साले साधु यादव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं रघुनाथपुर में कांग्रेस पूर्व विधान पार्षद डॉ. चंद्रमा सिंह को अपना झंडा थमाकर राजद के नए एमआरवाई समीकरण को चुनौती देने पर तुली है. सारण ज़िले के अंतर्गत भाजपा को मिली चार विधानसभा सीटों में से तीन पर राजपूत बिरादरी के उम्मीदवारों की उपस्थिति से इस वर्ग के मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में देखा जा रहा है. यही वजह है कि राजद की बेचैनी बढ़ी हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सोनपुर में भाजपा के विनय कुमार सिंह के समक्ष कांटे की लड़ाई में फंसकर रह गई हैं. सही आकलन चुनाव परिणाम आने के बाद संभव है. फ़िलहाल ऊंट किस करवट बैठेगा, कहना काफ़ी मुश्किल है. वैसे तीसरे चरण के चुनाव में ज़िले की सभी दस सीटों पर राजद और राजग गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रही है, जबकि कांग्रेस गड़खा, मांझी, तरैया एवं अमनौर विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी चुनौती देने की स्थिति में है.

कांग्रेस के इन क्षेत्रों के उम्मीदवारों ने अपने सियासी कौशल और जनता के बीच अपनी मज़बूत पकड़ की बदौलत राजद एवं राजग गठबंधन के उम्मीदवारों का चुनाव मैदान में डटकर मुक़ाबला किया है. ज़िले की अधिकांश सीटों पर बाग़ी उम्मीदवारों की उपस्थिति से दलीय प्रत्याशी हैरान हैं. इसी तरह पूर्व बिहार में भी अश्विनी चौबे, शकुनी चौधरी, अनंत सिंह और विजय कृष्ण जैसे दिग्गज अपने चुनावी भविष्य को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं. जीत को लेकर इनके दावों में उत्साह ज़्यादा और विश्वास कम दिखाई पड़ता है. किस प्रत्याशी को जीत नसीब होगी और पटना तक का सफ़र कौन तय करेगा, इसका गणित मतदान प्रतिशत में इज़ाफ़े के कारण भी उलझा है. राजद एवं राजग दोनों इसे अपने-अपने हिसाब से देख रहे हैं. राजद का मानना है कि वोट प्रतिशत का बढ़ना हमेशा सत्ता के ख़िलाफ़ जाता है. राजद के प्रधान महासचिव राम कृपाल यादव का कहना है कि इस चुनाव में ग़रीब लोग अपनी सरकार लाने के लिए बेचैन हैं, उनके घर की महिलाओं और युवकों का बड़ी संख्या में बूथों तक पहुंचना ही मतदान प्रतिशत बढ़ने का कारण है. जदयू के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. भीम सिंह का मानना है कि वोट प्रतिशत इसलिए बढ़ा है कि जनता की जनतांत्रिक व्यवस्था और सरकार के प्रति आस्था बढ़ी है. लोगों ने भयमुक्त होकर नीतीश सरकार की वापसी के लिए मतदान किया. उक्त अलग-अलग दावे बताते हैं कि सूबे में चुनाव परिणाम का सवाल कितना उलझा हुआ है. इस उलझन से पर्दा तो 24 नवंबर को ही उठेगा.

feedback@chauthiduniya.com

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सोनपुर में भाजपा के विनय कुमार सिंह के समक्ष कांटे की लड़ाई में फंसकर रह गई हैं. सही आकलन चुनाव परिणाम आने के बाद संभव है. फ़िलहाल ऊंट किस करवट बैठेगा, कहना काफ़ी मुश्किल है.

राबड़ी देवी

विजय कृष्ण

रामचन्द्र

महबूब अली कैसर

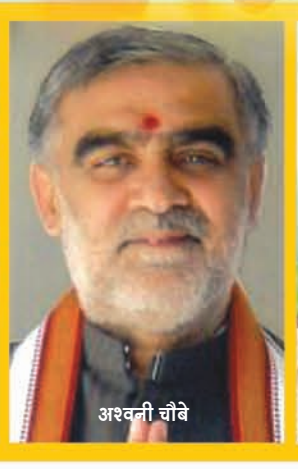

अश्वनी चौबे

जनार्दन सिंह

लवली आनंद

रंजीता रंजन

साधु यादव

अनिल कुमार को राजद ने इस बार घेरने का प्रयास किया है. पूर्व मंत्री एवं बाग़ी कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाकर राज्य स्तर पर दलीय जातीय गठबंधन को तोड़ने का प्रयास किया गया है.

जदयू ने पिछले चुनाव में चौथे स्थान पर रहे प्रमोद चंद्रवंशी को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है.

चुनावी तड़का

पलक झपकते मिटेगी थकान

टिकट लेने से लेकर वोट मांगने तक की कवायद में कुछ नेता इतने थक गए कि बेचारे हमेशा आह-उह करते नज़र आ रहे हैं. हर बैठक में बस एक ही चर्चा कि रात-दिन जनता के दरवाज़े पर दस्तक देते-देते शरीर का एक-एक अंग टूट गया. झाझा से राजद प्रत्याशी विनोद यादव भी इन दिनों दर्द से ज़्यादा ही परेशान हैं. जहां बैठते हैं, दर्द की चर्चा करना नहीं छोड़ते, लेकिन बाद में कहते हैं कि जनता ने इतना प्यार दिया कि यह दर्द धीरे-धीरे दूर हो जाएगा. उनके समर्थक उनसे कह रहे हैं कि नेता जी चिंता मत कीजिए, जीतकर जब पटना जाइएगा तो पूरी थकान पलक झपकते दूर हो जाएगी.

जिधर पूड़ी, उधर मुड़ी

ललन सिंह और शिवानंद तिवारी इन दिनों एक-दूसरे पर जमकर ज़ुबानी तीर चला रहे हैं. ललन सिंह एक बात कहते हैं तो शिवानंद दो बातें कहकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं. फ़िलहाल दोनों नेताओं में ज़ुबानी जंग जारी है. शिवानंद ने कहा कि नैतिकता का तक़ाज़ा है कि ललन सिंह को सांसदी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. जदयू में रहकर कांग्रेस का प्रचार करना कहां की नैतिकता है. इस पर ललन सिंह ने कहा कि मैं तो पहले दिन से ही इस्तीफ़ा देना चाहता था, पर उस समय शिवानंद जी ने मुझे मना कर दिया. दरअसल शिवानंद जो भाषा बोल रहे हैं, वह उनका मूल स्वभाव है. दरअसल वह जिधर पूड़ी, उधर मुड़ी वाले इंसान हैं.

कुर्ता और जींस चलेगा

मतदान के बाद बहुत विधायक विधानसभा जाने के लिए पहली जाने वाली ड्रेस को लेकर भी चल रहे हैं. युवा नेताओं के समर्थक उन्हें जींस और शर्ट पहन कर विधानसभा जाने की सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ चाहते हैं कि विधानसभा में पहली एंट्री कुर्ता-पायजामा पहन कर ही की जाए. इस कारण कुछ युवा संभावित विधायक इन दिनों पसोपेश में हैं. समर्थकों ने तो पहले दिन से ही इसलिए नेता जी उनका दिल फ़िलहाल नहीं तोड़ना चाहते. कुछ नेताओं ने रास्ता निकाला कि दोनों की बात रह जाए, इसलिए कुर्ता और जींस पहन कर विधानसभा में एंट्री की जाए.

चित भी अपनी, पट भी अपनी

अस्थावां विधानसभा क्षेत्र के बिंद में मुख्यमंत्री की सभा हो रही थी. सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक सभा में जुटे जदयू समर्थकों ने मुख्यमंत्री ज़िंदाबाद, विधायक डॉ. जितेंद्र कुमार मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया. ग़नीमत है कि डॉ. जितेंद्र को पुनः प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अस्थावां में काफ़ी विरोध है. शीर्ष नेताओं की ओर से अब तक समर्थकों को मनाने के प्रयास विफल रहे हैं. कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को मनाने की ज़िम्मेदारी विधायक इं. सुनील को सौंपी गई थी, वह भी अब तक नाकाम रहे हैं. माजरा समझते ही नीतीश कुमार ने चालाकी से काम लिया. चूंकि उन्हें दोनों का साथ चाहिए, लेकिन जनता को ख़ुश करने के लिए उन्होंने डॉ. जितेंद्र से भरी सभा में माफ़ी मंगवाई और इस तरह से मामला संभाल लिया.

आख़िरी मौक़ा दे दो

कहते हैं कि नेता और अभिनेता दोनों चुनाव और फ़िल्मों के समय ही जनता के दरबार में हाज़िरी लगाते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में नेता हाज़िरी लगाने के साथ-साथ जनता से आख़िरी मौक़े की गुहार भी कर रहे हैं. पिछले दिनों भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज़ हुसैन और राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में नीतीश-सुशील सरकार को एक मौक़ा और देने की अपील गया के नागरिकों से स्थानीय आज़ाद पार्क, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खरका उच्च विद्यालय और अतरी विधानसभा क्षेत्र के मोहड़ा प्रखंड के बेला गांव में आयोजित चुनावी सभाओं में की. प्रसाद ने चुटकी लेते हुए कहा कि 15 वर्ष का लालू-राबड़ी शासनकाल बिहार के लिए कई मायने में ऐतिहासिक रहा. मुख्यमंत्री पशुओं का चारा खा गए. खुलेआम सड़कों पर रायफल की नोक वाहनों से निकलती नज़र आती थीं. अपहरण, लूट, डकैती, सामूहिक दुष्कर्म एवं नरसंहार के लिए बिहार जाना जाता था. उन्होंने कहा कि बिहार की भाजपा-जदयू सरकार ने बाहुबलियों को स्पीडी ट्रायल कराकर जेल में बंद किया. आज बिहार में नरसंहार नहीं हो रहा. देर रात तक महिलाएं कहीं भी आ-जा सकती हैं. हुसैन कह रहे थे कि भाजपा ने महान वैज्ञानिक ए पी जे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाकर अल्पसंख्यकों को सम्मान दिया. रूडी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद राजद-लोजपा का चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा. अब इन तीनों को कोई यह समझाए कि अगर वास्तव में इतना काम हुआ है तो जनता पर सब कुछ छोड़ दीजिए, काहे को बार-बार मौक़ा मांग रहे हैं.

ज़ुबानी जंग है भाई

जहां प्रसाद, हुसैन और रूडी की तिकड़ी लालू के कारनामों का उदाहरण देते हुए ख़ुद को मौक़ा देने की बात कर रही है, वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद भी पीछे नहीं हैं. कहते हैं कि नीतीश ने विकास के नाम पर प्रदेश की हर गली में दारू की दुकान खुलवा कर पांच वर्षों में नशेड़ियों की जमात तैयार कर दी. मेरी सरकार बनी तो हर हाथ को काम दिया जाएगा. ये सब बातें उन्होंने नवादा और गया के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते के दौरान कहीं. उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर प्रदेश में सुई का एक कारखाना तक नहीं खुला. लाचार, ग़रीब बेबस एवं मज़दूर तबका यहां से पलायन कर रहा है. फ़र्ज़ी डिग्रीधारियों को नौकरी देकर शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई. नीतीश कुमार ने लोगों को जातिपात में बांटने का कार्य किया है. अब यह तो ज़ुबानी जंग है भाई, किसने कितना काम किया, इसका फ़ैसला तो जनता ही करेगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गया
नक्सलियों के रहमोकरम पर होगा मतदान

सुनील सौरभ

गया ज़िले के शेष बचे नक्सल प्रभावित पांच विधानसभा क्षेत्रों में बीस नवंबर को होने वाले मतदान में प्रत्याशियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. बिहार में हुए विकास के दावों को नकारते हुए नवसृजित शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, गुरुआ और टिकारी विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या माओवाद की है. इन क्षेत्रों में जनता बिहार सरकार की नहीं, बल्कि समानांतर सरकार के नुमाइंदों के रहमोकरम पर रहने को विवश है. हर बार की तरह इस बार भी प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने क्षेत्र में मतदान बहिष्कार का आह्वान कर रखा है. ऐसे में मतदान की क्या स्थित रहेगी, यह तो बीस नवंबर को ही पता चलेगा. फ़िलहाल लोग नक्सलियों के फ़रमान से दहशतज़दा हैं. मतदान के बाद सुरक्षाबलों की तो वापसी हो जाएगी और फिर नक्सलियों के फरमान की अवहेलना का ख़ामियाज़ा कैसे झेलना होगा, लोग इसी माथापच्ची में लगे हैं. उधर हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगा है. यहां टिकारी विधानसभा क्षेत्र ही ऐसा है, जहां विकास की बात की जा रही है. यहां नक्सलियों के फरमान का असर कम है. इन पांच विधानसभा क्षेत्रों में बिहार की पक्ष-विपक्ष की राजनीति के तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति जनता की अदालत में फंसे हैं. इमामगंज से जदयू प्रत्याशी एवं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, शेरघाटी से राजद प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री शकील अहमद खां और टिकारी से जदयू प्रत्याशी एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. अनिल कुमार. सभी अपने जातीय समीकरण बैठाकर विजयश्री हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

अनिल कुमार | अनिरुद्ध यादव | बिंदी यादव | सुरेन्द्र कुमार | शकील अहमद | उदय नारायण चौधरी

अब मतदाताओं का क्या रुख़ होगा, यह तो ईवीएम खुलने पर ही पता चलेगा, लेकिन समस्याओं के अंबार तले दबे और नक्सलियों की दहशत में जी रहे बाराचट्टी, इमामगंज, गुरुआ एवं शेरघाटी के लोगों को चुनाव जीतने वाले नेताओं से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है. नवसृजित शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री शकील अहमद खां, जदयू से शेरघाटी प्रखंड प्रमुख विनोद यादव, कांग्रेस से चंद्रिका यादव, जद (एस) से अलेक्जेंडर खां, निर्दलीय बख्तियार राणा, भरत यादव, बच्चू यादव एवं मंजू अग्रवाल चुनाव मैदान में हैं. यहां शकील अहमद खां की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इस बार वह चक्रव्यूह में फंसे हैं. इमामगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी एवं विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी नक्सलियों द्वारा क्षेत्र में न घुसने देने की धमकी और वोट बहिष्कार के ऐलान के बावजूद गठबंधन के जातीय समीकरण के चलते से मज़बूत नजर आ रहे हैं. राजद ने यहां से ज़िला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रोशन भुइयां एवं कांग्रेस ने सुजीत मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया है. यहां किसी की भी जीत नक्सलियों के फरमान के असर और समर्थन पर निर्भर करती है. बाराचट्टी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी की समधिन ज्योति मांझी जदयू की प्रत्याशी हैं. राजद ने पूर्व विधायक समता देवी, कांग्रेस ने बढ़न भुइयां, बसपा ने नीलम पासवान और भाकपा माले ने कमलेश पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है. यहां जीत उसी की होगी, जो बाराचट्टी और मोहनपुर प्रखंड के जंगली-पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीणों के मत पा सकेगा.

नक्सल प्रभावित इन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम होना सभी प्रत्याशियों की परेशानी बढ़ा सकता है. गुरुआ विधानसभा क्षेत्र भी नक्सल प्रभावित माना जाता है. यह क्षेत्र दो नक्सली गुटों के संघर्ष का केंद्र बना हुआ है. यहां राजद ने अपने पूर्व मंत्री शकील अहमद खां के बदले पूर्व ज़िला परिषद अध्यक्ष विंदेश्वर प्रसाद यादव उर्फ़ बिंदी यादव को चुनाव मैदान में उतारा है. भाजपा ने सुरेंद्र सिंह और कांग्रेस ने अनिरुद्ध यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ज़िला पार्षद राजेंद्र सिंह इन सबका खेल बिगाड़ने में लगे हैं. निर्दलीय प्रत्याशी होकर उन्होंने अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है, पर दलीय समीकरण के चलते मुख्य मुक़ाबला बिंदी यादव और सुरेंद्र सिंह के बीच ही नज़र आता है. टिकारी विधानसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. अनिल कुमार को राजद ने इस बार घेरने का प्रयास किया है. पूर्व मंत्री बाग़ी कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाकर राज्य स्तर पर दलीय जातीय गठबंधन को तोड़ने का प्रयास किया गया है. बीस नवंबर को होने वाले मतदान में उक्त पांच विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की व्यवस्था और नक्सलियों के फरमान के बीच मतदाता क्या करें और क्या न करें वाली स्थिति में हैं. वहीं दूसरी ओर विभिन्न संगठनों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान जारी है.

feedback@chauthiduniya.com

बाग़ी के फंदे में प्रौद्योगिकी मंत्री

टिकारी

सूबे के प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. अनिल कुमार टिकारी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के नए आयामों के बावजूद इस बार चुनाव में फंसे हुए नजर आ रहे हैं. उन्हें फंसाया है राजद प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री बागी कुमार वर्मा ने. राजनीतिक समीकरण के तहत बागी कुमार वर्मा की जाति वर्तमान में जदयू-भाजपा गठबंधन का वोट बैंक मानी जाती है, लेकिन अपने पिता पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र नाथ वर्मा के सहारे राजनीति की सीढ़ी चढ़े बागी कुमार वर्मा के पक्ष में जातीय मतों की गोलबंदी ने अनिल कुमार की नींद हराम कर दी है. कांग्रेस ने यहां से अनिल कुमार के सजातीय स्थानीय नेता राम नंदन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भूमिहारों का मत अनिल कुमार के पक्ष में एकजुट है. राजद प्रत्याशी बागी कुमार वर्मा कोयरी समाज के साथ-साथ राजद-लोजपा के यादव, पासवान एवं मुस्लिम और कुछ हद तक राजपूत मतों का भरोसा लेकर अति उत्साहित हैं. जबकि अनिल कुमार को अपने सजातीय भूमिहार मतों पर सौ फीसदी के साथ-साथ जदयू-भाजपा के अति पिछड़ों, महादलितों के अलावा विकास के आधार पर राजपूत मतों पर पूरा विश्वास है.

ऐसे में टिकारी के क्षेत्रीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजपूत मतदाता ही निर्णायक स्थिति में हैं, लेकिन उन्हें एकजुट करने में अनिल कुमार कितना सफल हो पाते हैं, यह उन्हीं पर निर्भर है. हालांकि क्षेत्र की जनता कहती है कि अनिल कुमार ने क्षेत्र में पांच वर्षों में विकास की जो हवा बहाई है, वैसा अब तक किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं हुआ है. उनके महीने में बीस दिन से अधिक क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात भी हर कोई स्वीकार करता है. बावजूद इसके कई लोगों का मानना है कि बागी कुमार वर्मा ने विकास के बावजूद अनिल कुमार को इस बार फंसा दिया है.

वादे नहीं जवाब मांगेगी जनता

चेनारी

रोहतास ज़िले के दक्षिणी छोर पर अगर कैमूर की पहाड़ियां झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाएं छूती हैं तो यहीं से निकटवर्ती कैमूर ज़िले का बंटवारा भी होता है. इन दुर्गम घाटियों में और इसके आसपास रहने वाले लोगों की समस्याएं भी उतनी ही दुर्गम हैं. यहां के लोग इन समस्याओं को लेकर लोग सदियों से जूझते आए हैं. चेनारी विधानसभा क्षेत्र इसी तलहटी वाले हिस्से में पड़ता है. यही कारण है कि यहां चुनाव लड़ रहे हर प्रत्याशी को मतदाताओं के एक-एक सवाल का जवाब देना पड़ रहा है. चेनारी विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में दुर्गावती जलाशय परियोजना की ओर मतदाता आस लगाए बैठे हैं कि यह जल्द ही शुरू हो जाए. साथ ही पूर्वी हिस्से में कदवन जलाशय परियोजना के अलावा महादेवा जलाशय परियोजना भी मतदाताओं के दिमाग़ में है. इन सबसे भी चुनावी गणित प्रभावित होगा.

ललन पासवान

श्याम बिहारी

यहां चुनाव मैदान में उतरे राजद प्रत्याशी ललन पासवान ने विधानसभा से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक दुर्गावती जलाशय परियोजना के लिए लड़ाई ज़रूर लड़ी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. मतदाताओं को आज भी इसका मलाल है. उधर कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी गौतम द्वारा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की तरफ़ से दुर्गावती जलाशय परियोजना को लेकर किए गए प्रयासों को लोगों तक पहुंचाने की कवायद चल रही है. जदयू प्रत्याशी श्याम बिहारी राम राज्य सरकार की सिंचाई परियोजनाओं को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं. 2 लाख 29 हज़ार 270 मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में एक लाख 23 हज़ार 194 पुरुष और एक लाख 6 हज़ार 16 महिला मतदाता हैं. पूरा इलाक़ा असिंचित है और उग्रवाद से भी प्रभावित है. चेनारी, शिवसागर, रोहतास और नौहट्टा प्रखंड में पड़ने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्थल भी आते हैं, जो इतिहास के पन्नों में ख़ास जगह रखते हुए भी अब तक सरकार की योजनाओं से अछूते हैं. बताते चलें कि वर्ष 2005 के फरवरी महीने में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी के रूप में ललन पासवान ने राजद प्रत्याशी को 21 हजार मतों से हराया था. जब अक्टूबर महीने में दोबारा चुनाव हुए तो उन्होंने राजद प्रत्याशी जवाहर पासवान को लगभग 18 हज़ार मतों से हराया. बाद में दुर्गावती जलाशय परियोजना को लेकर सरकार के साथ हुई अनबन में ललन पासवान ने जदयू छोड़कर राजद का दामन थाम लिया.

इसी के साथ बीते साल सितंबर में हुए उपचुनाव में वह 940 मतों से पिछड़ते हुए कांग्रेस के मुरारी गौतम से चुनाव हार गए. एक बार फिर चुनावी मैदान में राजद और कांग्रेस के पुराने दिग्गज आमने-सामने हैं. पिछले उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रहे जदयू ने इस बार शिवाधार पासवान की जगह श्याम बिहारी राम को मैदान में उतारा है, जबकि चौथे पायदान पर रही बसपा ने भी अपने पूर्व प्रत्याशी धोती प्रसाद आर्य की जगह रवींद्र राम में विश्वास जताया है. इसके अलावा और भी कई छोटे-बड़े दल अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर चौंकाने वाले परिणाम की तैयारी में हैं, लेकिन यहां वहीं जीतेगा, जो मुद्दों की नहीं, विकास की बात करेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रतिनिधित्व से वंचित हटिया

भाजपा को पूरा भरोसा है कि कोर्ट का निर्णय उसके प्रत्याशी रामजीलाल सारडा के पक्ष में होगा. उधर कांग्रेस सारडा का दावा ख़ारिज होने की उम्मीद कर रहा है. दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि स्थिति जल्द ही साफ़ हो जाए.

नवल किशोर सिंह

कांग्रेस विधायक गोपाल शरण नाथ शाहदेव के देहांत के बाद हटिया विधानसभा क्षेत्र नेतृत्वविहीन पड़ा है. शाहदेव का देहांत 24 जून 2010 को हुआ था. उनके चुनाव को दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के रामजी लाल सारडा ने न्यायालय में चुनौती दी थी. मामला अभी तक झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित है.

नियमानुसार कोई भी विधानसभा क्षेत्र छह माह से ज़्यादा समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता. यह अवधि 23 दिसंबर को समाप्त हो रही है, लेकिन समस्या यह है कि न्यायालय ने अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं दिया है. यदि अदालत रामजी लाल सारडा के दावे को सही मानकर उन्हें विजयी घोषित कर देती है तो इस विधानसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा और यदि उनके दावे को ख़ारिज़ कर दिया गया तो उपचुनाव ही एकमात्र रास्ता बचेगा. यदि अदालत के निर्णय में विलंब होता है तो छह माह के अंदर प्रतिनिधित्व देने में कठिनाई होगी. चुनाव होने की सूरत में चुनाव आयोग को भी कम से कम दो माह समय चाहिए. इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग अदालत से मामले की जल्द सुनवाई और निर्णय के लिए याचिका दायर करने की तैयारी में है. केंद्रीय उप चुनाव आयुक्त विनोद जुत्सी ने यह संकेत दिया है. उधर झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवाशीष गुप्ता का कहना है कि आयोग अदालत के निर्णय का इंतज़ार करेगा.

भाजपा को पूरा भरोसा है कि अदालत का निर्णय उसके प्रत्याशी रामजी लाल सारडा के पक्ष में जाएगा. उधर कांग्रेस सारडा का दावा ख़ारिज़ होने की उम्मीद कर रही है. दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि स्थिति शीघ्र ही साफ़ हो जाए. इसलिए संभव है कि वे भी जल्द निर्णय के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं. बहरहाल राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में भी जुटे हुए हैं. सबके बीच उम्मीदवारी की दावेदारी और चयन को लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है. झारखंड राज्य के गठन से पूर्व इस सीट पर भाजपा का क़ब्ज़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में कांग्रेस का वर्चस्व कायम हो गया.

इस लिहाज़ से दोनों पार्टियां इसे अपनी परंपरागत सीट मानती हैं. पिछले चुनाव में उनके बीच कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार स्वर्गीय शाहदेव मात्र 25 मतों से विजयी हुए थे. भाजपा उम्मीदवार रामजी लाल सारडा ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी थी.

उपचुनाव होने की सूरत में इस सीट से मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उनके पास वक़्त नहीं है. उन्हें शपथ ग्रहण के छह माह के अंदर विधानसभा चुनाव जीतना ज़रूरी है. इसलिए उन्होंने खरसांवा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है. इस संबंध में पार्टी के आला नेताओं को भी अवगत करा दिया गया है. अभी भाजपा के मंगल सिंह सोय वहां के विधायक हैं. उनसे इस्तीफ़ा दिलाकर इस सीट को खाली कराया जाएगा. सोय को लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की सीट पर भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने की उम्मीद है. विधायक बनने के बाद मुंडा को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा. बहरहाल हटिया विधानसभा को कब और कैसे प्रतिनिधित्व मिलेगा, कहना कठिन है, लेकिन यह तय है कि यदि उपचुनाव की नौबत आई तो टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगी.

feedback@chauthiduniya.com

सब कुछ दांव पर लगा है

औरंगाबाद

चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध नक्सल प्रभावित औरंगाबाद ज़िले के छह विधानसभा क्षेत्रों में इस बार विधानसभा चुनाव की जंग कम रोचक नहीं है. प्रत्याशियों के साथ-साथ उनके आकाओं की साख भी दांव पर लगी है. औरंगाबाद के मतदाता भी यह स्वीकार करते हैं. नीतीश कुमार जहां विकास और सुशासन की बात कर अपने गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर निखिल कुमार देश की रफ़्तार से बिहार को जोड़ने की बात कर कांग्रेस प्रत्याशियों का हौसला बुलंद कर रहे हैं. हालांकि वह राज्यपाल जैसे पद की संवैधानिक बाध्यता के कारण चुनाव प्रचार में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रहे हैं. कांग्रेस ने सभी छह सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. औरंगाबाद विधानसभा सीट पर फ़िलहाल भाजपा के रामाधार सिंह का क़ब्ज़ा है. राजद ने यहां के सांसद सुशील कुमार सिंह के बड़े भाई एवं जदयू के बाग़ी सुनील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है. कांग्रेस ने राकेश कुमार सिंह उर्फ़ पप्पू को चुनाव मैदान में उतारा है. मज़ेदार बात यह है कि राजद प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह ने जदयू से रफीगंज के लिए टिकट की मांग की थी. जदयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वह औरंगाबाद से राजद के उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतर गए. कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कुमार उर्फ़ पप्पू को निखिल कुमार का क़रीबी माना जाता है. ऐसे में भाजपा के वर्तमान विधायक रामाधार सिंह अपने राजनीतिक समीकरण के बावजूद परेशानी में फंसे दिख रहे हैं.

अरविंद शर्मा | अशोक कुमार सिंह | माधवी सिंह | प्रमोद कुमार | सुनील कुमार

नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में लोजपा के विजय कुमार सिंह उर्फ़ डब्लू अपनी सीट बरकरार रखने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं. उन्हें चुनौती देने के लिए जदयू के वीरेंद्र कुमार सिंह एवं कांग्रेस के मृत्युंजय कुमार सिंह मज़बूती के साथ मैदान में हैं. रफीगंज विधानसभा क्षेत्र पर पिछले दो चुनावों से निहालुद्दीन का क़ब्ज़ा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने डॉ. विजय कुमार सिंह की पुत्रवधू माधवी सिंह को और जदयू ने अशोक कुमार को उतार कर निहालुद्दीन को घेरने की कोशिश की है. गोह विधानसभा क्षेत्र में जदयू के विधायक रणविजय सिंह इस बार मुश्किल में हैं. हालांकि उनके प्रति लोगों में सहानुभूति है, लेकिन राजद से उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी राम अयोध्या यादव की उम्मीदवारी और राजपूत मतदाताओं की ख़िलाफ़त ने रणविजय सिंह की डगर कांटों से भर दी है. उधर कांग्रेस के काकब कादरी के आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है. ओबरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस ने निखिल कुमार के क़रीबी और भूमिहार जाति से आने वाले अरविंद शर्मा को प्रत्याशी बनाकर राजद के विधायक सत्य नारायण सिंह की राह में रोड़े अटका दिए हैं. जदयू ने पिछले चुनाव में चौथे स्थान पर रहे प्रमोद चंद्रवंशी को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहां पर भूमिहार-राजपूत मतदाताओं की जुगलबंदी और मुस्लिमों के कांग्रेस के प्रति रुझान ने जदयू एवं राजद प्रत्याशी को मुश्किल में डाल दिया है.

नए सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा, जो पूर्व में देव विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, से राजद ने अपने पूर्व मंत्री एवं देव के विधायक रह चुके सुरेश पासवान को प्रत्याशी बनाया है. उन्हें चुनौती देने के लिए जदयू के ललन भुइयां और कांग्रेस के राजेश राम सामने हैं. औरंगाबाद के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में सफलता के लिए नीतीश कुमार ख़ुद के साथ-साथ अपने गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार चुके हैं. वहीं कांग्रेस भी सोनिया-राहुल के साथ-साथ देश एवं प्रदेशस्तरीय नेताओं को मैदान में उतार कर अपना खोया जनाधार वापस पाने के प्रयास में है. जबकि राजद-लोजपा अपने गठबंधन की तीनों सीटों को बचाने के प्रयास के साथ अन्य सीटों पर भी क़ब्ज़े के लिए लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के अलावा अन्य कई बड़े नेताओं को लगा चुका है. कुल मिलाकर इस बार प्रत्याशियों के साथ-साथ उनके आकाओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है. देखना यह है कि 20 नवंबर को इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता किस ओर करवट लेते हैं.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने भी कई क्षेत्रों में सघन प्रचार किया और फिर से एनडीए सरकार बनाने की वक़ालत की.

अब स्टार करेंगे नैया पार

चुनाव प्रचार में फिल्मी हस्तियों को बुलाना अब हर पार्टी की मजबूरी है. भीड़ बटोरने का यह नुस्खा अब सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है.पटना एयरपोर्ट का नज़ारा बिल्कुल बदल गया है. हेलीकॉप्टरों की गर्जना के साथ हर दिन बड़े नेता और फिल्मी स्टार चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं और शाम होते ही पटना वापस आ जाते हैं.

सूबे का पूरा माहौल चुनावमय है. कोई किसी का साथ दे रहा है तो कोई किसी को धोख़ा. हर शख्स तिकड़म भिड़ा रहा है. सभी पार्टियों में प्रत्याशी चयन को लेकर उठा भूचाल तक़रीबन शांत हो गया है. अब जनता को गोलबंद करने के लिए प्रचार की योजनाएं बनाई जा रही हैं. इसके लिए हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के कलाकारों को प्रचारक बनाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाई जा सके. वह ज़माना लद गया, जब सिर्फ़ पार्टी के बड़े नेता और कद्दावर लोग ही चुनाव प्रचार में छाए रहते थे. अब लोकतंत्र के रंगमंच पर कई दूसरे चेहरे पूरी मज़बूती के साथ प्रचार धर्म निभाने को आतुर हैं. आपको याद होगा कि 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव प्रचार में उतारा और उसे इसका फायदा भी मिला. पार्टी प्रत्याशी शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने काफ़ी मतों से जीत हासिल की. दरअसल भाजपा का यह फॉर्मूला लोगों को अपनी ओर खींचने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा. भाजपा के नक़्शेकदम पर चलते हुए कांग्रेस ने भी यही फॉर्मूला अपनाया. चुनाव प्रचार में फिल्मी हस्तियों को बुलाना अब हर पार्टी की मजबूरी है. भीड़ बटोरने का यह नुस्खा अब सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है.

पटना एयरपोर्ट का नज़ारा बिल्कुल बदल गया है. हेलीकॉप्टरों की गर्जना के साथ हर दिन बड़े नेता और फिल्मी स्टार चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं और शाम होते ही पटना वापस आ जाते हैं. पटना पहुंचते ही मीडियाकर्मियों का हुजूम उन्हें घेर लेता है और फिर शुरू होता है सवाल-जवाब का सिलसिला. कांग्रेस के प्रचारकों में इस बार कई बड़े नाम शामिल हैं. इनमें चंकी पांडेय, भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन एवं हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव तो बिहार आकर कई जनसभाओं को संबोधित भी कर चुके हैं. फारबिसगंज की सभा में तो बेक़ाबू जनता सुरक्षा घेरे को तोड़कर हंगामा करने लगी. किसी तरह पुलिस ने उन कलाकारों को वहां से सुरक्षित निकाला. भाजपा ने भी कई फिल्मी चेहरों को प्रचार मैदान में उतारा है. टीवी धारावाहिक सास भी कभी बहू थी से चर्चित हुईं अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने भी कई क्षेत्रों में सघन प्रचार किया और फिर से एनडीए सरकार बनाने की वक़ालत की. क्रिकेट के लिए कम और अपने बड़बोलेपन के लिए ज़्यादा मशहूर भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू भी प्रचार अभियान में जुटे हैं. उनके द्वारा दिया गया एक बयान काफ़ी विवादास्पद रहा, जिसमें उन्होंने राजद प्रमुख पर जातिसूचक टिप्पणी कर दी थी. इस पर काफ़ी हंगामा हुआ.

किशनगंज से भाजपा उम्मीदवार स्वीटी सिंह के समर्थन में प्रचार के लिए आईं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्मृति ने कहा कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है. स्मृति ईरानी को देखने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी. एक मंझे हुए राजनेता की तरह उन्होंने मीडियाकर्मियों के सवालों का भी जवाब दिया. भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कांग्रेस की तरफ़ से चुनाव प्रचार किया. उन्होंने कहा कि उन्हें छोटी पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं है. पटना में पत्रकारों के सामने उन्होंने दावा किया कि राज्य में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी.

अभी कई और बड़े चेहरों का प्रचार में कूदना बाकी है. भाजपा की ओर से हेमामलिनी का नाम है तो कांग्रेस की ओर से शाहरुख़ ख़ान को बुलाने की चर्चा हो रही है. उधर रामविलास पासवान एवं प्रकाश झा का फिल्मी कनेक्शन भी काम कर रहा है. इस तरह हर बड़ी पार्टी भीड़ खींचने के लिए इस टोटके का इस्तेमाल कर रही है. फिल्म दबंग से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली बिहारी बाबू की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को भी प्रचार में उतारने की बात चली, मगर प्रेसवार्ता में शत्रुघ्न सिन्हा से यह पूछने पर उन्होंने ख़ामोश कहकर सबको ख़ामोश कर दिया.

अनुमेहा झा
feedback@chauthiduniya.com

दिनारा

जदयू को खोई ज़मीन की तलाश

जय कुमार सिंह

शीला सिंह

सीता सुंदरी

पिछले विधानसभा चुनाव में सैकड़े के आंकड़े से जदयू प्रत्याशी रामधनी सिंह के हारने के बाद जदयू दिनारा में अपनी खोई प्रतिष्ठा दोबारा वापस पाने के लिए बेकरार है. शायद यही कारण है कि नए परिसीमन के तहत विक्रमगंज विधानसभा क्षेत्र समाप्त होने के बाद पार्टी ने दमदार उम्मीदवार जय कुमार सिंह को यहां से उतारा है. राजद की तरफ़ से सीता सुंदरी और कांग्रेस के टिकट पर रोहतास ज़िला परिषद की पूर्व अध्यक्ष शीला सिंह चुनाव लड़ रही हैं. रही बात बसपा की तो इस बार उसने बक्सर ज़िले की राजपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सतेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि यहां से लोजपा नेता अजीत राय के मैदान में उतरने की अटकलों से चुनावी जंग रोचक मोड़ लेती जा रही है. रोहतास ज़िले के उत्तरी छोर पर स्थित बक्सर लोकसभा क्षेत्र का नया अंग बना दिनारा विधानसभा क्षेत्र 1990 से लेकर 2005 तक लगातार जनता दल एवं जदयू के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले वर्तमान विधान पार्षद रामधनी सिंह के क़ब्ज़े में रहा. 2005 में जब सूबे में जदयू-भाजपा की सरकार बनी तो ऐन वक़्त पर रामधनी सिंह को यहां की जनता ने नकार दिया और नए प्रतिनिधि के रूप में बसपा नेता स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह की पत्नी सीता सुंदरी उभर कर सामने आईं. हालांकि यह सब सहानुभूति की लहर का कमाल था.

दिनारा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास तो पूर्ववत है, लेकिन भूगोल बदल चुका है. पहले दिनारा के अलावा इस क्षेत्र में कोचस एवं करगहर के हिस्से आते थे, अब पूरा सूर्यपुरा एवं दावथ प्रखंड इस विधानसभा क्षेत्र के अंग बन गए हैं. बदले परिसीमन में जदयू अपनी खोई प्रतिष्ठा पाने की कोशिश में है.

रोहतास ज़िले के उत्तरी छोर पर स्थित बक्सर लोकसभा क्षेत्र का नया अंग बना दिनारा विधानसभा क्षेत्र 1990 से लेकर 2005 तक लगातार जनता दल एवं जदयू के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले वर्तमान विधान पार्षद रामधनी सिंह के क़ब्ज़े में रहा. 2005 में जब सूबे में जदयू-भाजपा की सरकार बनी तो ऐन वक़्त पर रामधनी सिंह को यहां की जनता ने नकार दिया और नए प्रतिनिधि के रूप में बसपा नेता स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह की पत्नी सीता सुंदरी उभर कर सामने आईं.

लगभग 2 लाख 29 हज़ार मतदाताओं वाले दिनारा विधानसभा क्षेत्र में कई दिग्गज खम ठोंकने के लिए तैयार हैं. इस क्षेत्र में 1952 से लेकर 2005 के बीच हुए 13 विधानसभा चुनावों में पूर्व मंत्री रामाशीष सिंह एवं रामधनी सिंह के सबसे ज़्यादा तीन और चार बार चुनाव जीतने के रिकॉर्ड रहे हैं. इसमें एक बार चुनाव जीतने के बाद रामधनी सिंह का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था. 1952 में रामानंद उपाध्याय, 1957, 1962 एवं 1967 में रामाशीष सिंह, 1969 में रामानंद यादव, 1971 में राम नारायण साहू, 1977 में शिवपूजन सिंह, 1980 एवं 1985 में लक्ष्मण राय, 1990, 1995, 2000 एवं 2005 में पुन: रामधनी सिंह और अक्टूबर 2005 में सीता सुंदरी ने विजयश्री हासिल की. इस विधानसभा क्षेत्र में दिनारा प्रखंड के 22, दावथ प्रखंड के 9 और सूर्यपुरा प्रखंड की 5 पंचायतें आती हैं. इसके अलावा दावथ प्रखंड की कोआथ नगर पंचायत भी इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है. यहां बूथों की संख्या 251 है. राजपूत और यादव बहुल्य इस क्षेत्र में ब्राह्मण एवं कुर्मी मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे हैं. इस बार देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है.

जदयू और राजद की तरफ़ से ज़ोर-आज़माइश जारी है, लेकिन मतदाताओं की ख़ामोशी असमंजस को जन्म देती है. ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि जातीय समीकरण के अलावा कहीं लोग विकास की बात करते हैं तो कहीं उन स्थानीय मुद्दों को हवा में उछाला जा रहा है, जो अब तक हल नहीं किए जा सके. फ़िलहाल कुर्मी, कुशवाहा और ब्राह्मण मतदाताओं पर सबकी नज़रें जमीं हुई हैं, लेकिन असल परीक्षा जदयू की मानी जा रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com